लखनऊ विश्वविद्यालय

UNIVERSITY OF LUCKNOW

ACT

उतर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973

The U.P. State Universities Act, 1973

OCTOBER 2001

Price Rs. 60/-

धारा		पृष्ठ
14.	प्रति-कुलपति	 34
15.	वित्त अधिकारी	 35
16.	कुल सचिव	 36
16क.	परीक्षा नियंत्रक	 37
17.	कुलसचिवों, उपकुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों की सेवा का केन्द्रीयकरण	 38
18.	अन्य अधिकारी	 40

अध्याय 4-क

समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड

18क.	समन्वय परिषद्	 41
18ख.	केन्द्रीय बोर्ड	 41
18ग.	सचिवीय सहायता	 44

अध्याय 5

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	 45
20.	कार्य परिषद् का गठन	 45
21.	कार्य परिषद् की शक्तियाँ और कर्त्तव्य	 48
22.	सभा	 52
23.	सभा की शक्तियाँ और कर्त्तव्य	...., 54
24.	सभा का अधिवेशन	 54
25.	विद्या परिषद्	 54
26.	वित्त समिति	 56
27.	संकाय	 57
28.	प्रवेश समिति	 59
29.	परीक्षा समिति	 61
30.	अन्य प्राधिकारी	 63

धारा		पृष्ठ

अध्याय 6

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

31. अध्यापकों की नियुक्ति 64
31क. विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति 75
31ख. कतिपय तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण 76
32. विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति संविदा 77
33. पेंशन, भविष्य निधि आदि 78
34. अध्यापकों के पारिश्रमिकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा 78
35. सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालयों से भिन्न सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें 79
36. माध्यस्थम् अभिकरण 80

अध्याय 7

सम्बद्धता तथा मान्यता

37. सम्बद्ध महाविद्यालय 83
38. सहयुक्त महाविद्यालय 84
39. प्रबन्धतंत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता 86
40. सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण आदि 86
41. घटक महाविद्यालय 88
42. स्वायत्त महाविद्यालय 88
43. श्रमजीवी महाविद्यालय 88
44. संस्थान 89

अध्याय 8

प्रवेश तथा परीक्षायें

45. छात्रों का प्रवेश 90
46. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक 91
46क. महाविद्यालय को अंशदान और दान 91
47. विश्वविद्यालय के छात्रावास तथा अनिवासी छात्र केन्द्र 91
48. परीक्षायें 92

धारा		पृष्ठ

अध्याय 9

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

49. परिनियम 93
50. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे 95
51. अध्यादेश 97
52. अध्यादेश कैसे बनायें जायेंगे 98
53. विनियमन 100

अध्याय. 10

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

54. वार्षिक रिपोर्ट 103
55. लेखा तथा संपरीक्षा 103
55क. अधिभार 104

अध्याय 11

उपाधि महाविद्यालयों का विनियमन

56. परिभाषायें 105
57. सूचना जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति 105
58. प्राधिकृत नियंत्रक 107
59. सहायता न प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग वाले महाविद्यालयों को धारा 58 का लागू न होना 109
60. प्राधिकृत नियंत्रक को सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने का कर्त्तव्य 109

अध्याय 11-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

60क. परिभाषायें 111
60ख. समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियाँ किये बिना वेतन का भुगतान 112
60ग. निरीक्षण करने की शक्ति 112

धारा		पृष्ठ
60गग.	अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद	113
60घ.	कतिपय महाविद्यालयों की दशा में वेतन संदाय की प्रक्रिया	113
60ङ.	वेतन के सम्बन्ध में दायित्व	115
60च.	दण्ड आस्तियाँ तथा प्रक्रिया	116
60छ.	आदेश का अन्तिक होना	117
60ज.	नियम बनाने की शक्ति	117

अध्याय 12

शास्तियाँ तथा प्रक्रिया

61.	शास्तियाँ	118
62.	न्यायालयों का संज्ञान	119
63.	रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों द्वारा अपराध	119

अध्याय 13

प्रकीर्ण

64.	प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति	120
65.	आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति	120
66.	रिक्तियाँ आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	121
67.	विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना	121
68.	कुलाधिपति का निर्देश	121
68क.	प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध अपना आदेश प्रवृत्त करने की कुलपति की शक्ति	122
69.	वाद का वर्जन	123
70.	विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति	124

अध्याय 14

संक्रमणकालीन उपबन्ध

71.	विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिकारियों का बना रहना	125
72.	कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति	125

धारा		पृष्ठ
72क.	काशी विद्यापीठ के सम्बन्ध में अस्थाई उपबन्ध	126
72ख.	गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अस्थायी व्यवस्था	127
72ग.	मेरठ विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अस्थायी व्यवस्था	127
72घ.	अवध विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अस्थायी व्यवस्था	127
72ङ.	काशी विद्यापीठ के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अस्थायी व्यवस्था	128
72च.	आगरा और कानपुर विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अस्थायी व्यवस्था	128
72छ.	गोरखपुर तथा रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अस्थायी व्यवस्था	128
72ज.	पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन विषयक अस्थायी व्यवस्था	129
73.	कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति	129
74.	कतिपय अधिनियमितियों का निरसन	129
75.	1965 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 का संशोधन	134
76.	निरसन और व्यावृत्तियाँ	134
	अनुसूची (धारा 5 देखिए)	136

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974

अध्याय 4

अस्थायी उपबन्ध

धारा 28. कठिनाइयों को दूर करना 140

Provisions regarding conduct of Examinations 141

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973)

कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधि का संशोधन और समेकन करने के लिये अधिनियम

निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 हैं

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और वर्तमान विभिन्न विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है जिसको यह अधिनियम उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रवृत हुआ हैं

(3) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (जिसका नाम उक्त विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय होगा), को इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार[1] समय-समय पर राजपत्र अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्ध में ऐसे अपवाद या उपान्तर जो सारत: प्रभाव न डालते हों, कर सकेगी जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित है।

---

1. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा बढ़ाया गया।

(4)(क). धारा की उपधारा 2 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाने के पश्चात् काशी विद्यापीठ को इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसे अपवाद या उपान्तर जो सारत: प्रभाव न डालते हों, कर सकेगी, जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों।

[2](ख).

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(1) 'विद्या परिषद्', 'सभा' और 'कार्य परिषद्' से विश्वविद्यालय की क्रमश: विद्या परिषद्, सभा और कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(2) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के उपबन्धों तथा किसी विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो;

(3) 'विश्वविद्यालय का क्षेत्र' से विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, यथास्थिति, धारा 5 या धारा 4 द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;

(4) 'सहयुक्त महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और[3] इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय की उपाधि ग्रहण करने के निमित्त आवश्यक शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिये प्राधिकृत हो;

(5) 'स्वायत्त महाविद्यालय' से कोई ऐसा सम्बन्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है जो धारा 42 के उपबन्धों के अनुसार ऐसा घोषित किया जाय;

---

2. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा निकाला गया।

3. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

5क. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5क) पद 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य वही होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 में है;

(5ख) 'केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड' का तात्पर्य धारा 18-ख में निर्दिष्ट केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड से है;

(6) 'घटक महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा पोषित हों और परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामाँकित हो;

(6क) 'समन्वय परिषद्' का तात्पर्य धारा 18-क के अधीन गठित समन्वय परिषद् से है,

(7) 'निदेशक' से किसी संस्थान के सम्बन्ध में उस संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है,

(8) 'वर्तमान विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय (जो कि 24 सितम्बर 1995 से डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा कहा जायेगा), गोरखपुर विश्वविद्यालय (जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के प्रारम्भ की तिथि से दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर कहा जायेगा), कानपुर विश्वविद्यालय (जो कि 24 सितम्बर, 1995 से श्री शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ की तिथि से क्षत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर कहा जायेगा) या मेरठ विश्वविद्यालय (जो कि 17 जनवरी 1994 से चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय,

---

5ख. 6क., 9क. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

मेरठ कहा जायेगा) या सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां जैसा मामला या संदर्भ हो।

(9) 'संकाय' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(9क) 'आधारभूत पाठ्यक्रम' का तात्पर्य स्वयं के और अधिक बोध और सामाजिक, साँस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी के पाठ्यक्रम से हें'

(10) 'विश्वविद्यालय का छात्र निवास (या महाविद्यालय)' से छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसमें पाठन तथा अन्य अनुपूरक शिक्षण व्यवस्था हो;

(11) 'विश्वविद्यालय का छात्र' से छात्र निवास से भिन्न छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो तथा 'सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का छात्रावास' से उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई अभिप्रेत है;

(12) 'संस्थान' से धारा 44 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कोई संस्थान अभिप्रेत है;

(13) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्रबन्धतंत्र' से ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय अभिप्रेत है जिस पर उस महाविद्यालय के कार्यकलाप के प्रबन्ध का भार है जो विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो;

[4]परन्तु किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर महापालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में, पद 'प्रबन्धतंत्र' का तात्पर्य यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या महापालिका की शिक्षा समिति से है, और पद 'प्रबन्धतंत्र के अध्यक्ष' का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है;

---

4. अधिनियम संख्या 12 सन् 1978 द्वारा बढ़ाया गया।

(14) विहित से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(15) 'प्राचार्य' से किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में ऐसे महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है;

(16) 'रजिस्ट्रीकृत स्नातक' से इस अधिनियम या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत विश्वविद्यालय का कोई स्नातक अभिप्रेत है;

(17) 'परिनियम', 'अध्यादेश' और 'विनियम' से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(18) 'अध्यापक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो [5]विश्वविद्यालय या किसी घटक, सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में शिक्षण के लिए अथवा अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए नियोजित हो और इसके अन्तर्गत प्राचार्य या निदेशक भी हैं;

(19) 'विश्वविद्यालय का अध्यापक' से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय में या उसके द्वारा पोषित किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय में शिक्षण अथवा अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित हो;

(20) 'विश्वविद्यालय' से कोई विद्यमान विश्वविद्यालय या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् धारा 4 के अधीन स्थापित कोई नया विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(21) 'श्रमजीवी-महाविद्यालय' से धारा 43 के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में मान्यता प्राप्त सम्बद्ध या संयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है।

---

5. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन

3. (1) किसी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति से तथा कार्य परिषद्, सभा और विद्या परिषद् के सदस्यों के रूप में तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्तियों से मिलकर एक निगमित निकाय उस विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा।

(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा अपने नाम से वह वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।

नए विश्व-विद्यालयों की स्थापना और विश्व-विद्यालयों के क्षेत्रों अथवा नामों में परिवर्तन

4. (1) नये विश्वविद्यालयों की स्थापना और विश्वविद्यालयों के नाम या क्षेत्र का परिवर्तन - 1. राज्य सरकार द्वारा गज़ट में जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से उसके अधीन नैनीताल में कुमायूँ विश्वविद्यालय एवं श्रीनगर जिला गढ़वाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय (जोकि 25 अप्रैल, 1989 से हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कहा जायेगा) की स्थापना की जायेगी। अधिसूचना में इनका क्षेत्र क्रमशः उल्लिखित है।

(1-क[5a]) ऐसी तारीखों से जिसे या जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे निमित्त नियत करे :-

(क) झाँसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय :

(ख) अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद को 18 जून 1994 से डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद तथा 11 जुलाई 1995 से डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद कहा जायेगा।

(ग) रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,

---

5a. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

1997 के प्रारम्भ की तिथि से महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली कहा जायेगा।

(घ) पूर्वाचल विश्वविद्यालय जौनपुर को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1999 के प्रारम्भ की तिथि से वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय जौनपुर के नाम से जाना जायेगा। अधिसूचना में इनका क्षेत्र क्रमशः उल्लिखित है।

(1-ख) उपधारा (1-क) के आधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, -

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के (कुलाधिपति से भिन्न) अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे विश्वविद्यालय के लिये ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी:

(ख) [6]खण्ड (क) के आधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य 31 दिसम्बर, 1981[6a] तक या खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे;

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ा सकती है।

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के आधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

---

6. अधिनियम संख्या 12 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित।

6a. अधिनियम संख्या 15 सन् 1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2)वाराणसी में काशी विद्यापीठ नामक संस्था को जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 के प्रारम्भ होने के दिनाँक से महात्मा गा।धी काशी विद्यापीठ कहा जायेगा। इस अधिनियम के उपबन्धों के आधीन स्थापित विश्वविद्यालय उस तारीख से समझा जायेगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे निमित्त नियत करें।

(3) उपधारा (2) के आधीन नियत तारीख से -

(i) काशी विद्यापीठ, वाराणसी नामक सोसाइटी विघटित हो जायेगी और सोसाइटी की सभी जंगम और स्थावर सम्पत्ति और अधिकार, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगे, और उनका प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जिनके लिये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

(ii) उक्त सोसाइटी के सभी ऋण, दायित्व तथा बाध्यताएं विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगे और तत्पश्चात् उसके द्वारा उन्मोचित तथा तुष्टि किये जायेंगे;

(iii) किसी अधिनियमित से उक्त सोसाइटी के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा, मानो वे विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हो;

(iv) किसी बिल, विलेख या अन्य दस्तावेज का चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् तैयार निष्पादित किया गया हो और जिसमें उक्त सोसाइटी के पक्ष में कोई वसीयत-दान या न्यास हो, ऐसा अर्थ लगाया जायेगा, मानो उसमें ऐसी सोसाइटी के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम हो;

(v) इस अधिनियम के उपबन्धों के आधीन रहते हुये उक्त तारीख के ठीक पूर्व उक्त सोसाइटी में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उक्त तारीख से उसी अवधि के लिये और सेवा की उन्हीं शर्तों अथवा तत्सदृश शर्तों पर,

जो परिवर्तित परिस्थितियों में अनुज्ञेय हों, विश्वविद्यालय का उसी प्रकार कर्मचारी हो जायेगा, जिस प्रकार वह ऐसी अधिसूचना जारी न किये जाने पर उक्त सोसाइटी के अन्तर्गत होता।

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा :-

(क) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र बढ़ा सकेगी :

(ख) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र कम कर सकेगी, या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सकेगी:

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना, सिवाय राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदित संकल्प के बिना जारी नहीं की जायेगी।

(5) इस धारा के आधीन अधिसूचना में अनुसूची और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों, के परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमनों का संशोधन करने के लिये ऐसे उपबन्ध हो सकेंगे जो अधिसूचना के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों और तत्पश्चात् अनुसूची तथा परिनियम, अध्यादेश और विनियम तदनुसार संशोधित हो जायेंगें

(6) उपधारा (5) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के आधीन किसी अधिसूचना में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्-

(क) उक्त अधिसूचना से प्रभावित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में विभिन्न हितों अथवा वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित उपबन्ध;

(ख) तत्समय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातक बने रहने अथवा किसी नए स्थापित विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराने के विकल्प का

प्रयोग करने के लिये उपबन्ध, किन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रीकृत स्नातक नहीं होगा;

(ग) ऐसे अन्य अनुपूरक आनुषँगिक तथा पारिणामिक उपबन्ध जिसे राज्य सरकार आवश्यक समाझें

1860 का 21 **स्पष्टीकरण**–इस धारा और धारा 5 के प्रयोजनों के लिये "काशी विद्यापीठ" से वाराणसी में काशी विद्यापीठ नामक संस्था अभिप्रेत है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के आधीन रजिस्ट्रीकृत काशी विद्यापीठ नामक सोसाइटी द्वारा स्थापित और प्रशासित है, जिसके सम्बन्ध में उक्त सोसाइटी की निरीक्षक सभा ने 28 मई, 1972 को यह अनुरोध करते हुए एक संकल्प पारित किया था कि राज्य सरकार उक्त संस्था की सम्पूर्ण जंगम और स्थावर सम्पत्तियों को ग्रहण कर ले और उसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दे।

शक्तियों का राज्य क्षेत्र में प्रयोग

5. (1) इस अधिनियम द्वारा या इसके आधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालाय तथा काशी विद्यापीठ से भिन्न) प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अनुसूची में उसके सामने तत्समय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया जा सकेगा।

(2) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा तथा वहाँ के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिये अनुमति दे सकेगा।:

परन्तु विश्वविद्यालय सम्बद्ध सरकार की सिफारिश के बिना :–

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान में नियोजित किसी अध्यापक को मान्यता नहीं प्रदान करेगा।

(3) महाविद्यालयों की सम्बद्धता अथवा मान्यता से सम्बद्ध इस अधिनियम की कोई बात काशी विद्यापीठ पर लागू न होगी।

(4) उप अनुभाग (1) में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति में शोध तथा संस्था के संदर्भ में, साथ ही ज्ञान के प्रचार-प्रसार और विकास की दृष्टि से क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को जो अधिकार प्रदान किये गये हैं वे सारे उ0 प्र0 के विश्वविद्यालयों में प्रयोग के योग्य माने जायेंगे।

[7](5) उप अनुभाग (1) में निहित तथ्यों के बावजूद (1) सम्पूर्ण उ0 प्र0 में होम्योपैथिक शिक्षा संबंधी या निर्देशात्मक संस्थाएं, डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय आगरा या क्षत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध हो सकती हैं।

(6) अनुभाग 37 के उप अनुभाग (1) में निहित तथ्यों के बावजूद उ0 प्र0 में कहीं भी इन्जीनियरिंग प्रौद्योगिकी या प्रबंधन तथा भारतीय चिकित्सा संबंधी प्रमाणपत्र अधिनियम 1916 में दी गई परिभाषा के अनुसार पाश्चमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा या निर्देशा प्रदान करने के लिए स्थापित संस्थाएं या स्थापना के लिए प्रस्तावित संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश या निर्देश के अन्तर्गत आयेंगी और किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो सकती है।

6. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा, भले ही ये किसी वर्ग या मत के हों, किन्त इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में अध्यादेशा द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है : विश्व सभी और मतावलम्बियों के लिये होगा

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों[7अ]

7. अधिनियम संख्या 14 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

7अ. उ. प्र. अध्यादेश सं. 12 सन् 1994 द्वारा जोड़ा गया।

या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लि विशेष उपबन्ध बनाना मना हें

विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कर्तव्य

7. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्‍ होंगे, अर्थात् :-

(1) ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना जिन्‍ विश्वविद्यालय ठीक समझे, तथा अनुसंधान-कार्य और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(2) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता क विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से हैं यथास्थिति, सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना अथवा उसमें कमी करना और सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों का मार्ग-दर्शन करना तथा उनके कार्य का नियंत्रण करना;

(3) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विश्शिष्टताओं को संस्थित करना :

(4) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों, डिप्लोमाओं पर अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं सम्प्रदान करना :-

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में अथवा किसी सहयुक्त कालेज में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में, या विश्वविद्यालाय रा निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप

से, परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के आधीन अनुसंधान कार्य किया हो; या

(ग) जिन्होंने पत्राचार द्वारा, चाहे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में या उससे बाहर निवास करके, किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, और जो ऐसी शर्तों के आधीन रहते हुये जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित की जाये, वाहक अभ्यर्थियों के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत किये गये हों; या

(घ) जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के आधीन विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या किसी घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में या अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक या अन्य कर्मचारी हों अथवा राज्य सरकार के शिक्षण विभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण अधिकारी हों, और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के आधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो; या:

(ङ) जो विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास करने वाली महिलायें हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के आधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो; या

(च) जो नेत्रहीन हों और विश्वविद्यालय क्षेत्र में निवास करते हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के आधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो;

(5) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिये जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के आधीन निजी रूप से अध्ययन किये हों, परीक्षायें लेना और उन्हें बेचलर

आफ आर्ट्स या कामर्स अथवा मास्टर आफ आर्टस या कामर्स की उपाधि प्रदान करना;

(6) परिनियमों में अधिकथित रीति तथा शर्तों के आधीन सम्मानित उपाधियाँ अथवा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टतायें प्रदान करना;

(7) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों ऐसे डिप्लोमा देना और उनके लिये ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(8) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना जिन्हे विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(9) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन-पदों को संस्थित करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(10) छात्र निवास में शिक्षण देने के लिये अध्यापकों को मान्यता देना;

(11) महाविद्यालयों की सम्बद्धता या मान्यता सम्बन्धी शर्तें अधिकथित करना और समय-समय पर निरीक्षणों द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही है;

(12) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृतियों, अधिछात्रवृत्तियों (जिसके अन्तर्गत यात्रिक अधिछात्रवृत्तियाँ भी है), विद्यावृत्तियों तथा पारितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(13) छात्र निवासों तथा छात्रावासों को संस्थित तथा पोषित करना और विश्वविद्यालय संस्थानों या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के लिये निवास स्थानों को मान्यता देना;

(14) ऐसी फीस और अन्य प्रभार माँगना तथा प्राप्त करना जो अध्यादेश द्वारा नियत किये जाएं;

(15) विश्वविद्यालय, संस्थान तथा घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिये व्यवस्था करना;

(16) प्रशासकीय, लिपिक-वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना; तथा

(17) विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित ऐसे सभी कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों।

कुछ विश्वविद्यालय की अतिरिक्त शक्तियां और कर्तव्य

7-क[8]. उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक दवा अधिनियम 1951 के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार से अधिकृत किये जाने पर डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय आगरा या क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर जहां जैसा मामला या संदर्भ हो।

(क) होम्योपैथिक में परीक्षाएँ लेगा और डिप्लोमा प्रदान करेगा;

(ख) उक्त अधिनियम के आधीन गठित होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिये परीक्षा लेने और डिप्लोमा प्रदान करने का कार्य करेगा और उक्त परीक्षाओं को लेने और डिप्लोमा प्रदान करने के निर्देश उक्त अधिनियम के आधीन गठित ऐसे बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

अधिनियम संख्या 14 सन 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय 3

निरीक्षण तथा जाँच

परिदर्शन

8. (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी घटक महाविद्यालय अथवा किसी संस्थान का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर भी है और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा संचालित या कराई गई परीक्षा, अध्यापन-कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के आधीन कोई निरीक्षण या जाँच कराने का निश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी, और ऐसे निरीक्षण या जाँच में परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा :

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के आधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्ति व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के

प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को [9]दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी, और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्य परिषद् को संसूचित करेगा।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे उसे परिषद् द्वारा की गयी या की जाने के लिये प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के आधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जाँच की और उपधारा (5) के आधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के आधीन जारी किये गये प्रत्येक निर्देश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियाँ भी भेजेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कुलाधिपति की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी किसी जाँच की कोई रिपोर्ट भी

9. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

है, विचार करने के पश्चात् यह राय हो कि कार्य परिष्द् अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगा कि उक्त कार्य परिषद् को अतिष्ठित करते हुये कुलाधिपति तथा उस अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करे जिसके अन्तर्गत अतिष्ठित कार्य परिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये और उपधारा 11 के उपबन्धों के आधीन रहते हुये जिसे कुलाधिपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के आधीन कार्य परिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी।

(9) उपधारा (8) के आधीन गठित तदर्थ कार्य परिषद् की संरचना पर धारा 20 की कोई बात लागू न होगी।

(10) उपधारा 8 के आधीन आदेश दिये जाने परर, उससे अतिष्ठित कार्य परिषद् के सभी सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं, पदावधि समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

(11) उपधारा (8) के आधीन किसी आदेश के प्रवर्तन के अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित उपान्तरों के आधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 20 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित समझी जायेगी :-

"(6) कार्य परिषद् का अधिवेशन प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार होगा।" :

(ख) धारा 21 की उपधारा (1) में, "इस अधिनियम के उपबन्धों के आधीन रहते हुये, "शब्दों के पश्चात्", तथा कुलाधिपति के भी नियंत्रणाधीन रहते हुये" शब्द अन्त:स्थापित समझे जायेंगे :

(ग) धारा 24 की उपधारा (2) में, ''और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर'' शब्दों का लोप कर दिया जायेगा।

(12) उपधारा (8) के आधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार एक नई कार्य परिषद् गठित की जायेगी।

(13) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वे उपधारा (11) के उपबन्धों के कारण उपान्तरित समझे जायेंगे, उपधारा (8) के आधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई परिनियम, अध्यादेश, विनिमय या किया गया आदेश, ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर भी, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संशोधित, निरसित या विखण्डित न कर दिया जाये।

अध्याय 4
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

(क) कुलाधिपति :

(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की दशा में, प्रति कुलाधिपति :

(ग) कुलपति :

(घ) धारा 14 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की दशा में, प्रति-कुलपति :

(ङ) वित्त अधिकारी :

(च) कुल सचिव :

[9a](चच) परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो

(छ) संकायों का संकायाध्यक्ष :

(ज) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष :

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

10. (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान तथा सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(2) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति माँगे, प्रस्तुत करे।

9a. उ. प्र. अध्यादेश सं. 7 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके आधीन प्रदान की जायें।

11. (1) वाराणसी के महाराजा विभूति नारायण सिंह सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति-कुलाधिपति आजीवन बने रहेंगे। **प्रति कुलाधिपति**

(2) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, प्रति-कुलाधिपति सभा के अधिवेशनों का तथा विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति-कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके आधीन प्रदान की जायें।

12. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उपधारा (5) या उपधारा (10) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों। **कुलपति**

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) [10]कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, संस्थान घटक महाविद्यालय, सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा, छात्रनिवास या छात्रावास से सम्बन्धित व्यक्ति न हों) जिसका निर्वाचन कार्य परिषद् द्वारा किया जाना है;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का

---

10. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

न्यायाधिपति है या रहा हो, जिसके अन्तर्गता उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है; औार

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा :

[10a]परन्तु जहाँ कार्य परिषद् खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहाँ कुलाधिपति खण्ड (ग) के आधीन अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्य परिषद् के प्रतिनिधि के बदले में नाम-निर्दिष्ट करेंगे।

(3) उपधारा (7) के आधीन पदावधि समाप्ति अथवा पद त्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाधिपति को कम्म से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित न करेगी।

(4) जहाँ कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्त के लिये उपलब्ध न हों और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नए नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम

10a. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

का सुझाव देने में असफल या असमर्थ हैं [10b]या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेगा जो धारा (3) के अनुसारण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियाँ थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के आधीन रहते हुये, कुलपति की उपलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करें।

(9) कुलपति धारा (33) के आधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा :

[11]परन्तु जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा जिस

10b. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

11. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा बढ़ाया गया।

सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा हो।

(10) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होगा) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिये जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा -

(क) जहाँ कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी;

(ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात् में :

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रति-कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ प्रति कुलपति न हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा धारा 38 में उल्लिखित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय की दशा में, विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य, या किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय का ज्येष्ठतम प्राचार्य कुलपति के कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

[11a.] (12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

[11a.] (13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी **जाँच** को अनुध्यात करते हुये, कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये, -

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था:

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।''

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य

13. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और :-

(क) विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय तथा संस्थान भी हैं और उससे सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दीक्षाँत समारोह का सभापतित्व करेगा;

11a. उ. प्र. अध्यादेश संख्या 12 सन् 1994 द्वारा बढ़ाया गया।

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ङ) [12]विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) वह कार्य परिषद्, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और [13]धारा 10 तथा 68 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हो।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, सभा, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति के अधिवेशन के बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी:

परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

---

12. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।
13. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) जहाँ विश्वविद्यालय[14] के (अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न) कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम के मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते:

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु वह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपाँतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके आधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु वह और भी कि विश्वविद्यालय को सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस तारीख से ज[illegible] उसे ऐसे कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने

---

14. अधिनियम संख्या सन् 1992 दिनांक 3-3-1992 (22-11-1991 से)

का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उ उलट सकेगी।

(7) उपधारा (6) में की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिये सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(8) जहाँ कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई हो, तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से नियुक्ति दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें

प्रति कुलपति

*14.(1) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों को और किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों को लागू होती है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालयों के आचार्यों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रति-कुलपति अपने कर्त्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(4) प्रति-कुलपति कुलपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(5) प्रति-कुलपति, को तीन सौ रुपये प्रति मास मानदेय मिलेगा।

---

*अन्य विश्वविद्यालयों के लिये संलग्नक A देखें।

(6) प्रति-कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति को सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालयों के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति उसे सोंपे तथा प्रत्यायोजित करे।

वित्त अधिकारी

15. (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में वित्त अधिकारी अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी तथा उसके पारिश्रमिक तथा भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी, सभा के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे कार्य परिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे।

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए।

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो परिनियमों तथा अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो,

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करना,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालयों की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ तथा कृत्य वे होंगे जो विहित किए जायें।

कुल सचिव

16. (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कुलसचिव की नियुक्ति की जायेगी और उसकी सेवा की शर्तें उनके अधीन होंगी।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद्, सभा, विद्या परिषद् और प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा तथा वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगी जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो

किन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर, मत देने का हकदार न होगा।

[14क](5) निकाल दी गयी।

(6) कुलसचिव की धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबंधित के सिवाए, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

परीक्षा नियंत्रक

[14ख]**16-क.** (1) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, और कानपुर विश्वविद्यालयों को और किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों को लागू होती है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा। जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय का संस्थान से ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की या ऐसी

14क. उ. प्र. अध्यादेश सं0 7 सन् 1995 द्वारा निकाल दी गई।

14ख. उ. प्र. अध्यादेश सं0 7 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(5) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(6) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्ष नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी-काम के लिए को: पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न वह स्वीकार करेगा।

(8) यदि कभी परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्त्तव्यों का पालन यथास्थिति परीक्ष नियंत्रक के पुन: कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तव ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायगा जिसे कुलपति द्वार नियुक्त किया जाय।

कुलसचिवों, उप-कुलसचिवों तथा सहायक कुल सचिवों की सेवा का केन्द्रीयकरण

17. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बनाकर कुलसचिवों, उप-कुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवं की एक ऐसी पृथक सेवा के सृजन का उपबन्ध करेगी जो समस्त विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य होगी तथा ऐसी किसी सेवा ं भर्ती को तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों क विनियमित करेगी :

[15]परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई नियम पूर्वगामी तारीख से, जो 31 अक्टूबर, 1975 से पूर्व न हो, बनाय जा सकता है।

15. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) जब ऐसी कोई सेवा सृजित की जाये, तो [15अ]कुलसचिव, उप-कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव के प्रशासनिक पदों पर तत्समय सेवारत सभी व्यक्ति जो यदि तारीख 14 मई, 1973 से पूर्व स्थायी किये जा चुके हों तो उक्त सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित कर लिए जायेंगे तथा उक्त पदों पर तत्समय सेवा करने वाले अन्य व्यक्ति यदि उपयुक्त पाए जायें, तो उक्त सेवा में अस्थायी या अन्तिम रूप से आमेलित किये जा सकेंगे और यदि पश्चात्वर्ती व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अन्तिम रूप से उक्त सेवा में आमेलित नहीं किया जाता तो उसकी सेवायें एक मास का वेतन प्रतिकर के रूप में संदत्त किये जाने पर समाप्त समझी जायेंगी।

(3) जहाँ उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को सेवा में आमेलित किया जाए तो उसे लागू होने वाली सेवा की शर्तें, उसके आमेलित किये जाने के पूर्व उस पर लागू शर्तों से, सिवाय इसके कि उसका एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकेगा, कम लाभकारी न होगी:

[16]परन्तु सेवा में इस प्रकार के आमेलन से ऐसे आमेलन की तारीख के पूर्व किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने या जारी रखने के लिए कोई रोक नहीं होगी।

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कम से कम तीन दिन की कुल कालावधि के लिए जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाये, राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे उपान्तरों या निष्प्रभावीकरणों

15अ. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

16. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिए सहमत हो जायें किन्तु ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

अन्य अधिकारी

18. कुलाधिपति, प्रति-कुलाधिपति, कुलपति, प्रति-कुलपति वित्त अधिकारी, कुलसचिव और [16क]परीक्षा नियंत्रक यदि कोई नियुक्त हो, से भिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की वही शक्तियाँ होंगी जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें।

16क. उ. प्र. अध्यादेश सं. 7 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

[17]अध्याय 4-क

समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड

18-क. (1) एक समन्वय परिषद् होगी जिसका अध्यक्ष कुलाधिपति होगा और उसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :- समन्वय परिषद्

(एक) समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति;

(दो) उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष;

(तीन) राज्य सरकार के न्याय विभाग का सचिव;

(चार) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव;

(पाँच) राज्यपाल का सचिव;

(छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव जो समन्वय परिषद् का पदेन सचिव होगा।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों या उसके द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुये समन्वय परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) स्नातक उपाधि के लिये अध्यापक के सामान्य पाठ्यक्रम की सिफारिश करना;

(ख) आधारभूत पाठ्यक्रम के लिये या प्रत्येक विषय या विषयों के समूहों के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन के संबंध में सिफारिश करना;

(ग) विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग के उपायों और साधनों की सिफारिश करना;

(घ) विश्वविद्यालयों के सामान्य हित के विषयों पर विचार करना और सिफारिश करना;

(3) समन्वय परिषद् की बैठक लखनऊ में या ऐसे अन्य स्थान पर और ऐसे अन्तराल पर जैसा कुलाधिपति विनिश्चय करें, होगी।

18(ख). (1) आधारभूत पाठ्यक्रम या ऐसे अन्य विषयों या विषयों के समूह के लिये, जिन्हें कुलाधिपति समन्वय परिषद् केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड

17. उ. प्र. अध्यादेश सं. 28 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

की सिफारिश पर अधिसूचित करे, केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) आधारभूत पाठ्यक्रम के केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :

(एक) प्रत्येक विश्वविद्यालय के उपाचार्य के अनिम्न पद का एक अध्यापक या संबद्ध या सहयुक्त विद्यालय का प्राचार्य, जिसे कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, और

(दो) पाँच शिक्षाविद को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिष्ठित आचार्यों की सूची में हों, जिन्हें समन्वय समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) अन्य विषयों या विषयों के समूह के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :

(एक) विषय या विषयों के समूह के संबंध में, जिनके लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड का गठन किया जाना है, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड का संयोजक:

परन्तु यह कि यदि किसी विश्वविद्यालय में विषय या विषयों के समूह में अध्ययन बोर्ड न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय में उपाचार्य के स्तर से अनिम्न किसी अध्यापक या किसी संबद्ध या सहयुक्त विद्यालय के प्राचार्य को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है;

(दो) किसी संबद्ध या सहयुक्त विद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर तक विषय का अध्यापन करने वाला एक विभागाध्यक्ष जिसे कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(तीन) किसी संबद्ध या सहयुक्त विद्यालय में स्नातक स्तर तक विषय का अध्यापन करने वाला एक विभागाध्यक्ष जिसे कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(चार) विषय के तीन विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिष्ठित अध्यापकों की सूची में हों,

जिन्हें समन्वय समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा; और

(पाँच) राज्य के बाहर से विषय के दो अन्य विशेषज्ञ जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(4) कुलाधिपति केन्द्रीय अध्ययन मंडल के अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे -

(i) आधार पाठ्यक्रम के लिए उप अनुभाग 2 की धारा 1 में दिये सदस्यों के नाम से तथा

(ii) अन्य विषय या विषयों के समूह के लिए उप-अनुभाग 3 की धारा (i) और (ii) में दिये गये नामों में से -

(5) केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन और पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों के नाम-निर्देशन को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायगा।

(6) केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अवधि उपधारा (5) में निर्दिष्ट अधिसूचना के दिनाँक से तीन वर्ष होगी और सदस्यों की पदावधि केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अवधि के साथ समाप्त होगी।

परन्तु यह कि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके पूर्ववर्ती की शेष पदावधि तक के लिये ही होगी।

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों या उसके द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुये, केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् -

(क) समन्वय परिषद् की सिफारिशों और कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन अध्ययन और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों और शैक्षिक कैलेण्डर निर्धारित करना और स्नातक पूर्व स्तर के लिये पाठ्य पुस्तकों और अन्य, पुस्तकों की सिफारिश करना,

(ख) समन्वय परिषद् या कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय पर विचार करना और रिपोर्ट देना, और

(ग) इस अधिनियम के संगत ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन ऐसे समय के भीतर करना जो कुलाधिपति के लिखित आदेश द्वारा सम्पादन करने की अपेक्षा की जाय।

(8) अपने कृत्यों का अनुपालन करने में केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड ऐसे विशेषज्ञों से भी परामर्श कर सकता है जो उसके सदस्य नहीं है।

(9) कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की सिफारिशें राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उस दिनाँक से प्रवृत्त होंगी जो कुलाधिपति द्वारा अधिसूचित किया जायें।

(10) कुलाधिपति किसी भी समय केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के किसी विनिश्चय को इस आधार पर निलम्बित, उपान्तरित या संशोधित कर सकता है कि यह इस धारा में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है और विषय पर नये सिरे से विचार करने के लिये बोर्ड को निर्देश दे सकता है।

सचिवीय सहायता

18-ग. उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 1995 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड को सचिवीय सहायता देंगी।

अध्याय 5

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

(क) कार्य परिषद्,

(ख) सभा,

(ग) विद्या परिषद्

(घ) वित्त समिति,

(ङ) संकायों के बोर्ड,

(च) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियाँ,

(छ) प्रवेश समिति,

(ज) परीक्षा समिति, और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किए जायें।

कार्य परिषद् का गठन

20. (1) कार्य परिषद् के सदस्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो,

(ग) दो संकायों के संकायाध्यक्ष, विहित रीति में चक्रानुक्रम से,

(घ) [17अ]कुमांयू विश्वविद्यालय, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय आगरा, क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद तथा महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के संदर्भ में -

---

17अ. अधिनियम संख्या 20 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

(i) विश्वविद्यालय का प्रति-कुलपति का उपयुक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिसका विहित रीति से चयन किया जायगा,

(ii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा,

और धारा 37 की उपधारा (1) में उल्लिखित या उसके अधीन अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्थिति में सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य और चार अन्य अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा,

(ङ) धारा 38 की उपधारा (1) में उल्लिखित या तद्धीन अधिसूचित किसी विश्वविद्यालय की दिशा में -

(i) विश्वविद्यालय के दो आचार्य [प्रति-कुलपति अथवा उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकाय से भिन्न], दो उपाचार्य, दो प्राध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है;

(ii) किसी सहयुक्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य जिसका विहित रीति से चयन किया जाना है?

(च) सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने गये चार व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अथवा छात्र निवास हाल या छात्रावास में छात्र के रूप में नामावलिगत न हो या की सेवा में न हों,

(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति।

[18](परन्तु इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हों)

[18b](ज) ख्याति प्राप्त उद्योगपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जिसने उच्च शिक्षा में मूल्यवान योगदान किया हो।;

[18a](2) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष और उसके खण्ड (च) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष और (छ) या (ज) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(3) कोई भी व्यक्ति, उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) के अधीन, कार्य परिषद् का लगातार दो से अधिक पदावधि के लिए सदस्य न होगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में तब तक निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(5) कोई व्यक्ति कार्य परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है :

---

18. उ. प्र. अध्यादेश सं. 3 सन् 1988 द्वारा बढ़ाया गया।

18a. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित तथा उ. प्र. अध्यादेश सं. 7 सन् 1995 द्वारा संशोधित।

18b. उ. प्र. अध्यादेश सं. 14 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप से किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण-इस धारा में, ''नातेदार'' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भतीजा और भतीजी भी है।

कार्य परिषद् की शक्तियां एवं कर्तव्य

21. (1)कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्य निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्-

(i) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना,

(ii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना,

(iii) परिनियमों तथा अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना,

(iv) विशिष्ट परियोजनों के लिए विश्वविद्यालयों के व्ययनाधिकार से रखी गई किसी निधि का प्रशासन करना,

(v) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना

(vi) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधि-छात्रवृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना,

(vii) विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना,

(viii) [19]परीक्षकों की फीस, उपलब्धियाँ तथा यात्रा तथा अन्य भते नियत करना,

(ix) [20]धारा 37 उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से ही सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना,

(x) संस्थानों, सम्बद्ध, सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों, छात्र निवास, छात्रावासों तथा छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना,

(xi) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आधार पर तथा प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना,

(xii) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग तथा अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित तथा प्रवर्तित करना,

(xiii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति कारोबार तथा अन्य सभी प्रशासकीय कार्य-कलापों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे,

---

19. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा निकाला गया।

20. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

(xiv) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास तथा विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों शेयरों या प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, अथवा भारत में स्थावर सम्पत्ति तय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना,

(xv) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचरों तथा साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना,

(xvi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और निरस्त करना,

(xvii) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय तथा घटक, सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद्, बन्धक, विक्रय विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय का किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूरी मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन उपेक्षित हो, और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय [21]अथवा

21. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा बढ़ाया गया।

राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जायगा।

[22](3-क) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियाँ अर्जित कर सके और भविष्य निधि में अंशदान कर सके और सेवा निवृत्ति के लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके :

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

(4) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाये।

(5) कार्य परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद् और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद्, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

22. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा बढ़ाया गया।

(7) कार्य परिषद् सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे और सभा को यथास्थिति की गई कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(8) कार्य परिषद् परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकेगी।

सभा

22. (1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

वर्ग–1 पदेन सदस्य

(i) कुलाधिपति,

(ii) कार्य परिषद् के सदस्य,

(iii) वित्त अधिकारी,

वर्ग–2 आजीवन सदस्य

(iv) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सभा या नियामक सभा (सीनेट) का आजीवन सदस्य थाँ

वर्ग–3 अध्यापकों आदि के प्रतिनिधि

(v) विश्वविद्यालय तथा उनके द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष,

(vi) मेडिकल तथा इंजीनियरिंग संकायों के संकायाध्यक्ष यदि वे कार्य परिषद् के सदस्य न हों,

(vii) विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों तथा संस्थानों के छात्रावासों और छात्र निवास के प्रोवोस्टों तथा वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जाना है,

(viii) राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय के सभी प्राचार्य,

(ix) पन्द्रह अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है,

(x) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्ध के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जाना है,

वर्ग–4 रजिस्ट्रीकृत स्नातक

(xi) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के पन्द्रह प्रतिनिधि जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा, जो विहित की जाये ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से निर्वाचित किये जायेंगे जो विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय की सेवा में न हो अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, छात्र-निवास या . छात्रावास की सेवा में अथवा उसके प्रबन्ध से सम्बद्ध न हों,

वर्ग–5 छात्रों का प्रतिनिधित्व

(xii) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में, विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती उपाधि परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में (जिसके अन्तर्गत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय भी है) किसी स्नातकोत्तर उपाधियाँ विधि अथवा मेडिकल या इंजीनियरिंग उपाधि के शिक्षा पाठ्य-क्रम का अध्ययन कर रहा हो,

वर्ग–6[23]

ार्ग–7 राज्य विधान मंडल के प्रतिनिधि

(xiii) विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य,

(xiv) विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके पाँच सदस्य।

अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा निकाला गया।

(2) उपधारा (1) में वर्णित सिवाय वर्ग 1, 2 और 5 के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त वर्ग 5 के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

सभा की शक्तियां तथा कर्त्तव्य

23. सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपायों का सुझाव देना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) कुलाधिपति की किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किए जाएं, सलाह देना और

(घ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जायें।

सभा का अधिवेशन

24. (1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा जो कुलपति द्वारा नियत की जाती है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलाएगा।

(2) कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा, और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलाएगा।

विद्या परिषद्

25. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए :

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) कुलपति,

(ii) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो।

(iii) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो तो सम्बद्ध संकाय में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों से ज्येष्ठतम अध्यापक,

(iv) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हो,

(v) घटक महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा संस्थानों के निदेशक, यदि कोई हो,

(vi) प्रत्येक घटक महाविद्यालय से (यदि कोई हो) चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता-क्रम में जो विहित रीति में अवधारित की जाएगी, दो आचार्य,

(vii) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जिनका विहित रीति में चक्रानुक्रम से, चयन किया जाएगा,

(viii) पन्द्रह अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है,

(ix) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष,

(x) विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष, और

(xi) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पाँच व्यक्ति जो विहित रीति से सहयोजित किये जायेंगे।

(3) धारा 65[24] के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्यों भिन्न सदस्यों की पदावधि वही होगी जो विहित की जाए।

वित्त समिति

26. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति,

(कक) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव

(ककक) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हों,

(ग) कुलसचिव,

(गग) परीक्षा नियंत्रक

(घ) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का सदस्य या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय में सेवा करने वाला व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो, और

(ङ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा।

[25](1-क) उपधारा (1) के खण्ड (कक) या खण्ड (ककक) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक

---

24. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

(कक),(ककक), उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं. 7 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

25. उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं. 7 सन् 1995 द्वारा बढ़ाया गया।

में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(2) वित्त समिति, कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। यह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कुल आवर्त तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्ध कर होगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जायं।

[26](4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जायं, कार्य परिषद् इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेंगी और यदि कार्य परिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद् पुन: वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

27.(1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जो विहित किये जायं। **संकाय**

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जो विहित किये जाएं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा सोंपे जाएं।

---

26. अध्यादेश सं0 4 सन् 1996 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियाँ और कर्त्तव्य वही होंगे जो विहित किये जाएं।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता-क्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

[27]परन्तु किसी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय की दशा में ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, यथास्थिति मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा :

परन्तु यह और कि यदि एक से अधिक ऐसा महाविद्यालय हो, तो प्रत्येक ऐसे संकाय के संकायाध्यक्ष का पद ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्यों के बीच विहित रीति से चक्रानुक्रमित होगा :

[28]परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के उपचार्यों द्वारा, और यदि कोई उपाचार्य नहीं है तो अन्य अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठता-क्रम के अनुसार बारी-बारी से धारण किया जायगा।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह :-

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन, तथा

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिये उत्तरदायी होगा।

---

27. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

28. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6)[29]विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायगी:

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण किये रहेगा जिन पर उक्त तारीख के ठीक पूर्व धारण किये हों।

(7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जाएं।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सोंपे जा सकेंगें

प्रवेश समिति

28. (1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में होगा।

(2) प्रवेश समिति को उतनी उप-समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह ठीक समझे।

(3) विद्या परिषद् के अधीक्षणाधीन तथा उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान या घटक विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश प्राधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उप-समिति को भी नाम-निर्दिष्ट कर सकेगी।

---

29. अधिनियम संख्या 21 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों में और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए मापदण्ड या रीति [30](जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) के सम्बन्ध में कोई निदेश दे सकेगी और ऐसे निदेश ऐसे महाविद्यालयों पर आबद्धकर होंगे।

[31](5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, -

(क) किसी विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये प्रवेश के लिये ऐसे आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उसे निमित्त बनाये :

परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षण किसी पाठ्यक्रम में स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के मामले में लागू नहीं होगा।

(ख) मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षण या आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा (जिसे

30. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।
31. अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

आवश्यक होने पर भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकेगा किन्तु जो 1 जनवरी, 1979 के पूर्व से प्रभावी नहीं होगा) विनियमित होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उसे निमित्त बनाये :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रवेश के विनियमन का कोई आदेश अल्पसंख्यक वर्गों के, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा।

(ग) खण्ड (क) के अधीन कोई आदेश बनाने में राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करने या उसके प्रयोजनों को विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह तीन मास से अनधिक की अवधि के लिये कारावास से या एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, दण्डनीय होगा।

(5-क) उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उप-बन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते है।

(6) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, और ऐसा उल्लंघन करके दिए गए किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति की शक्ति होगी।

29. (1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जो अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जायगी। **परीक्षा समिति**

(2) धारा 42 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय समिति, साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना,

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना,

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

[31a](4) इस अधिनियम के किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या, यथास्थिति, किसी उप-समिति या किसी व्यक्ति के लिये, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित अपनी शक्ति की प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को

31a. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

30. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य वही होंगे जो विहित किए जाएं। **अन्य प्राधिकारी**

अध्याय 6

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

31. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापक और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न यथास्थिति कार्य परिषद्, अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किए जाएंगें [32](चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो)।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक, निदेशक तथा प्राचार्य की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गई नियुक्ति न हो, प्रथमत: एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगी जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि, -

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् आदेश न दे दे;

(ख) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में प्रबन्ध समिति आदेश न दे दे; और

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अन्य अध्यापक की दशा में प्राचार्य उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक (जब तक कि ऐसा अध्यापक, उस विषय का ज्येष्ठतम अध्यापक न हो) की रिपोर्टों

---

32. अधिनियम संख्या 1 सन् 1992 द्वारा बढ़ाया गया।

पर भी विचार करने के पश्चात् प्रबन्ध समिति आदेश न दे दे :

[32a]परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा :

परन्तु यह भी कि यदि, यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाय तो परीवीक्षा अवधि तब तक के लिये बढ़ जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कार्य परिषद् का अन्तिम आदेश या, यथास्थिति, जब तक कि धारा 35 के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दी जाय।

(3)(क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में कुलपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट विशेषज्ञ के परामर्श से प्रबन्ध समिति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किए बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिए स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य रिक्ति या पद जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिए होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी।

[32a](ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर, नियुक्त किया हो जिसके छः मास से अधिक चलने की सम्भावना रही हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद पर परिवर्तित कर दिया गया हो, या किसी स्थायी

32a. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव सृजित हो वहाँ, यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अध्यापक, ऐसी अधिष्ठायी नियुंक्त के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जायगा जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (2) के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगें

[33](ग) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जिसकी नियुक्ति प्राध्यापक के रूप में 30 जून, 1991 को या उसके पूर्व अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश किये बिना की गयी थी, कार्य परिषद् द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति 2 नवम्बर, 1991 को उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक-

---

33. अधिनियम संख्या 1 सन् 1992 द्वारा बढ़ाया गया।

(एक) 22 नवम्बर, 1991 को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनाँक से निरन्तर कार्य कर रहा हो;

(दो) प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनाँक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हता, 22 नवम्बर, 1991 को रखता हो ;

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हों

ऐसा कोई अध्यापक जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है ऐसे दिनाँक को जैसा कार्य परिषद् विनिर्दिष्ट करे ऐसा पद धारण नहीं करेगा।

(4) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक (किसी संस्थान के निदेशक और घटक महाविद्यालय के प्राचार्य से भिन्न) की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) संबद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब संबद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पंक्ति में ऊँचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग के आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायगा :

[33a]परन्तु यह भी कि जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है; वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते है, ऐसी वे उचित समझे,

---

33a. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

(iii) किसी आचार्य या उपाचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई किसी स्कीम के अधीन क्रमोन्नत घटक मेडिकल महाविद्यालय के किसी विभाग के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का एक-एक नाम निर्देशिती,

(v) किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में यथास्थिति, संस्थान का निदेशक या घटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ख) संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे,

(ग) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध का एक सदस्य जो अध्यक्ष होगा,

[34](ii) उन संकायों के जिनसे संबद्ध विषय महाविद्यालय में पढ़ाये जाते हों, संकायाध्यक्षों अथवा आचार्यों में से कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक संकायाध्यक्ष या आचार्य,

(iii) प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो सदस्य समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा, और

34. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

(iv) दो विशेषज्ञ जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु किसी संबद्ध महाविद्यालय के आचार्य की नियुक्ति की दशा में संकायों का संकायाध्यक्ष, यदि वह स्वयं उस महाविद्यालय का अध्यापक हो, चयन समिति में नहीं बैठेगा :

परन्तु यह और कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतंत्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पाँच विशेषज्ञों के पैनल में से नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे जिनके लिए प्रबन्धतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

[35]परन्तु यह भी पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यालयों की स्थिति में, संकायाध्यक्ष या आचार्य भी, जो उपखण्ड (2) के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, उन पाँच संकायाध्यक्षों या आचार्यों के पैनल में से, जिनके लिए प्रबंधतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो, प्रबंधतंत्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे, और यदि ऐसे संकायाध्यक्ष या आचार्य अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों का नाम पैनल में सम्मिलित किया जा सकता है।

(घ) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध का एक सदस्य जो, उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य और प्राचार्य द्वारा नाम-निर्दिष्ट महाविद्यालय का एक और अध्यापक,

---

. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

(iii) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे :

[36]परन्तु किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में जिसमें उप-खण्ड (2) के अधीन चयन समिति का सदस्य होने के लिए कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक उपलब्ध न हो, चयन समिति इस खण्ड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से गठित होगी :

परन्तु यह और कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबंधतंत्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पाँच विशेषज्ञों के पैनल में से नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे जिनके लिए प्रबंधतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानी संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगा। उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो

(ख) प्रत्येक संकाय का बोर्ड प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए सोलह या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक स्थायी पैनल बनाएगा, और उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

[36a](घ) यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए

36. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा बढ़ाया गया।

36a. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा बढ़ाया गया।

विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट-क्रम ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट-क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- (1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिससे स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके भाग 1 या 2 के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण- (2) जहाँ चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गई किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

[36b](7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी :

परन्तु आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे-

[36c](7-क) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करें।

(8) (क) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई

36b. उ. प्र. अध्यादेश सं. 30 सन् 1994 द्वारा संशोधित।

36c. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा बढ़ाया गया।

सिफारिश से सहमत न हो तो कार्य परिषद् उस मामले को ऐसी असहमत के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

[37]परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

[37a](कक) जहाँ खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चय करने की विफलता कार्य परिषद् के किसी दोष के कारण न हो तो कुलाधिपति कार्य परिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलाधिपति समय-समय पर अनुमति दें विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलपति को इस प्रयोजन से कार्य परिषद् की बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है :

परन्तु (1) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत नहीं है तो कार्य परिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) यदि कार्य परिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ख) किसी संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्धतंत्र चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत न हो तो प्रबन्धतंत्र उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1)

---

37. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा बढ़ाया गया।

37a. उ. प्र. अधिनियम संख्या 30 सन् 1994 द्वारा संशोधित।

में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्धतंत्र चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत न हो तो प्रबन्धतंत्र को एक अन्य चयन समिति नियुक्त करने का अधिकार होगा और उस समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों को नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समितियों के विचार-विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे प्राचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किए जायेंगे।

(10) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायगा, जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाए जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

[38](11) (क) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (जो राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो) का प्रबन्धतंत्र चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी अध्यापक को नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि कुलपति का पूर्वानुमोदन न ले लिया जाय।

(ख) प्रबन्धतंत्र, चयन समिति के अधिवेशन के पश्चात् यथाशीघ्र, अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए कुलपति को प्रस्तुत करेगा।

(ग) कुलपति, यदि उनका समाधान हो जाय कि चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी विहित न्यूनतम अर्हता तथा अनुभव नहीं रखता है, या अध्यापक के चयन के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, प्रबन्धतंत्र को अपनी अस्वीकृति की सूचना देंगे :

38. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित

परन्तु यह कि यदि कुलपति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपनी अस्वीकृति की सूचना नहीं देते है, या प्रबन्धतंत्र को उसके सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं भेजते हैं तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(12) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन मे, या प्रबंधतंत्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर, किसी सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है जो पद के लिए विहित अर्हतायें रखता हो।

(13) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का प्राचार्य उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उक्त कालेज के आचार्यों में से नियुक्त किया जायेगा, और उप-धारा (10) के उपबन्ध ऐसे चयन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों को वैयक्तिक पदोन्नति

[39]31क. (1) इस अधिनियम की किसी अन्य व्यवस्था में निहित विपरीत तथ्यों के बावजूद (1) अनुभाग 31 के अधीन विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया प्रवक्ता या उपाचार्य या इस अनुभाग के अधीन प्रोन्नत व्यक्ति जो अपनी इस प्रकार की सेवावधि में अपेक्षित योग्यता रखता है उसे क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर व्यक्तिगत प्रोन्नति दी जा सकती है।

(2) इस प्रकार की व्यक्तिगत प्रोन्नति अनुभाग 31 के उप-अनुभाग 4 की धारा (अ) के अधीन नियुक्त की गई चयन समिति की संस्तुति पर अपेक्षित शर्तों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

---

39. अधिनियम संख्या 9 सन् 1985 द्वारा प्रतिस्थापित

35. (1) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का (जो राज्य सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो) प्रत्येक अध्यापक लिखित संविदा के अन्तर्गत नियुक्त किया जायगा जिसमें ऐसे निबन्धन तथा शर्तें होंगी, जो विहित की जायें। संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अध्यापक को दी जायेगी, और उसकी दूसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा रखी जायगी। सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालयों से भिन्न सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

(2) ऐसे महाविद्यालय के प्रवन्धतंत्र का किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किया गया प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किए जाने के पूर्व, कुलपति को रिपोर्ट किया जायगा और वह तब तक प्रभावी न होगा जब तक कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबंधतंत्र को किसी अध्यापक को पदच्युत करने, पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किये गये विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा किन्तु उसे विनिश्चय की सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है तब तक विनिश्चय लागू नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के उपबन्ध किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के, किसी विनिश्चय पर भी, चाहे वह दण्ड के रूप में हो या अन्यथा हो, लागू होंगे, किन्तु वह उस कालावधि के व्यतीत हो जाने पर, जिसके लिए अध्यापक नियुक्त किया गया हो, सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में लागू न होंगे :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों

किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य या अध्यापक के पद पर नियुक्ति मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी, इलाहाबाद के नियमों और उपविधियों के अनुसार की जायगी।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के पूर्व उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार की गई समस्त नियुक्तियाँ उक्त उपधारा के अधीन की गयी समझी जायेगी मानो उक्त उपधारा के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।''

कतिपय तदर्थ नियुक्तियों का नियमितिकरण

[40]**31-ख-1** (1) प्राचार्य से भिन्न प्रत्येक अध्यापक को, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1982 या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1983 के उपबन्धों के अनुसार किसी मौलिक रिक्ति में तदर्थ आधार पर 3 जनवरी, 1984 को या इसके पूर्व सीधे नियुक्त हुआ है और जो सम्बन्धित परिनियमावलियों के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हतायें रखता है या जिसे उन उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के दिनाँक से मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायेगा, बशर्ते ऐसा अध्यापक ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनाँक से ऐसे प्रारम्भ के दिनाँक तक उस महाविद्यालय में निरन्तर कार्य करता रहा हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापक को ऐसे प्रारम्भ के दिनाँक से परिवीक्षा पर समझा जायगा।

(3) इस धारा की, किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति का हकदार है, यदि:

40. अधिनियम संख्या 9

(क) ऐसे प्रारम्भ के दिनाँक को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसा पद पहले ही भर दिया गया हो, या ऐसे पद के लिये चयन किया जा चुका है, या

(ख) ऐसा अध्यापक सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र के किसी सदस्य या उसके प्राचार्य का सम्बन्धी हें

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सम्बन्धी समझा जायगा यदि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 20 के स्पष्टीकरण में उल्लिखित रीति से उसका सम्बन्धी हो।

विश्व-विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति संविदा

32. (1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जायगा।

(2) मूल संविदा कुल-सचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, इस प्रकार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवत्त सभी संविदाएं उस विस्तार तक जहाँ तक वे इस अधिनियम के परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों से असंगत हो। उक्त उपबन्धों द्वारा उपान्तरित समझी जायेंगी।

(4) किसी संविदा या अन्य लिखित में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी घटक, चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यापकों का, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

पेंशन, भविष्य निधि आदि

33. विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए [40a]जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत एक ऐसी निधि भी है जिससे ऐसे अध्यापकों वा यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में निर्योग्य, आहत, या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जायगा।

अध्यापकों के पारिश्रमिकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा

34. (1) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किए गये किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय सम्बन्धी शर्तें [41]वहीं होगी जो विहित की जायें।

(2) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक, अध्यापन सम्बन्धी कर्त्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्त्तव्यों से भिन्न कर्त्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-''पारिश्रमिक पद'' शब्दों के अन्तर्गत छात्र निवास अथवा छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीड़ाधीक्षक, पुस्तकाध्यक्ष और नेशनल कैडिट कोर, राजकीय खेल-कूद संगठन, राष्ट्रीय समाज सेवा स्कीम तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई पद भी है।

40a. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

41. अधिनियम संख्या 39 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) इस अनुभाग में निहित कोई भी बात अनुभाग 31 की व्यवस्था के अनुसार प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों को प्रभावित नहीं करेगी।

31कक. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त किसी सहायक आचार्य को या उक्त विश्वविद्यालय के उक्त संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत किसी सह-आचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जैसी विहित की जांय, सह-आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है। सह-आचार्य और आचार्य के पद की पदोन्नति

(2) उपधारा (1) के अधीन पदोन्नति, धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी।

स्पष्टीकरण- लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय के सम्बन्ध में धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शब्द ''उपाचार्य'' का अर्थ ''सहआचार्य'' होगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय के दंत चिकित्सा विज्ञान या औषधि संकाय के संदर्भ में 'रीडर' या 'उपाचार्य' शब्द, अनुभाग 31 के उप अनुभाग 4 की धारा (अ) में किये गये उल्लेख के अनुसार "Associate Professor" उपाचार्य के रूप में माना जायेगा। **व्याख्या**

(3) इस अधिनियम की किसी अन्य व्यवस्था में **या** उप-अनुभाग 1 या 2 में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ की तिथि से सेवा में कार्यरत और राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश सं0 842/15.10.97-11 (7)/96 दिनांक 11 अप्रैल 1997 के अनुसार, उप अनुभाग 1 में उल्लिखित संकाय में प्रोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति प्रोन्नति की तिथि से उप अनुभाग 1 के अधीन प्रोन्नत हुआ माना जायेगा।

31-ख. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 में नियुक्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

की दशा में, प्रबन्धतंत्र के किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित न होगा, उसे विनिश्चय की सूचना दी जायेगी और जब तक उसका समाधान न हो जाय, कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है तब तक विनिश्चय प्रभावी नहीं किया जायगा।

(4) उपधारा (2) की कोई बात जाँच के दौरान निलम्बन के आदेश पर, लागू नहीं समझी जायेगी, किन्तु कुलपति द्वारा ऐसा कोई आदेश स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकेगा :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में ऐसा आदेश कुलपति द्वारा तभी स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकेगा जब ऐसे निलम्बन के लिए विहित शर्तें पूरी न की गई हो।

(5) ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो विहित की जायें।

माध्यस्थम् अधिकरण

36. (1) धारा 32 या धारा 33 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति-संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा),

(ख) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की दशा में, महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अध्यापक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का कार्य करेगा) :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबंधतंत्र के और सम्बन्धित अध्यापक के नाम-निर्देशितियों द्वारा संयोजक का चयन, ऐसे पाँच व्यक्तियों के पेनल में से किया जायगा जिनके लिए प्रबंधतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

परन्तु यह और कि विहित समय के भीतर उनके संयोजक नियुक्त करने में असफल रहने पर तो कुलपति पेनल में से संयोजक नाम-निर्दिष्ट करेगा।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाये तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति या सम्बन्धित निकाय उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियाँ उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर रिक्त पद की पूर्ति की जाये।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

(i) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ii) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना; और

(iii) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलम्बित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) माध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम पर लागू होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही कि ऐसी बात के बारे में नहीं की जायेगी जो उपधारा (1) द्वा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित ह

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्ये विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारिता युक्त निम्नतम् न्यायालय द्वा निष्पादनीय होगा मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो

अध्याय 7

सम्बद्धता तथा मान्यता

सम्बद्ध महाविद्यालय

37. (1) यह धारा आगरा, गोरखपुर, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों और (लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों से भिन्न) ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होगी जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(2) कार्य परिषद् कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से, सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी :

[41a][* * * *]

(3) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए, उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय मे अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।

(4) इस अधिनियम द्वारा तथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, महाविद्यालय के कार्य-कलापों का प्रबन्ध और नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगा जिन्हें परिषद् या कुलपति माँगें।

41a. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा निकाला गया।

(6) कार्य परिषद्, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का, अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पाँच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को भेजी जाएगी।

(7) कार्य परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(8) कार्य परिषद् द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद् के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

[42](9) उपधारा (2) और (8) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है तो कुलाधिपति प्रबंधतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेंगे या उसमें कमी कर सकेंगे।

सहयुक्त महाविद्यालय

38. (1) यह धारा लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों तथा (आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से भिन्न) ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होगी जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(2) सहयुक्त महाविद्यालय वही होंगे जो परिनियमों द्वारा नामित किये जायें।

(3) किसी सहयुक्त महाविद्यालय के लिए किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से

42. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्यापन कार्य में सहयोग प्राप्त करने का इन्तजाम करना विधिपूर्ण होगा।

(4) किसी सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जायेंगी, अथवा कार्य परिषद् द्वारा अधिरोपित की जायेगी, किन्तु किसी सहयुक्त महाविद्यालय को, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना स्नातकोत्तर उपाधि के लिए शिक्षण देने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जायगा :

परन्तु यदि किसी सहयुक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर उपाधि के लिए शिक्षण देने के लिए मान्यता देने से इन्कार किया जाए तो धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे महाविद्यालय को, कुलाधिपति के अनुमोदन से धारा 37 में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दी जा सकेगी और तदुपरान्त ऐसा महाविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय न रह जायगा।

(5) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सहयुक्त महाविद्यालय को प्रबंधतंत्र महाविद्यालय के कार्यों का प्रबन्ध तथा नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) कार्य परिषद् प्रत्येक सहयुक्त महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर तीन वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेंगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को भेजी जाएगी।

(7) यदि कार्य परिषद् का यह समाधान हो जाये कि किसी सहयुक्त महाविद्यालय ने मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा उसके इन अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में अथवा कार्य परिषद् द्वारा अपने काम में बताई गई किसी त्रुटि को दूर करने में निरन्तर व्यतिक्रम किया है तो वह कुलपति की पूर्व मंजूरी से प्रबंधतंत्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे महाविद्यालयों

की मान्यता वापस ले सकेंगी।

(8) इस धारा में या धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे विश्वविद्यालय, जिस पर यह धारा लागू होती हो, के क्षेत्र में स्थित किसी महाविद्यालय को, उस विश्वविद्यालय की सम्पत्ति से किसी ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा जिस पर धारा 37 लागू होती हो, संबद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकेगा।

प्रबंधतंत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता

39. कोई भी व्यक्ति (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न), सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह अथवा उसका सम्बन्धी ऐसे महाविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए अथवा उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या महाविद्यालय के किसी छात्र-निवास का छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए अथवा महाविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण- पद "नातेदार" का वहीं अर्थ होगा जो उसके धारा 20 के स्पष्टीकरण में दिया गया हें

सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का निरीक्षण आदि

40. (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गई परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने

अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के संबंध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराने का निश्चय करे तो वह उसकी सूचना प्रबन्धतंत्र को देगी और प्रबंधतंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतंत्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबंधतंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा, किन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थिति होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898[42a] की धारा 480 तथा 482 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(4) राज्य सरकार प्रबन्धतंत्र को ऐसे निरीक्षण या जाँच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और किये जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निदेश दे सकेगी और प्रबंधतंत्र ऐसे निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबंधतंत्र को दी गई किसी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी।

(6) राज्य सरकार किसी समय सम्बद्ध या सहयुक्त

महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र अथवा प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण य जाँच के सम्बन्ध में कोई जानकारी माँग सकेगी।

घटक महाविद्यालय

41. (1) घटक महाविद्यालय वही होंगे जो परिनियमों द्वार नामित किए जायें।

(2) किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य, महाविद्यालय में नामावलिगत छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और महाविद्यालय को आवंटित लिपिक वर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर साधारण नियंत्रण होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

स्वायत्त महाविद्यालय

42. (1) विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को, जो इस निमित्त विहित शर्तों को, पूरा करे ऐसे महाविद्यालय में शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित अध्ययन पाठ्यक्रमों में, विहित रीति से परिवर्तन करने, तथा इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगा।

(2) ऐसे महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने की सीमा तथा परीक्षा लेने की रीति प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जाएगी।

(3) ऐसा कोई महाविद्यालय विहित रीति से स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया जाएगा।

श्रमजीवी महाविद्यालय

43. (1) विश्वविद्यालय, ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जायें, ऐसे व्यक्तियों के लिए उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ जो ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए अन्यथा पात्र हों, किन्तु जो व्यवसाय, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे होने अथवा किसी अन्य प्रकार की सेवा में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक छात्रों के रूप में नामावलिगत होने में असमर्थ हों, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता दे सकेगा।

(2) ऐसे छात्रों के लिए पाठ्यक्रमों की अवधि का विस्तार अन्य छात्रों के निमित्त पाठ्यक्रम के लिए विहित कालावधि के डेढ़ गुने से कम नहीं होगी।

(3) प्रत्येक ऐसा पाठ्यक्रम पृथक रूप से संगठित किया जायगा।

44. विश्वविद्यालय किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा।

अध्याय 8
प्रवेश तथा परीक्षायें

छात्रों का प्रवेश

45. (1) कोई भी छात्र किसी भी उपाधि के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश पाने के लिए पात्र न होगा जब तक कि -

(क) उसने -

(i) उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड की अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो,

(ii) कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ऐसी कोई उपाधि प्राप्त न कर ली हो जो ऐसी परीक्षा या उपाधि हो जिसे विश्वविद्यालय ने इण्टरमीडिएट परीक्षा या विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के बराबर मान्यता दी हो, और

(ख) वह ऐसी अतिरिक्त अर्हतायें, यदि कोई हों, रखता हो जो अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जायें :

परन्तु विश्वविद्यालय ललित कला की किसी उपाधि के लिए प्रवेश की न्यूनतर अर्हतायें अध्यादेशों द्वारा विहित कर सकेगा।

(2) वे शर्तें जिनके अधीन छात्र विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकेंगे, अध्यादेशों द्वारा विहित की जायेंगी।

(3) विश्वविद्यालय को (किसी उपाधि या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के प्रयोजनार्थ), किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, संचालित किसी परीक्षा को, किसी भारतीय विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता देने की शक्ति होगी।

(4) किसी ऐसे छात्र को, जिसका काम अथवा आचरण असमाधानप्रद हो, विश्वविद्यालय या संस्थान या घटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार हटाया जा सकेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

46. सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे[43] महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से अध्यादेशों में अधिकथित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

महाविद्यालय को अंशदान और दान

[44]**46-क.** जहाँ किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहाँ इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायगा जिसके लिए वह महाविद्यालय को दिया गया और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा। जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के छात्रावास तथा अनिवासी छात्र केन्द्र

47. (1) यह धारा लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, पर लागू होगी।

---

43. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।
44. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) विश्वविद्यालय के छात्र-निवास या छात्रावास वही होंगे जो -

(क) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित तथा परिनियमों में नामित हों,

(ख) कार्य परिषद् द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर जो अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित की जायें, मान्यता प्राप्त हों।

(3) छात्र-निवासों तथा छात्रावासों के वार्डन और अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(4) कार्य परिषद् को किसी ऐसे छात्र-निवास या छात्रावास की जो उपधारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार घोषित न हों, मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसे छात्र-निवास या छात्रावास के प्रबन्धतंत्र को प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिये बिना कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(5) विश्वविद्यालय के ऐसे छात्रों के लिए, जो किसी घटक महाविद्यालय या छात्र-निवास में अथवा उसकी देख-रेख में नहीं रहते हैं, निवास स्थान, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी इन्तजाम का पर्यवेक्षण करने के लिए एक अनिवासी छात्र केन्द्र होगा। अनिवासी छात्र केन्द्र का गठन, शक्ति तथा कर्त्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

परीक्षायें

48. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिए इन्तजाम करने का निदेश देगी।

अध्याय 9

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

49. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे : **परिनियम**

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्त्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वाँछनीय हो :

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य ;

[45](घ) सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं) उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण, नियम और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित है);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है) और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित है);

---

45. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना

(छ) उपाधियाँ तथा डिप्लोमा संस्थित करना ;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(झ) उपाधियाँ और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना ;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुनः संगठन ;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना ;

(ठ) विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित छात्र-निवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनः संगठन; वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाये और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सकें;

(ढ) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को मान्यता प्रदान करना;

[46](ण) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा-निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं, और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;

(त) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा परितोषिकों को संस्थित करना;

---

46. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

(थ) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हतायें, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना;

(द) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, करना; और

(ध) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगें

50. (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, जब तक प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनायें जायें, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन जो आवश्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपान्तरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी। **परिनियम कैसे बनायें जायेंगे**

[47](1-क) राज्य सरकार [48]31 दिसम्बर, 1990 तक किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी, चाहे वे परिवर्तन, प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हों, और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनाँक से हो सकेगा जो इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनाँक से पहले का न हो।

[49](2) कार्य परिषद्, [50]31 दिसम्बर, 1990 के पश्चात् किसी समय, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।

---

47. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा बढ़ाया गया।
48. अध्यादेश सं. 15 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
49. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
50. अध्यादेश संख्या 3 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) कार्य परिषद्, किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्य परिषद् को भेज सकेगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाय अथवा ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्रभावी होगा।

[51](6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में या अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारी वर्ग के लाभ के लिए या अध्यापकों की अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए, कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार कुलाधिपति की अनुमति से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना

---

51. अध्यादेश संख्या 30 सन् 1994 द्वारा बढ़ाया गया। अधिनियम संख्या 9 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित (17.9.1997 से प्रभावी)।

सकती है या उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद् को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी।

51. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें। अध्यादेश

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलिगत होना और इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टतायें;

(ग) वे शर्ते जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जायगा तथा वे ऐसी उपाधियों तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्ते;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वार पोषित छात्रनिवास और छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्ते;

(च) ऐसे छात्रनिवास और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबन्ध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना;

(ज) पत्राचार पाठ्य-क्रमों तथा प्राइवेट अभ्यर्थियों से सम्बन्धित सभी विषय;

[52](झ) अभिभावक-शिक्षक एसोसियेशन की रचना;

(ञ) फीस जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजनार्थ ली जा सकें;

(ट) वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रनिवास तथा छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाये;

(ठ) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उसके कर्त्तव्य;

(ड) परीक्षाओं का संचालन;

(ढ) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं;

(ण) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

52. (1) प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश वही होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों प्रवृत्त हों :

परन्तु ऐसे किन्हीं अध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिये

---

52. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेश में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हों, कर सकेगा जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो और उपबन्ध कर सकेगा कि अध्यादेश ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

(2) कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालय और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे।

(3) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यादेश कार्य परिषद् समय-समय पर नये अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :-

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा :-

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि पाठ्य-क्रम में प्रवेश के लिये धारा 45 की उपधारा (1) में वर्णित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करें जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो,

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्त्तव्यों तथा परीक्षाओं का किसी पाठ्य-क्रम के संचालन या स्तर पर पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय या संकायों की प्रस्थापना के अनुसार न हों, या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो, या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हों।

(4) कार्य परिषद् को उपधारा (3) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे स्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद् को पूर्णत: अथवा भागत: पुन: विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी जिसका कार्य परिषद् सुझाव दें।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशाक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(6) कुलाधिपति, किसी समय कार्य परिषद् को उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(7) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हों इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

विनियमन

53. (1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा-

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों; और

(ग) किसी ऐसे अन्य विषय का उपबन्ध करना जिनका सम्बन्ध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये, विनियमों में, उसके सदस्यों की अधिवेशनों की तारीखों की, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले कामकाज का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेगा।

(3) कार्य परिषद् सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा :

परन्तु यदि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय का समाधान किसी ऐसे निदेश से न हो तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है, जो कार्य परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझें

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए विनियम सम्बन्धित संकाय

के बोर्ड द्वारा उसके प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही
बना सकेगा।

(5) विद्या परिषद् को उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

अध्याय 10

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

54. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे सभा को उसके वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी। **वार्षिक रिपोर्ट**

(2) सभा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे।

55. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्य परिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धन और ऐसी रकमें जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखी गई लेखा में प्रविष्ट की जायेंगी।1 **लेखा तथा संपरीक्षा**

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उनकी संपरीक्षा कराएगी।

(3) वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र की सम्परीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायगा और उनकी प्रतियाँ संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों सहित कार्य परिषद् द्वारा सभा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) कार्य परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाये आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथाविहित रकम से अधिक हो जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जाएगी जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद् जो वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) वार्षिक लेखा, तुलनपत्र तथा संपरीक्षा रिपोर्ट पर सभा अपनी वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और सभा उसके संबंध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी।

(8) कुलपति या कार्य परिषद् द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगा -

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो :

परन्तु धारा थ ध की उपधारा (ब) के किसी बात के होते हुए भी, अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति पाँच हजार से अधिक ऐसी अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा जो बजट में मंजूर हो और ऐसे सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा।

(ख) जो [53]इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के अधीन किसी आदेश का विरोध करने के लिए किसी मुकदमे के संबंध में हो।

अधिभार

[54]**55-क.** (1) धारा 9 के खण्ड (ग) से (झ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

---

53. अधिनियम संख्या 12 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित।
54. अधिनियम संख्या 12 सन् 1978 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय 11

उपाधि महाविद्यालयों का विनियमन

56. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो :- **परिभाषायें**

(क) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के संबंध में "संपत्ति" के अन्तर्गत महाविद्यालय की समस्त संपत्ति आती है, चाहे जंगम हों और स्थावर, जो उस महाविद्यालय से सम्बन्धित हो या उस महाविद्यालय के फायदे के लिए पूर्णत: या भागत: विन्यासित हो और जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन (छात्रावासों सहित), संकर्म, पुस्तकालय, प्रयोगशाला उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, स्टोर, स्वचालित यान और अन्य यान, यदि कोई हों, और महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य चीजें, हाथ की रोकड़, बेंक नकदी, विनिधान और बही ऋण और ऐसी सम्पत्ति जो महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, से उद्भूत ऐसे सभी अन्य अधिकार और हित और समस्त लेखाबहियाँ, रजिस्टर और तत्सम्बन्धी किसी भी प्रकार की अन्य दस्तावेजे है तथा महाविद्यालय के सभी अस्तित्वयुक्त उधार और किसी भी प्रकार के दायित्व और बाध्यतायें भी इसके अन्तर्गत समझी जायेंगी।

(ख) "वेतन" से उपलब्धियों का जोड़ अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत अध्यापक या अन्य कर्मचारी को अनुज्ञेय कटौतियाँ करने के पश्चात् तत्समय संदेय महँगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ता है।

57. यदि राज्य सरकार को किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है :- **सूचना जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति**

(i) कि उसके प्रबन्धतंत्र ने महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों को उस मास के जिसके सम्बन्ध में या जिसके भाग के सम्बन्ध में वेतन संदेय है, अगले मास के बीसवें दिन तक वेतन का संदाय करने में जानबूझकर बार-बार व्यक्तिक्रम किया है ; या

(ii) कि उसका प्रबन्धतन्त्र ऐसी अर्हताओं वाले, जो महाविद्यालय के सम्बन्ध में विद्या सम्बन्धी स्तरों को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, अध्यापक नियुक्त करने में असफल रहता है, अथवा उसने परिनियमों या अध्यादेशों के उल्लघंन में किसी अध्यापक को नियुक्त किया है या सेवा में रखा हुआ है या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अधीन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है; या

(iii) कि ऐसे किसी विवाद ने जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार के बारे में है कि वे उसके प्रबन्धतंत्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी हैं, महाविद्यालय के सुचारु और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव डाला है ; या

(iv) कि उसका प्रबन्धतंत्र महाविद्यालय को ऐसे पर्याप्त और उचित आवास, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, प्रयोगशाला, उपस्कर और अन्य सुविधायें जो महाविद्यालय के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक हैं, की व्यवस्था करने में बार-बार असफल रहा है; या

(v) कि उससे प्रबन्धतंत्र महाविद्यालय की सम्पत्ति या सारवान रूप से इस प्रकार परिवर्तन, दुरुपयोजन या दुर्विनियोजन किया है जिससे महाविद्यालय को अहित

हो, तो वह प्रबन्धतंत्र से यह कारण दर्शित करने की माँग कर सकेगी कि धारा 58 के अधीन आदेश क्यों न किये जायें :

परन्तु जहाँ यह विवाद हो कि प्रबन्धतंत्र के पदाधिकारी कौन है, तो ऐसी सूचना उन सभी व्यक्तियों को जारी की जायगी जो ऐसी होने का दावा करते है।

प्राधिकृत नियंत्रक

58. (1) यदि धारा 57 के अधीन प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि उस धारा में वर्णित कोई आधार विद्यमान है तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगी कि वह महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो विनिर्दिष्ट की जाये अपने हाथ में ले ले और यह प्रबन्धतंत्र को अपवर्जित करके होगा और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध को इस प्रकार अपने हाथ मे लेता है तब उन निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार अधिरोपित करे, उसे महाविद्यालय तथा उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे जैसा कि प्रबन्धतंत्र को उस समय होता जबकि महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति इस उपधारा के अधीन हाथ में नहीं ली गई होती।

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित बनाये रखने के लिए ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर इस आदेश के प्रवर्तन का विस्तार ऐसी अवधि के लिए जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो, यथा विनिर्दिष्ट रूप में कर सकेगी किन्तु इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत इस उपधारा के अधीन प्रारम्भ के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी

है, [54a]पाँच वर्ष से अधिक न हो।

[54a](Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully Constituted Management of the College the Authorised Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that the Management has been lawfully constituted)

परन्तु यह और कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन किये गये आदेश को किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) धारा 57 के अधीन सूचना जारी करते हुये जब राज्य सरकार की राय अभिलिखित कारणों से यह हो कि महाविद्यालय के हित में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह प्रबन्धतंत्र निलम्बित कर सकेगी जो तदुपरान्त कृत्य नहीं करेगा और महाविद्यालय तथा उसकी सम्पत्ति के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिये अग्रेतर कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसा प्रबन्ध करेगी जैसा कि वह ठीक समझे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जब कि ऐसे आदेश के अनुसरण में प्रबन्ध तंत्र को वास्तव में हाथ में लिया जाता है, छः मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि उक्त छः मास की अवधि की संगणना करने में वह समय जिसके दौरान यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा निलम्बित रहा था या कोई अवधि जिसके दौरान प्रबन्धतंत्र धारा 57 के अधीन सूचना के अनुसरण में कारण दर्शित करने में असफल रहा था, अपवर्जित कर दी जायेगी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह प्राधिकृत नियंत्रक को महाविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करने (प्रबन्ध करने के साधारण

54a. अधिनियम संख्या 4 सन् 1983 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुक्रम में मासानुमास किराये पर दिये जाने के सिवाय) या उस पर कोई प्रभार सृजित करने की (राज्य सरकार या भारत सरकार से महाविद्यालय को किसी सहायता अनुदान की प्राप्ति की शर्त के सिवाय) शक्ति प्रदान करती है।

(4) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश महाविद्यालय के या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा :

परन्तु महाविद्यालय की सम्पत्ति और उससे कोई आय महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार किया जाता रहेगा जैसाकि किसी ऐसे लिखत में उपबंधित हों।

(5) शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) का निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति के उचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों का पालन करेगा।

सहायता न प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग वाले महाविद्यालयों को धारा 58 का लागू न होना

59. धारा 58 की कोई बात किसी ऐसे महाविद्यालय को लागू न होगी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित हों।

प्राधिकृत नियंत्रक को सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने का कर्त्तव्य

60. (1) जहाँ किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में धारा 58 के अधीन आदेश पारित किया गया हो तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रणाधीन महाविद्यालय की कोई सम्पत्ति है वह सम्पत्ति प्राधिकृत नियंत्रक को तत्काल परिदत्त कर देगा।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस आदेश की तारीख पर महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी बही या अन्य दस्तावेज पर कब्जा या नियंत्रण रखता है, उक्त बही और अन्य दस्तावेजों का लेखा प्राधिकृत नियंत्रक को देने के लिये दायी होगा और उन्हें उसको या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक कलेक्टर से महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा और नियंत्रण परिदत्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे महाविद्यालय या सम्पत्ति का कब्जा सुनिश्चित कराने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाएगा और विशिष्टत: यथावश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा या कराएगा।

---

[55]अध्याय 11-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

60-क. इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-(1) 'महाविद्यालय' से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उसे तत्समय राज्य सरकार से पोषण अनुदान मिलता हो (किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या किसी [55a]स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय नहीं है); परिभाषायें

(2) 'उप-निदेशक' से सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन उप-निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;

(3) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'कर्मचारी' से ऐसे महाविद्यालय का अध्यापनेतर कर्मचारी अभिप्रेत है -

(क) जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो; या

(ख) जो शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से किसी पद पर नियुक्त किया गया हो;

(4) 'पोषण अनुदान' से किसी महाविद्यालय का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के लिये समुपयुक्त पोषण अनुदान मानने के लिये निदेश दें;

---

55. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा बढ़ाया गया।
55a. अधिनियम संख्या 15 सन् 1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) 'वेतन' का वही अर्थ होगा जो धारा 56 के खण्ड (ख) में उसके लिये दिया गया हें

(6) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, 'अध्यापक' से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो, अथवा जो -

(क) सम्बद्ध कुलपति की अनुज्ञा से 1 अप्रैल, 1975 के पूर्व सृजित किस पद पर, या

(ख) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से 31 मार्च, 1975 के पश्चात् सृजित किसी पद पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से नियोजित हो।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

60-ख. (1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी 31 मार्च, 1975 के पश्चात् किसी कालावधि के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उस मास के जिसके लिये या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, अनुवर्ती मास की बीसवीं तारीख की समाप्ति के पूर्व या उससे और पहले ऐसी तारीख को जैसा राज्य सरकार सामान्य आदेश द्वारा उस निमित्त नियत करे, उसे किया जायगा।

(2) सिवाय उन कटौतियों के जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, वेतन का संदाय किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना किया जाएगा।

निरीक्षण करने की शक्ति

60-ग. (1) उप-निदेशक किसी समय इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करवा सकेगा या उसके अध्यापकों अथवा कर्मचारियों के वेतन के संदाय के सम्बन्ध में उसके प्रबन्धतंत्र से ऐसी सूचना तथा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर

लेखा-बहियाँ तथा वाउचर भी हैं) माँग सकेगा अथवा वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों के अनुपालन के लिये उसके प्रबन्धतंत्र को कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छटनी करने अथवा किसी अपव्ययकारक व्यय के प्रतिषेध के लिये कोई निदेश भी है) दे सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन छटनी के लिये प्रत्येक निदेश, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् जारी किया जायगा और उसमें ऐसा भावी दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब से ऐसी छटनी प्रवृत्त होगी।

(3) जहाँ उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार छंटनी के लिये कोई निदेश जारी किया जाय वहाँ सम्बद्ध अध्यापक अथवा कर्मचारी इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनाँक से महाविद्यालय का अध्यापक अथवा कर्मचारी नहीं रह जायगा।

[56]**60-गग.** कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकता है कि ऐसा अध्यापक जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियाँ अर्जित कर सके और भविष्य निधि में अंशदान कर सके और सेवा-निवृत्ति के लाभ यदि कोई हों, प्राप्त कर सके : **अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद**

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिये ऐसे अध्यापक को महाविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

60-घ. (1) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के संवितरण के प्रयोजनों के लिये किसी अनुसूचित बेंक अथवा सहकारी बेंक या डाकखाने **कतिपय महाविद्यालयों की दशा में वेतन संदाय की प्रक्रिया**

56. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

में एक पृथक लेखा (जिसे आगे इस अध्याय में 'वेतन संदा लेखा' कहा गया है) खोलेगा जिसे प्रबन्धतंत्र के एक प्रतिनि और उप-निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो उप-निदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से चला जायगा:-

परन्तु वेतन संदाय लेखा खोले जाने के पश्चात् य उप-निदेशक का धारा 60-ज के अधीन बनाये गये किन्हीं निय के अधीन रहते हुये यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐ करना समीचीन है तो वह बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा लेखा अकेले प्रबन्धतंत्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायगा अ वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखँडित कर सकेगा

परन्तु यह और कि उप-धारा (3) में निर्दिष्ट दशा में अथ जहाँ किसी अन्य दशा में प्रबन्धतंत्र को हेतुक दर्शित करने व अवसर देने के पश्चात् उप-निदेशक की यह राय हो कि ऐ आवश्यक या समीचीन है तो उप-निदेशक बैंक को यह अनुदे दे सकेगा कि वेतन संदाय लेखा उपनिदेशक द्वारा ही अथवा ऐ अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह उस निमित्त प्राधिकृत करे, चला जायेगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखण्डित क सकेगा।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य अथवा विशे आदेश द्वारा किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से यह अपेक्षा क सकेगी कि वह छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि व ऐसा भाग और महाविद्यालय की या उसके लाभार्थ पूर्णत अंशत: धर्मास्वति किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आ का ऐसा भाग भी यदि कोई हो, ऐसी तारीख तक जिन्हें उ आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय वेतन संदाय लेखा में जमा क और तदुपरान्त प्रबन्धतंत्र ऐसे निदेश के अनुपालन करने के लि बाध्य होगा।

(3) जहाँ उप-निदेशक की वह राय हो कि प्रबन्धत ने उप-धारा (2) अथवा तद्धीन जारी किये गये आदेशों

उपबन्धों के अनुसार फीस नहीं जमा की है वहाँ उप-निदेशक आदेश द्वारा प्रबन्धतंत्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तदुपरान्त उप-निदेशक छात्रों से प्रत्यक्षत: (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) फीस वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन संदाय लेखा में जमा करेगा।

(4) राज्य सरकार भी वेतन संदाय लेखा में पोषण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो उपधारा (1) तथा (3) के अधीन जमा की गई धनराशि को ध्यान में रखते हुये, उपधारा (5) के अनुसार संदाय करने के लिये आवश्यक हो।

(5) वेतन संदाय लेखा में जमा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायगा, अर्थात् :

(क) 31 मार्च, 1975 के पश्चात् की किसी कालावधि के लिये महाविद्यालय अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को देय होने वाले वेतन के संदाय के लिये;

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में प्रबन्धतंत्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिये।

(6) किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी का वेतन, वेतन संदाय लेखा से उसी बेंक में उसके लेखे में यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, अथवा यदि उस बेंक में उसका लेखा न हो तब चेक द्वारा संदत्त किया जायेगा।

वेतन के संबंध में दायित्व

60-ङ. (1) राज्य सरकार प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के 31 मार्च 1975 के पश्चात् की किसी कालावधि के सम्बन्ध में देय होने वाले वेतन का संदाय करने के लिए देनदार होगी।

(2) राज्य सरकार कोई ऐसी धनराशि जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, महाविद्यालय की अथवा उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्क करके वसूल कर सकेगी मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय भू-राजस्व का बकाया हो।

(3) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे किन्हीं ऐसे देयों के सम्बन्ध में जो अध्यापक अथवा कर्मचारी को देय हो, महाविद्यालय के दायित्वों का अल्पीकरण होता है।

दण्ड आस्तियां तथा प्रक्रिया

60-च. (1) यदि धारा 60-ग के अधीन किसी निदेश का या धारा 60-ख या धारा फत-घ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यक्तिक्रम किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो व्यतिक्रम किये जाने के समय महाविद्यालय का प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें उसके कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित था जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने व्यतिक्रम के किये जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, धारा 60-ख, के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करने की दशा में जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा और किसी अन्य व्यतिक्रम की दशा में कारावास जो छः मास तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उप-निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो, किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के

आदेश के बिना नहीं करेगा और न वारन्ट के बिना गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई भी न्यायालय जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे पंक्ति का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

आदेश का अन्तिम होना।

60-छ. इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उप-निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

60-ज. (1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की कालावधिपर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख में ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

अध्याय 12

शास्तियाँ तथा प्रक्रिया

शास्तियां

61. (1) जो कोई धारा 46 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, सिद्धदोष होने पर ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो तीन मास तक की हो सकती है या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो -

(क) महाविद्यालय की कोई ऐसी सम्पत्ति का जिसके सम्बन्ध में धारा 58 के अधीन आदेश किया गया था, कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखता है, ऐसी सम्पत्ति को उस धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक से या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से दोषत: रखे रखता है, या

(ख) ऐसे महाविद्यालय की किसी सम्पत्ति का कब्जा दोषत: अभिप्राप्त करता है या,

(ग) कोई बही या अन्य दस्तावेज जो उसके कब्जा अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, प्राधिकृत नियंत्रक को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट धारा 60 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने में जान-बूझकर रोकता है या असफल रहता है, या

(घ) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी या किसी उपबन्ध का सम्यक् रूप से पालन करने में जानबूझकर बाधा डालता है, सिद्धदोष होने पर ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय

अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराते समय उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह दोषत: रखी गई या दोषत: अभिप्राप्त किसी सम्पत्ति को या जानबूझकर रखी गई किसी बही या अन्य दस्तावेज को न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर परिदत्त कर दे या वापस कर दें

न्यायालयों का संज्ञान

62. कोई भी न्यायालय शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) के निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना धारा 61 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों द्वारा अपराध

63. (1) यदि धारा 61 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो तो सोसाइटी और अपराध किये जाने के समय उसके कारोबार के संचालन के लिए सोसाइटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिए दायी होगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का दायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि उसकी जानकारी के बिना अपराध किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध कर दिया जाता है कि ऐसा अपराध उस सोसाइटी को किसी सदस्य की सम्पत्ति या मौनानुकूलता से किया गया है या ऐसे अपराध का किया जाना सोसाइटी के किसी सदस्य की उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

64. (1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में के सदस्य यथासम्भव, निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगें

(2) जहाँ इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाय।

(3) जहाँ इस अधिनियम में निर्वाचन के लिए कोई उपबन्ध किया गया हो तो, ऐसा निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जायगा और जहाँ परिनियमों में निर्वाचन के लिए उपबन्ध किया गया है तो वह ऐसी रीति से होगा जैसी परिनियमों द्वारा उपबंधित हों

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिए पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

65. (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहताँ

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे

वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय के प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियां आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

66. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :-

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी ; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी ; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हों

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

67. सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है जो सभी की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूरी की गई कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निर्देश

68. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं,

अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय [58](जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधि मान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश -

(क) उस तारीख के जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था; तीन मास से अधिक के पश्चात्,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में -

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निर्देश ग्रहण कर सकेगा,

(ख) जहाँ निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझें।

(ग)[59]

प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध अपना आदेश प्रवृत्त करने की कुलपति की शक्ति

[60]**68-क.** (1) जहाँ सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने, या पंक्तिच्युत करने या किसी अन्य रीति से उसे दण्ड देने या उसकी

58. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा बढ़ाया गया।
59. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा निकाला गया।
60. अध्यादेश संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

सेवा समाप्त करने के विनिश्चय का कुलपति ने अनुमोदन नहीं किया है या जहाँ इस अधिनियम के या धारा 74 द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुलपति ने ऐसे अध्यापक के निलम्बन के आदेश को स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर दिया है, और प्रबन्धतत्रं ने ऐसे अध्यापक के वेतन का जो कुलपति के आदेश के परिणामस्वरूप उसे देय हो गया है, भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है, वहाँ कुलपति या आदेश दे सकता है कि प्रबन्धतन्त्र वेतन की उस राशि का भुगतान करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो तथा निलम्बन काल में, देय वेतन का 1/2 की दर से निलम्बन भत्ता, यदि भुगतान न किया गया हो तो, भुगतान करने के लिए भी प्रबन्धतंत्र को आदेश दे सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी मामले में, कुलपति सम्बद्ध अध्यापक की ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा वह उचित समझे, बहाली का भी आदेश दे सकता हें

(3) उपधारा (1) के अधीन कुलपति के किसी आदेश में भुगतान के लिए अपेक्षित वेतन या निलम्बन भत्ता की धनराशि कुलपति द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र पर, कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल की जायगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कुलपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारितायुक्त निम्नतम् सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा, मानो वह उस न्यायालय की डिक्री हो।

(5) किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिसके लिए इस धारा के अधीन कुलपति द्वारा अनुतोष दिया जा सकता है, किसी प्रबन्धतंत्र या अध्यापक के विरुद्ध कोई वाद ग्राह्य नहीं होगा।

वाद का वर्जन

[61]69. राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या उपनिदेशक (जैसा धारा 60-क में परिभाषित है) या प्राधिकृत नियंत्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी

61. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिए न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियाँ की जा सकेंगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

70. (1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी जैसाकि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

अध्याय 14
संक्रमणकालीन उपबन्ध

विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिकारियों का बना रहना

71. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तारीख को किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबन्धन तथा शर्तों पर अपने पदावधि की समाप्ति तक पद धारण किये रहेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

[62]**72.** (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीध्र, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व ऐसे प्राधिकारी के एक सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनाँक से ऐसा सदस्य नहीं रह जायगा।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह समय-समय पर निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य तथ्य अथवा निर्वाहन योग्य शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वाहन किसके द्वारा और किस रीति से किया जायगा।

[63]परन्तु ऐसा कोई निदेश 31 दिसम्बर, 1981 के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 की धारा 67 की उप-धारा (2) के अनुसरण में गठित प्रशासनिक समितियाँ और विद्या समितियाँ 15 सितम्बर, 1973 को विघटित उन बातों के सिवाय हो जायेंगी जो उन्होंने उस तारीख से पूर्व किया था या उनके किये जाने में सोच किया

---

62. अधिनियम सं. 21 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।
63. अधिनियम संख्या 15 सन् 1980 द्वारा संशोधित।

था किन्तु इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को उस तारीख के उपधारा (2) के अधीन कोई ऐसी कार्यवाही करने से, जिसे वह ठीक समझे प्रवासरित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

काशी विद्यापीठ के संबंध में अस्थायी उपबन्ध

[64]72-क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी-

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो काशी विद्यापीठ के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के ठीक पूर्व की तारीख को (कुलाधिपति से भिन्न) उसके किसी अधिकारी के रूप में पद धारण कर रहा हो, अवधि के सिवाय उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर, तब तक जब तक कि खण्ड (ख) के अधीन नई नियुक्तियाँ न कर दी जायें, इस रूप में उसी प्रकार पद धारण करता रहेगा जिन पर कि वह उक्त तारीख को धारण कर रहा था ;

(ख) इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी और उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन ऐसी रीति से करेगी, जिसे वह उचित समझे ऐसा होने पर खण्ड(क) में निर्दिष्ट तत्सम अधिकारी पद पर न रह जायेंगे और तत्सम प्राधिकारियों का तत्काल विघटन हो जायेगा ;

[65](ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य 31 दिसम्बर, 1981 तक या खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो पद धारण करेंगे ;

(घ) (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति

64. अधिनियम सं. 29 सन् 1974 द्वारा बढ़ाया गया।
65. अधिनियम सं. 15 सन् 1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ग) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

[65a] **72-ख.** 25 अप्रैल 1989 से इस अधिनियम में गढ़वाल विश्वविद्यालय से संदर्भित कोई भी विषय, नियम, अधिनियम, अध्यादेश, विधिक प्रकरण या थोड़े ही समय के लिए लागू कोई नियम या दस्तावेज या गतिविधि को हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बन्धित माना जायेगा।

गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अस्थायी व्यवस्था

72-ग. 17 जनवरी 1994 से इस अधिनियम में मेरठ विश्वविद्यालय से संदर्भित कोई भी विषय, नियम, अधिनियम, अध्यादेश, विधिक प्रकरण या थोड़े ही समय के लिए लागू कोई नियम या दस्तावेज या गतिविधि को चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बन्धित माना जायेगा।

मेरठ विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अस्थायी व्यवस्था

72-घ. (1) 18 जून 1994 से इस अधिनियम में अवध विश्वविद्यालय से संदर्भित कोई भी विषय, नियम, अधिनियम, अध्यादेश, विधिक प्रकरण या थोड़े ही समय के लिए लागू कोई नियम या दस्तावेज या गतिविधि को डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद से सम्बन्धित माना जायेगा।

अवध विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अस्थायी व्यवस्था

(2) 11 जुलाई 1995 से इस अधिनियम में डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद या अवध विश्वविद्यालय से संदर्भित कोई भी विषय, नियम, अधिनियम, अध्यादेश, विधिक उपकरण, या थोड़े ही समय के लिए लागू कोई नियम या कोई दस्तावेज या गतिविधि को डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बन्धित माना जायेगा।

65a. उत्तर प्रदेश राज्य वि. वि. (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 द्वारा प्रतिस्थापित

काशी विद्यापीठ के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अस्थायी व्यवस्था

72-ङ. 11 जुलाई, 1995 से इस अधिनियम में काशी विद्यापीठ से संबंधित किसी भी नियम, अधिनियम, अध्यादेश, विधिक प्रकरण या अस्थायी रूप से थोड़े ही समय के लिए लागू कोई नियम, दस्तावेज, या गतिविधि को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से सम्बन्धित माना जायेगा।

आगरा और कानपुर विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के संबंध में अस्थायी व्यवस्था

72-च. (1) 24 सितम्बर, 1995 से इस अधिनियम में आगरा और कानपुर विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी विषय, नियम, अधिनियम, विधिक प्रकरण या थोड़े ही समय के लिए लागू कोई नियम, दस्तावेज या गतिविधि को क्रमशः डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा तथा श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बन्धित माना जायेगा।

(2) उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1997 के प्रारम्भ की तिथि से इस अधिनियम में कानुपर विश्वविद्यालय या श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बन्धित कोई भी विषय, नियम, अधिनियम, विधिक प्रकरण या थोड़े ही समय के लिए लागू कोई नियम, दस्तावेज या गतिविधि को क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बन्धित माना जायेगा।

गोरखपुर तथा रूहेलखंड विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के संबंध में अस्थायी व्यवस्था

72-छ. उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ की तिथि से इस अधिनियम में गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा रूहेलखंड विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी विषय, नियम, अधिनियम, विधिक प्रकरण या थोड़े ही समय के लिए लागू कोई नियम, दस्तावेज या गतिविधि को क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर तथा महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से संबंधित माना जायेगा।

72-ज. उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1999 के प्रारम्भ की तिथि से इस अधिनियम में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबन्धित कोई भी विषय, नियम, अधिनियम, विधिक प्रकरण या थोड़े ही समय के लिए लागू कोई नियम, दस्तावेज या गतिविधि को वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बन्धित माना जायेगा। **पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन विषयक अस्थायी व्यवस्था**

73. (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टत: धारा 74 द्वारा निरसित अधिनियमितियों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे; **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति**

[65b]परन्तु 31 दिसम्बर, 1982 के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

74. (1) निम्नलिखित अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा क्रमश: उन तारीखों से निरसित की जा रही है जिन तारीखों को यह अधिनियम विद्यमान सम्बद्ध विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रवृत्त किया गया है :- **कतिपय अधिनियमितियों का निरसन**

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920,

65b. अधिनियम संख्या 25 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1921,

(ग) आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926,

(घ) गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956,

(ङ) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1965, और

(च) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965

[66](2) ऐसे निरसन के होते हुए भी -

(क) किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियाँ, जारी किये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियाँ या डिप्लोमा अथवा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बातें (जिनके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उप-बन्धों के अधीन क्रमशः की गयी, जारी किये गये, प्रदत्त, मंजूर किये गये या की गई समझी जायगी, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा अधिक्रान्त न कर दिये जायें प्रवृत्त बनी रहेगी।

(ख) चयन समितियों की ऐसी सभी कार्यवाहियाँ, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई तथा ऐसी चयन समितियों की संस्तुतियों के सम्बन्ध में यथास्थिति, प्रबन्धतंत्र या कार्य परिषद् द्वारा ,की गयी सभी कार्यवाहियाँ, जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो,

66. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

इस बात के होते हुए भी चयन की प्रक्रिया में इस अधिनियम द्वारा परिष्कार कर दिया गया है, विधिमान्य समझी जायेंगी, किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रेसर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायगी और उसी प्रक्रम में जारी रखी जायेगी जहाँ वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी।

(3) इस अधिनियम की उपधारा (1) और उपधारा (2) या किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी –

(क)[67]

(ख)[68]

(ग) जहाँ किसी संस्था ने आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के लिए आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926 के उपबन्धों के अनुसार 18 जून, 1953 से पूर्व आवेदन किया है और ऐसा आवेदन उक्त तारीख को लम्बित था और जहाँ यह संस्थान स्थित है, वह स्थान इस अधिनियम के अधीन आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर पड़ता है तो ऐसा आवेदन आगरा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ऐसे निपटाया जा सकेगा मानो वह संस्थान उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाता है और कुलाधिपति द्वारा ऐसा आवेदन मन्जूर किए जाने पर वह संस्था उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएगी जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर, जैसा कि धारा 5 में विनिर्दिष्ट है, संस्थान स्थित होगा ;

(घ) जब तक कि धारा 31 की उपधारा (5) के अधीन विशेषज्ञों का नया पैनल तैयार नहीं किया जाता तब तक, यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति उस धारा

---

67. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा निकाला गया।

68. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा निकाला गया।

के अधीन चयन समिति के विशेषज्ञों को उन पैन
में से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठ
पूर्व विद्यमान हों, नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा।

[69]परन्तु यह कि उक्त उपधारा (5) के स्पष्टीक
1 तथा 2 के उपबन्ध इस खण्ड में निर्दिष्ट विशे
के पैनल तथा इस खण्ड के अधीन ऐसे पैनलों
से किये गये नाम-निर्देशनों पर भी लागू होंगे;

(ङ) जब तक किसी विश्वविद्यालय में कोई वित्त अधिक
नियुक्त नहीं किया जाता तब तक इस अधिनियम
अधीन वित्त अधिकारी के कृत्य कुलाधिपति द्वारा
निमित्त नाम-निर्दिष्ट संकाय के संकायाध्यक्षों
पालन किए जायेंगे ;

(च) जब तक कि धारा 17 के अधीन नियम नहीं
दिए जाते तब तक कुलसचिव, उपकुलसचिव
सहायक कुलसचिव के पद, की कोई रिक्ति, कुलस
के पद की दशा में कुलाधिपति द्वारा और उपकुलस
या सहायक कुलसचिव की दशा में कुलपति
अस्थायी आधार पर भरी जा सकेगी।

[70](छ) वाराणसी जिले में स्थित काशी नरेश गवर्न
डिग्री कालेज, ज्ञानपुर या गवर्नमेंट डिग्री काले
जखनी अथवा देहरादून जिले में स्थित गवर्नमेंट डि
कालेज, ऋषिकेश के प्रत्येक ऐसे छात्र को, जो

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973
प्रारम्भ के ठीक पूर्व आगरा विश्वविद्यालय की वि
उपाधि के लिए अध्ययन कर रहा था; या

(2) उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए
वर्ष 1973-74 के दौरान उक्त महाविद्यालयों में
किसी महाविद्यालय के छात्र के रूप में प्रविष्ट
या

---

69. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा बढ़ाया गया।
70. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) वर्ष 1974 में, या भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष 1975 में[71] अथवा वर्ष 1976 में उक्त विश्वविद्यालय को किसी उपाधि परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो ;

आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्य-विवरण के अनुसार अपना पाठ्य-क्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायगी और आगरा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के शिक्षण तथा उनकी परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जायगा और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

(ज) जब तक कि धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों में संकायों का गठन न हो जाय, धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :

(1) प्रबन्धतंत्र का अध्यक्ष अथवा उसके नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध-तंत्र का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा ;

(2) प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य ; और

(3) तीन विशेषज्ञ जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

[72](झ) गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे आगरा विश्वविद्यालय ने काशी नरेश गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से 1974 की बी. ए. भाग 1 या एम. ए. भाग 1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी थी और जिसे उक्त परीक्षाफल पर सफल घोषित किया गया है, उसे आगरा विश्वविद्यालय विद्या वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान काशी नरेश गवर्नमेंट

अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से उत्त विश्वविद्यालय की यथास्थिति, बी. ए. भाग 2 य एम. ए. भाग 2 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा देगा और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वार उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्ष विधिमान्य समझी जायेगी;

(अ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले किस व्यक्ति को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा (जि आगे इस खण्ड में उक्त विश्वविद्यालय कह गया है) धारा 7 के खण्ड (5) में निर्दि परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जा सकेगी औ ऐसे परीक्षाफल पर उक्त विश्वविद्यालय द्वा उपाधि प्रदान की जा सकेगी, यद्यपि ऐसा व्यक्ति उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में नहीं रहता था

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 का संशोधन

75. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्ध उपबन्ध) अधिनियम, 1965 की धारा 3 में "दो मास" शब्द के स्थान पर 'छ: मास' शब्द रखे जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां

76क. (1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 (1973 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1) एतद्द्वा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधी की गई कोई बात या कार्यवाही धारा 72 की उपधारा (3) उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन ऐसे व गई मानी जाएंगी मानो यह अधिनियम, 1973 के जून के 18 दिन प्रारम्भ हुआ था।

ख-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के धीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा थासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत ार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के पबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

अनुसूची
(धारा 5 देखिए)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	2	3
1	लखनऊ विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय के दीक्षान्त हाल से चारों और सोलह किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र।
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय के दीक्षान्त हाल से चारों और सोलह किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र।
[73]3	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	
	(1) रुहेलखंण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	आगरा, अलीगढ़, बरेली, बिजनौर, बदायूं, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहाँपुर जिले
	(2) रुहेलखंण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी तथा मथुरा जिले।
4	पं. दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर	
	(1) पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, तथा वाराणसी जिले।

73. अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	2	3
	(2) पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	बस्ती, देवरिया, और गोरखपुर, जिले।
[74](5)	क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	
	(1) बुन्देलखण्ड तथा अवध विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झाँसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले। इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा में पड़ने वाले क्षेत्र को छोड़कर
	(2) अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर, किन्तु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक	इलाहाबाद, बाँदा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झाँसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले। इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय

74. अधिनियम संख्या 21 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	2	3
	(3) अवध विश्वविद्यालय की तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो जाने पर।	इलाहाबाद, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव के जिले। इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय
6.	चौधरी चरन सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले।
7.	कुमायूं विश्वविद्यालय	अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिले।
8.	हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल	चमोली, देहरादून, गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले।
9.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	बाँदा, हमीरपुर, ज़ालौन, झाँसी तथा ललितपुर जिले।
10.	डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद	बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिले।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	2	3
11.	महात्मा ज्योतिबाफुले विश्वविद्यालय, रुहेलखण्ड बरेली	बदायूं, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहाँपुर जिले।
12.	वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल, विश्वविद्यालय, जौनपुर	आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, और वाराणसी जिले।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974)

अध्याय 4

अस्थायी उपबन्ध

कठिनाइयों को दूर करना

28. (1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को, विशिष्टतः बुन्देलखण्ड, अवध, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालयों अथवा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना और उनके कृत्य के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि अध्याय 2 तथा 3 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्ध ऐसी कालावधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्तन या लोप के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगे :

प्रतिबन्ध वह है कि [75]31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

---

75. अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

The Uttar Pradesh Universities (Provisions Regarding Conduct of Examinations) Act, 1965 (U.P. Act XXIV of 1965 as amended by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973)

An Act to make provision for certain matters in connection with the conduct of examination by certain Universities in Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows :

1. Short title and extent :- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Universities (Provisions Regarding Conduct of Examinations) Act, 1965.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2. Definitions :- In this Act, unless the context otherwise requires -

(a) "Centre' means any institution, or part there of, or any other place, fixed by the University for the purposes of holding its examinations and includes the entire premises attached there to,

(b) "Invigilator" means a person who assists the Superintendent of a center in conducting and supervising an examination at a centre,

(c) "Superintendent of a Centre" means a person appointed by the University to conduct and supervise its examinations held or to be held at a centre, and includes an Additional Superintendent or Associate Superintendent of such centre ;

(d) "University" means any University established by or under an Uttar Pradesh Act and declared by the State Government by Notification in the Gazette to be a University to which this Act applies.

3. Superintendents and invigilators to be public servant - Every Superintendent of a centre and every invigilator shall be deemed to be public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code during the course of an examination or examinations conducted by the University for a period of one month prior to the commencement of and of six months immediately following examination or examinations.

4. Assault, etc. on Superintendent or Invigilator - An assault or use of criminal force to a Superintendent or Invigilator during the period mentioned in Section 3 shall be deemed to be an obstruction voluntarily caused to a public servant in the discharge of his public function punishable under Section 186 of the Indian Penal Code (Act No. XIV of 1860), and shall notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) be cognizable offence.

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

CONTENTS

Sections *Pages*

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application 149
2. Definitions 150

CHAPTER II

THE UNIVERSITIES

3. Incorporation of Universities 155
4. Establishment of new Universities and alternation of the areas or names of Universities 155
5. Territorial exercise of powers 160
6. University open to all classes and creed 161
7. Powers and duties of the University 162

7-A. Additional powers and duties of certain University 165

CHAPTER III

INSPECTION AND INQUIRY

8. Visitation 167

CHAPTER IV

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

9. Officers of the University 171
10. The Chancellor 171
11. The Pro-Chancellor 172
12. The Vice-Chancellor 172
13. Powers and duties of the Vice-Chancellor 177
14. The Pro-Vice-Chancellor 180
15. The Finance Officer 180
16. The Registrar 182

16-A. The Controller of Examination 182

16-B. Duties of Registrar with respect to examiation in certain University. 184
17. Centralisation of Services of Registrars, Deputy Registrars, and Assistant Registrars 184
18. Other Officers 186

Chapter IV A
CO-ORDINATION COUNCIL AND CENTRAL BOARD OF STUDIES

18-A. Co-ordination Council 187
18-B. Central Board of Studies 188
18-C. Secretarial Assistance 191

Chapter V
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

19. Authorities of the University 192
20. Constitution of the Executive Council 192
21. Powers and duties of Executive Council 196
22. The Court 200
23. Powers and duties of the Court 202
24. Meeting of the Court 203
25. Academic Council 203
26. The Finance Committee 204
27. The Faculties 206
28. Admissions Committee 208
29. Examinations Committee 210
30. Other Authorities 211

Chapter VI
APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS AND OFFICERS

31. Appointment of Teachers 212
31-A. Personal promotion of Teachers of University 224
31-AA. Promotion to the post of Associate Professor and Professor 226

31-B. Regularisation of Certain ad hoc appointments 226
32. Contract of appointment of teachers of the University 227
33. Pensions, Provident Fund, etc. 228
34. Limits of additional remunerative work permissible to teachers 228
35. Conditions of service of teachers of affiliated or associated colleges other than those maintained by Government or local authority 229
36. Tribunal of Arbitration 231

CHAPTER VII

AFFILIATION AND RECOGNITION

37. Affiliated College 233
38. Associated Colleges 234
39. Disqualification for membership of management 236
40. Inspection etc., of Affiliated and Associated Colleges 237
41. Constituent Colleges 238
42. Autonomous College 238
43. Working Men's Colleges 239
44. Institutes 239

CHAPTER VIII

ADMISSIONS AND EXAMINATIONS

45. Admission of Students 240
46. Bar of charging any donation, etc., for admission to a College 241
46-A. Contribution and donations to Colleges 241
47. Halls, hostels and delegacy of the University 242
48. Examinations 242

CHAPTER IX

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

49. Statutes 243
50. Statutes how made 245

51. Ordinance 248

52. Ordinance how made 249

53. Regulations 252

CHAPTER X
ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

54. Annual Report 254

55. Accounts and audit 254

55-A. Surcharge 256

CHAPTER XI
REGULATION OF DEGREE COLLEGES

56. Definitions 257

57. Power of the State Government to issue notice 258

58. Authorised Controller 259

59. Clause 58 not applied to minority Colleges 261

60. Duty to deliver possession to the Authorised Controller.... 262

CHAPTER XI-A
PAYMENT OF SALARY TO TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF DEGREE COLLEGES

60-A. Definitions 26

60-B. Payment of salary within time and without unauthorised deductions 264

60-C. Power to inspect 26

60-CC. Supernumerary post of teachers 26

60-D. Procedure for payment of salary in case of certain colleges 26

60-E. Liability in respect of salary 26

60-F. Punishment, penalties and procedure 26

60-G. Finality of orders 26

60-H. Rule-making power 26

CHAPTER XII
PENALTIES AND PROCEDURE

51.	Penalties	....	271
52.	Cognizance by Courts	....	272
53.	Offences by registered societies	....	272

CHAPTER XIII
MISCELLANEOUS

4.	Manner of appointment of officers and members of authorities	....	273
5.	Filling of casual vacancies	....	273
6.	Proceeding not to be invalidated by vacancies, etc.	....	274
7.	Removal from membership of the University	....	274
8.	Reference to the Chancellor	....	274
8-A.	Power of Vice-Chancellor to enforce his order against Management	....	276
9.	Bar of suit	....	277
0.	Mode of proof of University record	....	277

CHAPTER XIV
TRANSITORY PROVISION

1.	Continuation of existing officers of the University	....	278
2.	Constitution of authorities	....	278
2-A.	Transitory provisions regarding Kashi Vidyapith	....	279
2-B.	Transistory provision on change of name of Garhwal University	....	280
2-C.	Transitory provisions on change of name of University of Meerut	....	280
2-D.	Transitory provisions on the change of name of the University of Avadh	....	280
2-E.	Transitory provision on the name of the Kashi Vidyapith	....	281
-F.	Transitory provision on the name of the University of Agra and Kanpur	....	281

72-G. Transitory provisions on the change of names of University of Gorakhpur and University of Rohilkhand.... [illegible]

72-H Transitory provision of change of name of the Purvanchal University 28

73. Power to remove difficulties 28

74. Repeal of certain enactments 28

75. Amendment of U.P. Act XXIV of 1965 28

76. Repeal and Savings 28

The Schedule 29

Provisions regarding conduct Examinations 29

APPENDICES

(I) The Uttar Pradesh State Universities (Centralised) Service Rules, 1975 29

(II) The Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules. 1970 31

(III) Rules for admissions to courses of instruction for degrees in Education in Affiliated or Associated Colleges of State Universities, 1983 31

(IV) The Uttar Pradesh State Universities (Validaiton of Appointments) Act, 1984 34

(V) The Uttar Pradesh State Universities (Reservation in Admission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Order, 1994) 3

(VI) Notification 3

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, विधेयक, 1994 3

Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, Act, 1994 3

The U.P. State Universities (Centralised) Service Rules 1975

No. 3457 (2)/XVI-V.I.51-74

Dated Lucknow September 25, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vishwavidyalaya (Punah Adhiniyaman Tatha Sanshodhan) Adhiniyam, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 22, 1974.

THE UTTAR PRADESH UNIVERSITIES (RE-ENACTMENT AND AMENDMENT) ACT, 1974

(U.P. Act No. 29 of 1974)

[AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 and to re-enact the same with certain modifications.

It is Hereby enacted in the Twenty-fifth year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title, commencement and application

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette* appoint and different dates may be appointed in relation to

different existing Universities and references to commencement of this Act in relation to an existing University shall be construed as the date on which this Act comes into force in relation thereto.

(3) In its application to the Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya (which after the coming into force of this Act in relation to that University shall called the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya), the State Government may[1] from time to time by notification in the *Gazette*, make such exceptions or modifications not affecting the substance, in the provisions of this Act, as the circumstances may require.

(b) [2][* * *]

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(1) "Academic Council" "Court" and "Executive Council" mean respectively the Academic Council, the Court and the Executive Council of the University ;

(2) "Affiliated College" means an institution affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act and Statutes of that University;

(3) "area of the University" means the area specified in respect of the University by or under Section 5 or Section 4 s the case may be ;

(4) "associated college" means any institution recognised by the University and authorised

1. *Ins.* by U.P. Act 21 of 1975, S.2.
2. *Omitted* by U.P. Act 29 of 1974, S.4.

under the provisions of [3]this Act and the statutes of the University to provide for the teaching necessary for admission to a degree of University ;

(5) "autonomous college" means an affiliated or associated college declared as such in accordance with the provisions of Section 42;

[4](5A) the expression "other backward classes of citizens" shall have the same meaning as in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

[5](5B) "Central Board of Studies" means the Central Boards of Studies referred to in Section 18 B";

(6) "constituent college" means an institution maintained by the University or by the State Government and named as such by the Statutes ;

[6](6A) "Co-ordination Council" means the Co-ordination Council constituted under Section 18-A".

(7) "Director" in relation to an Institute, means the head of such Institute ;

Subs. by U.P. Act 29 of 1974 for the words "this Act", S.5.
Ins. by U.P. Act 20 of 1994, S.2 (w.e.f. 15-7-1994).
Ins. by President's Act 4 of 1996, S.2 (a) (w.e.f. 11-7-1995).
Ins. by President's Act 4 of 1996, S.2 (b) (w.e.f. 11-7-1995).

(8) "existing University" means the University of Lucknow, Allahabad, Agra, [7][which shall from September 24, 1995 be called Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra], Gorakhpur, [8][which shall with effect, from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act 1997 be called Deen Dayal Upadhaya, Gorakhpur University, Gorakhpur] Kanpur [9][which shall be called Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur with effect form September 24, 1995 and Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1997] or Meerut [10][which shall from January 17, 1994 be called Chaudhary Charan Singh University, Meerut] or the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, as the case may be ;

(9) "faculty" means a faculty of the University ;

[11](9A) "Foundation Course" means a course of greater awareness of oneself and of the social, cultural and natural environment."

---

7. *Ins.* by President's Act 4 of 1996. S.2 (c) (w.e.f. 23-9-1995).

8. *Ins.* by U.P. Act 18 of 1997, S.2 (w.e.f. 16-8-197).

9. *Subs.* by U.P. Act 12 of 1997, S.2.

10. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1994, S.2 (w.e.f. 17-1-1994).

11. *Ins.* by President's Act 4 of 1996. S.2 (d) (w.e.f. 11-7-1995).

(10) "hall (or college) of a University" means a unit of residence for students maintained or recognised by the University at which provision is made for imparting tutorial and other supplementary instructions ;

(11) "hostel of a University" means a unit of residence for students maintained or recognised by the University, other than a hall, and "hostel of an affiliated or associated college" mean a unit of residence for students of that college ;

(12) "Institute" means an Institute established by the University under Section 44;

(13) "management" in relation to an affiliated or associated college, means the managing committee or other body charged with managing the affairs of that college and recognised as such by the University;

[12][Provided that in relation to say such college maintained by a Municipal Board or Nagar Mahapalika, the expression, "Management", means the Educations Committee of such Board or Mahapalika, as the case may be and the expression "Head of the Management" means the Chairman of such Committee.]

(14) "prescribed" means prescribed by the Statute ;

(15) "Principal" in relation to an affiliated, associated or a constituent college, means the head of such college;

12. *Ins.* by U.P. Act 12 of 1978, S. 1.

(16) "registered graduate" means a graduate of the University registered under the provisions of this Act or under any enactment repealed by this Act ;

(17) "Statutes" "Ordinances" and "Regulations" means respectively the Statutes, Ordinances and Regulation of the University;

(18) "teacher" means a person employed [13][for imparting instruction or guiding or conducting research in the University or in an Institute or in a constituent, affiliated or associated college] and includes a Principal or a Director;

(19) "teacher of the University" means a teacher employed by the University for imparting instruction and guiding or conducting research either in the University or in an Institute or in constituent college maintained by the University;

(20) "University" means an existing University or a new University established after the commencement of this Act under Section 4;

(21) "Working Men's College" means an affiliated or associated college recognised as such in accordance with the provisions of Section 43.

---

13. *Subs.* by U.P. Act 29 of 1974, S.5 for the words "by the University or by a constituent, affiliated or associated college for imparting instruction or guiding or conducting research".

CHAPTER II

THE UNIVERSITIES

Incorporation of Universities

3. (1) The Chancellor, the Vice-Chancellor and the members of the Executive Council, the Court and the Academic Council for the time being holding office as such in any University shall constitute a body corporate by the name of that University.

(2) Each University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name.

Establishment of new Universities and alteration of the areas or names of Universities

4. (1) With effect from such date as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint in that behalf, there shall be established a University of Kumaun at Nani Tal and a University of Garhwal [14][which shall from April 25, 1989 be called the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University] at Srinagar (District Garhwal) for the areas respectively specified in the Schedule.

[15](1-A) With effect from such date or dates as the State Government may be notification in the *Gazette* appoint in this behalf, there shall be established –

(a) a University of Bundelkhand at Jhansi.

(b) a University of Avadh at Faizabad; [16][which shall be called the Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad with effect from June 18, 1994, and the Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad

---

14. *Ins.* by U.P. Act 26 of 1989, S. 2 (w.e.f. 24-4-1989).
15. *Ins.* by U.P. Act 29 of 1974, S. 6.
16. *Subs.* by President's Act 4 of 1996, S.3 (a) (w.e.f. 11-7-1995).

with effect from July 11, 1995];[* * *][17]

(c) a University of Rohilkhand at Bareilly [18][which shall with effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act 1997 be called Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly];

[19][(d) a University to be known as Purvanchal University at Jaunpur, which shall, with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1999, be called "Vir Bahadur Singh" Purvanchal University, Jaunpur];

for the areas respectively specified in the Schedule.

(1-B) In relation to the universities to be established under sub-section (1-A) –3

(a) the State Government shall appoint interim officers of the Universities (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of such Universities in such manner as it thinks fit;

[20][(b) the officers appointed and members of the authorities constituted under clause (a) shall hold office [* * * * *][21] until the appointment of officers or the constitution of the authorities

---

17. *Omitted* by U.P. Act 19 of 1987.
18. *Ins.* by U.P. Act 18 of 1997, S.3 (w.e.f. 16-8-1997).
19. *Subs.* by U.P. Act 11 of 1999 S.2 (w.e.f. 8-1-1999).
20. *Subs.* by U.P. Act 12 of 1978 S.3.
21. *Deleted* by U.P. Act 19 of 1978.

in accordance with clause (c) [22][or such other earlier date as may be specified by the State Government in this behalf];

[23][Provided that the State Government may, by notification, extend the term of the members of such authorities for a period not exceeding one year.]

(c) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of such Universities in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under clause (b).]

(2) With effect from such date as the State Government may, by notification in the *Gazette* appoint in that behalf of the institution known as Kashi Vidyapith at Varanasi shall be deemed to be a University established under the provisions of this Act, [24][which shall be called Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi with effect from July 11, 1995].

(3) As from the date appointed under sub-section (2)–

(i) The society known as the Kashi Vidyapith, Varanasi, shall be dissolved, and all property movable and immovable, and rights, powers and privileges of the society shall be transferred to and vest in the University and

---

22. *Subs.* by U.P. Act 19 of 1978.

23. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977 S.2.

24. *Ins.* by President's Act 4 of 1996, S.3(b) (w.e.f. 11-7-1995)

shall be applied to the objects and purposes for which the University is established ;

(ii) all debts, liabilities and obligations of the said society shall be transferred to this University and shall thereafter be discharged and satisfied by it ;

(iii) all references in any enactment to the said society shall be constructed as reference to the university;

(iv) any will, deed or other document; whether made or executed before or after the commencement of this Act, which contains any request, gift or trust in favour of the said society shall be construed as if the University was therein named instead of such society ;

(v) Subject to the provisions of this Act, every person employed immediately before the siad date in the said society shall with effect from the date, become an employee of the University by the same tenure and upon the same conditions of service or conditions as a similar thereto as changed circumstances may permit, as he would have held under the said society, if such notification had not been issued.

(4) The State Government may, be notification in the *Gazette* –

(a) increase the area of a University ;

(b) diminish the area of a University ; or

(c) after the name of a University ;

Provided that no such notification shall be issued except with the previous approval by resolution, of both the Houses of the State Legislature.

(5) Any notification under this section may contain such provisions for the amendment of the Schedule and the Statutes, Ordinances and Regulations of the University or Universities affected by such notification, as may be necessary to give effect to the provisions of the notification, and thereupon the Schedule and such Statutes, Ordinances and Regulations shall stand amended accordingly.

(6) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (5), any notification under this section may provide for the following matters, namely -

(a) provisions in respect of representation of various interest of classes of persons in the authorities of the University or Universities affected by the said notification ;

(b) provisions for exercise of option by registered graduates of any then existing University to continue to remain registered graduates of same University or to get registered with a newly established University so, however, that no person shall be registered graduate of more than one University;

(c) Such other supplement, incidental and consequential provisions as the State Government may deem necessary.

Explanation – For the purposes of this section and Section 5 "Kashi Vidyapith" means the institution known

as Kashi Vidyapith at Varanasi established and administered by the Society known as Kashi Vidyapith registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in respect of which the Nirikshak Sabha of the said Society has passed a resolution on 28th May, 1972 requesting the State Government to take over the entire movable and immovable properties of the said institution and to convert it into a State University.

Territorial exercise of powers

5. (1) Save as otherwise provided by under this Act, the powers conferred on each University (other than the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya and the Kashi Vidyapith) shall be exercisable in respect of the area for the time being specified against it in the Schedule.

(2) The Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyala... may affiliate institutions situated in any part of the territory of India and recognize teachers of, and admit to its examinations candidates from such territory or abroad :

Provided that the Vishvadiyalaya shall not–

(a) affiliate an institution outside Uttar Pradesh; or

(b) recognize any teacher employed in an institution situated outside Uttar Pradesh and maintained by any Government ;

except upon the recommendation of the Government concerned.

(3) Nothing in this Act relating to affiliation or recognition of colleges shall apply to the Kashi Vidyapith.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the powers conferred on the [25][[26][Chhatrapati

25. *Subs.* by President's Act 4 of 1996, S.4(a) (w.e.f. 23-9-1995).

26. *Subs.* for "Shri" U.P. Act 12 of 1997, S.3.

Shahu Ji Maharaj University, Kanpur] in respect of institution and research in the Ayurvedic and Unani systems of medicine and advancement and dissemination of knowledge thereof shall be exercisable throughout Uttar Pradesh.

[27][(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the homeopathic educational or instructional institutions throughout Uttar Pradesh may be affiliated to the [28][Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra or [Chhatrapati][26] Shahu Ji Maharaj University Kanpur]

[29][(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (1) of Section 37, the institutions established or proposed to be established for imparting education or instruction in Western Medical Science as defined in the Indian Medical Degrees Act, 1916, engineering technology or management anywhere in Uttar Pradesh may, subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, be affiliated to any University.]

University open to all classes and creed

6. The University shall be open to all persons irrespective of class or creed, but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a large number of students that may be determined by the Ordinances :

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of students belonging to

---

27. *Ins.* by U.P. Act 14 of 1977, S.9.

28. *Subs.* by President's Act 4 of 1996, S.4(b) (w.e.f. 23-9-1995).

29. *Ins.* by President's Act 4 of 1996, S.4 (c) (w.e.f. 25-8-1995).

[30][the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other Backward classes of citizens.

Powers and duties of the University

7. The University shall have the following powers and duties, namely –

(1) to provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit, and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(2) to admit any college to the privileges of affiliation or recognition or to enlarge the privileges of any college already affiliated or recognised, as the case may be, or to withdraw or curtail any such privilege and to guide and control the work of affiliated and associated colleges;

(3) to institute degrees, diplomas and othe academic distinctions ;

(4) to hold examinations for, and to grant and confer degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons who –

(a) have pursued a course of study in the University, a constituent college or an affiliated college, or associate college; or

(b) have carried on research in the University or in an institutio

30. *Subs.* by U.P. Act 20 of 1994 S.4 (w.e.f. 15-7-1994).

recognised in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances; or

(c) have pursued a course of study by correspondence whether residing within the area of the University or not, and have been registered by the University, subject to such conditions as may be laid down in the Statutes and Ordinances as external candidates; or

(d) are teachers or other employees in the University or in an Institute or in a constituent or affiliated or associated college or in any other educational institutions under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances or are inspecting officers permanently employed in the Department of Education of the State Government, and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances, ; or

(e) are women residing within the area of the University and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and Ordinances; or

(f) are blind and are residing within the area of the University and have carried

on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances.

(5) to hold examinations for and to grant the degree of Bachelor of Arts or Commerce or Master of Arts or Commerce to persons residing within the area of the University who have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances;

(6) to confer honorary degree or other academic distinction in the manner and under conditions laid down in the Statutes ;

(7) to grant such diplomas to, and to provide such lectures and instructions for persons not being students of the University, as the University may determine;

(8) to co-operate or collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;

(9) to institute teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts ;

(10) to recognise teachers for giving instruction in halls ;

(11) to lay down the conditions of affiliation or recognition of colleges and to satisfy itself by periodical inspection and otherwise that those conditions are satisfied;

(12) to institute and award scholarships, fellowships (including travelling fellowship), studentships and prizes in accordance with the Statutes and the Ordinances ;

(13) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for students of University, the Institutes or the constituent or associated colleges affiliated; or

(14) to demand and receive such fees and other charges as may be fixed by the Ordinances;

(15) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of students of the University, the Institute and the constituent or affiliated or associated colleges and to make arrangements for promoting their health;

(16) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto; and

(17) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be requisite in order to further the objects of the University.

Additional powers and duties of certain University

[31][7-A. Upon being authorised by the State overnment by notification under the Uttar Pradesh omoeopathic Medicine Act, 1951, [32][Doctor Bhimrao mbedkar University, Agra or [Chhatrapati][33] Shahu Ji

Ins. by Act 14 of 1977, S. 10.

Subs. by President's Act 4 of 1996, S.5 (w.e.f. 23-9-1995).

Subs. for "Shri" bY U.P. Act 12 of 1997, S.3.

Maharaj University, Kanpur, as the case may be, shall –

(a) hold examinations for and grant diplomas in Homoeopathy;

(b) take over the functions of holding of examinations for courses prescribed by the Board of Homoeopathic Medicine constituted under the said Act and granting diplomas and shall exercise and perform al the powers and functions of such Board under the said Act with respect to holding of such examinations and granting of diplomas.]

CHAPTER III

INSPECTION AND INQUIRY

8. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University or any constituent college or any Institute maintained by the University, including its buildings, Libraries, laboratories, workshops and equipment and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University or such colleges or Institute or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University or such college or such Institute. **Visitation**

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such :

Provided that no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the University at such inspection on inquiry.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects,

and shall be deemed to be a civil court within the meaning of [34][Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973], and any proceeding before him or them shall be deemed to judicial proceeding within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(6) If the University authorities do not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

14. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1977, S.3.

(8) Without prejudice to the provisions of sub-section (6) if the Chancellor on consideration of any document or material referred to in sub-section (7) of this section including any report of an inquiry held before the commencement of this Act, is of opinion that the Executive Council has failed to carry out its functions or has abused its powers, he may, after giving it an opportunity of submitting a written explanation, order that in supersession, of the said Executive Council, an *ad hoc* Executive Council, consisting of the Vice-Chancellor and such other persons not exceeding ten in number as the Chancellor may appoint in that behalf including any member of the superseded Executive Council, shall for such period not exceeding two years as the Chancellor may from time to time specify, and subject to the provisions of sub-section (11), exercise and perform all the powers and functions of the Executive Council under this Act.

(9) Nothing in Section 20 shall apply to the composition of the *ad hoc* Executive Council that may be constituted under sub-section (8).

(10) Upon an order being made under sub-section (8), the term of office of all members of the Executive Council superseded thereby, including *ex officio* members, shall cease and all such members shall vacate their offices as such.

(11) During the period of operation of an order under sub-section (8), the provisions of this Act, shall have effect subject to the following modifications, namely –

(a) in Section 20, after sub-section (5), the following sub-section shall be deemed inserted :

"(6) A meeting of the Executive Council shall be held at least once every two months";

(b) in Section 21, in sub-section (1), after the words 'subject to the provisions of this Act', the words 'and subject also to the control of the Chancellor shall be deemed inserted;

(c) in Section 24, in sub-section (2), the words 'and shall upon a requisition in writing signed by not less than one-fourth of the total membership of the Court' shall be deemed *omitted.*

(12) A fresh Executive Council shall be constituted in accordance with the provisions of Section 20 with effect from the expiration of the period of operation of an order under sub-section (8).

(13) Any Statute, Ordinance, Regulation or other rules made during the period of operation of an order under sub-section (8), in accordance with the provisions of this Act, as deemed modified by virtue of the provisions of sub-section (11) shall, notwithstanding the expiration of such period, continue in force until amended, repealed or rescinded in accordance with the provisions of this Act.

CHAPTER IV

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

Officers of the University

9. The following shall be the officers of the University-

(a) the Chancellor;

(b) in the case of Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya only, the Pro-Chancellor,

(c) the Vice-Chancellor;

(d) in the case of Universities referred to in sub-section (1) of Section 14, the Pro-Vice-Chancellor ;

(e) the Finance Officer;

(f) the Registrar;

[35](ff) the Controller of Examinations, if any appointed.

(g) the Deans of the Faculties;

(h) the Dean of Students Welfare;

(i) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

The Chancellor

10. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and the President of the Court and shall, when present, preside at meeting of the Court and at any convocation of the University.

(2) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the

---

35. *Ins.* by U.P. Act 14 of 1995, S.2 (w.e.f. 25-2-1995).

administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the Statutes.

Pro-Chancellor

11. (1) Maharaja Vibhui Narain Singh of Varanasi shall continue to be the Pro-Chancellor for life of the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya.

(2) The Pro-Chancellor shall, in the absence of the Chancellor, preside at meeting of the Court at any convocation of the Vishvavidyalaya.

(3) The Pro-Chancellor shall have such other powers as may be conferred upon him by or under this Act or the Statutes.

Vice-Chancellor

12. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor except as provided by sub-section (5) or sub-section (10) from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance, with the provisions of sub-section (2).

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members, namely –

(a) One person (not being a person connected with the University, an Institute, a constituent college, an associated or affiliated college or a hall or hostel) to be elected by the Executive Council [36][at least three months before the date on which a vacancy in the

---

36. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S.4.

Office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of his term];

(b) one person who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad including the Chief Justice thereof nominated by the said Chief Justice; and

(c) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convenor of the committee :

[37][Provided that where the Executive Council fails to elect any person in accordance with clause (a) then the Chancellor shall nominate in addition to the person nominated by him under clause (c), one person in lieu of the representative of the Executive Council.]

(3) The Committee shall, as far as may be, at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (7), and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chancellor; submit to the Chancellor the names of not less than three and not more than five persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference.

(4) Where the Chancellor does not consider any one or more of persons recommended by the Committee

37. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S.4.

to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the Committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (3).

(5) If the Committee in the case referred to in sub-section (3) or sub-section (4) fails or is unable to suggest any names within the time specified by the Chancellor, [38][or if the Chancellor does not consider any one or more of the fresh named recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor] another Committee consisting of three persons of academic eminence shall be constituted by the Chancellor which shall submit the names in accordance with sub-section (3).

(6) No act or proceeding of the Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

(7) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office:

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

(8) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-

---

38. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 4 and shall be deemed to have been inserted.

Chancellor shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.

(9) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension insurance or provident fund constituted under Section 33 :

[39][Provided that when any teacher or other employee of any University or any affiliated or associated college is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the provident fund to which he is a subscriber and the contribution of the University shall be limited to what it had been contributing immediate before his appointment as Vice-Chancellor.]

(10) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chancellor shall be the sole judge) the Chancellor may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months as he may specify–

(a) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chancellor,

(b) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5);

(c) any other emergency :

---

39. *Ins.* by U.P. Act 21 of 1975, S. 3 and shall be deemed to have been inserted.

Provided that the Chancellor may, from time to time, extended the term of appointment or any person to the office of Vice-Chancellor under this sub-section, so however, that the total term of such appointment (including the term fixed in the original order) does not exceed one year.

(11) Until a Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (5) or sub-section (10) assumes office, the Pro-Vice-Chancellor, if any, or where there is no Pro-Vice-Chancellor, the senior-most Professor of the University in the case of the University of Gorakhpur and any University mentioned in or specified under Section 38, or the senior-most Principal of an affiliated college in the case of any other University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.

[40](12) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(13) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (12) the Chancellor may order that till further orders –

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the

40. *Ins.* by U.P. Act 20 of 1994, S.5 (w.e.f. 15-7-1994).

emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (8) ;

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

Powers and duties of the Vice-Chancellor

13. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall–

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the University including the constituent colleges and the Institutes maintained by the University and its affiliated and associated colleges;

(b) give effect to the decisions of the authorities of the University ;

(c) in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any convocation of the University;

(d) be responsible for the maintenance of discipline in the University;

[41](e) [be responsible for holding and conducting the University examinations properly at due times and for ensuring that the result of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on proper dates.]

(2) He shall be an *ex-officio* member and Chairman the Executive Council, Acedemic Council and the finance Committee.

Ins. by U.P. Act 5 of 1977, S.5.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-sectior be entitled to vote.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act the Statutes and the Ordinance and he shall, withou prejudice to the powers of the Chancellor [42][unde Sections 10 and 68] possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executiv Council, the Court, the Academic Council and the Financ Committee :

Provided that he may delegate this power to an other officer of the University.

(6) Where any matter [43][other than the appointme of teacher of the University] is of urgent nature requirin immediate action and the same could not be immediatel delt with by any officer or the authority or other body the University empowered by or under this Act to de with it, the Vice-Chancellor may take such action as I may deem fit and shall forthwith report the action taken l him to the Chancellor and also to the officer, authority, other body who or which in the ordinary course wou have dealt with the matter :

Provided that no such action shall be taken by t Vice-Chancellor without the previous approval of t

42. *Subs.* by U.P. Act 29 of 1974, S. 7.
43. *Ins.* by U.P. Act No. 1 of 1992, S.2 (w.e.f. 22.11.1991)

Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances :

Provided further that if the officers, authority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have affect or, as the case may be, take effect in the modified form so however that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor :

Provided also that any person in the service of University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(8) Where the exercise of the power by the Vice-Chancellor under sub-section (6) involves the appointment of an officer [44][* * *], such appointment shall terminate an appointment being made in the prescribed manner or on the expiration of a period of six months from the date of the order of the Vice-Chancellor, whichever is earlier.

44. The words 'or a teacher of the University' *omitted* by U.P. Act No. 1 of 1992 (w.e.f. 22.11.1991).

(9) The Vice-Chancellor shall exercise such othe powers as may be laid down by the Statutes and th Ordinances.

The Pro-Vice-Chancellor

14. [45][(1) This section applies only to the Universitie Lucknow, Allahabad and Gorakhpur and to any othe University specified in that behalf by the State Governmer by notification in the *Gazette*.

(2) The Vice-Chancellor, if he considers necessar may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst th Professors of the University.

(3) The Pro-Vice-Chancellor appointed under su section (2) shall discharge his duties in addition to his duti as a Professor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at th pleasure of the Vice-Chancellor.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall get an honorariu rupees three hundred per month.

(6) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vic Chancellor in respect of such matters, as may be specifi by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time a shall preside over the meetings of the University in t absence of the Vice-Chancellor and shall exercise su powers and perform such duties as may be assigned delegated to him by the Vice-Chancellor.

The Finance Officer

15. (1) There shall be a Finance Officer for t University, who shall be appointed by the State Governme by a notification published in the Official *Gazette*, and remuneration and allowances shall be paid by the Universi

45. For other Universities as specified by the Chancellor *see* Appendi

(2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.

(4) The Finance Officer shall have the duty –

(a) to ensure that no expenditure, not authorised in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investment);

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes of Ordinances;

(c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

(d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.

(5) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(6) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.

(7) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may prescribed.

The Registrar

16. (1) The Registrar shall be a wholetime Officer of the University.

(2) The Registrar shall be appointed in accordance with, and his conditions of service shall be governed by rule made under Section 17.

(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Executive Council, the Court, the Academic Council and the Admission Committee][46] and of every Selection Committee for appointment of teachers of the University, and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for transaction of their business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section be entitled to vote.

[47][(5) * * * *]

(6) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by rules made under Section 17.

The Controller of Examination

[48]**16-A**(1) This section applies only to the Universities of Lucknow, Allahabad, Gorakhpur and Kanpur and

46. *Subs.* by U.P. Act 14 of 1995, S.3 (w.e.f. 25-2-1995).
47. *Omitted* by U.P. Act 14 of 1995, S.3 (w.e.f. 25-2-1995).
48. *Ins.* by U.P. U.P. Act 14 of 1995, S.4 (w.e.f. 25-2-1995).

any other University specified in that behalf by the State Government by notification in the official *Gazette*.

(2) The Controller of Examinations shall be a whole time officer of the University.

(3) The Controller of examinations shall be appointed by the State Government by a notification published in the official *Gazette* and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(4) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* Secretary of the Examinations Committee of the University and shall be bound to place before such Committee all such informations as may be necessary for transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote. He may require, from any office or institute of the University, the production of such return or the furnishing of such information as may be necessary for the discharge of his duties.

(5) The Controller of Examinations shall have administrative control over the employees working under him and have, in this regard all the powers of the Registrar.

(6) Subject to Superintendence of the Examination Committee, the Controller of Examinations shall conduct the Examinations and make all other arrangements therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(7) The Controller of Examinations shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University, except in accordance with the order of the State Government.

(8) While the Controller of Examinations is for any reason unable to act or the office of Controller of Examinations is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of Examination resumes his duties or, as the case may be the vacancy is filled.

Duties of Registrar with respect to examinations in centain Universities

[49][**16-B.** In the universities to which the provisions of Section 16-A do not apply the duties of the Controller of Examinations shall be discharged by the Registrar and with respect to such universities the Registrar shall be deemed to be the Controller of Examinations for the purposes of this Act.

Centralisation of Services of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars

17. (1) The State Government shall by rule made by notification in the Official *Gazette*, provide for the creation of a separate service of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars common to all the universities and regulate the recruitment to and conditions of service of persons appointed to any such service :

[50][Provided that any rules made under this sub-section may be made retrospectively to a date not earlier than October 31, 1975.]

49. *Ins.* by U.P. State Universities (Second Amendment) Act No. 14 of 1995 dated 8.8.1995.

50. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S.6.

(2) When any such service is created, the persons then serving on [51][the administrative posts of Registrars, Deputy Registrars; and Assistant Registrars] if confirmed before May 14, 1973, shall be absorbed in the service finally, and other persons serving on the said posts may, if found suitable, be absorbed in such service either provisionally or finally, and if, in the latter case, any person is not absorbed finally, then his services shall be deemed to have been terminated on payment of one month's salary as compensation.

(3) Where any person referred in sub-section (2) is absorbed in the service, the conditions of service applicable to him shall not be less advantageous than those applicable to him before his absorption, except that he shall be liable to transfer from one University to another :

[52][Provided that such absorption in the service shall not operate as a bar against holding or continuing to hold any disciplinary proceeding against a member of the service in respect of any act committed before the date of such absorption.]

(4) All rules made under this section shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during

51. *Subs.* by U.P. Act 29 of 1974, S.8.

52. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S.6. and to be deemed to have always been *inserted.*

the said period agree to make, so, however, that any such modification of annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Other Officers

18. The powers of officers of the University other than the Chancellor, the Pro-Chancellor, the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the [Finance Officer, the Registrar and the Controller of Examinations, if any, appointed] [53] shall be such as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

---

53. *Subs.* by U.P. Act 14 of 1995, S.5 (w.e.f. 25-2-1995)

[54][CHAPTER IV-A

CO-ORDINATION COUNCIL AND CENTRAL BOARD OF STUDIES

18-A. (1) There shall be a Co-ordination Council which shall consist of Chancellor as its Chairman, and the following other members, namely – **Co-ordination Council**

(i) the Vice-Chancellors of all the Universities;

(ii) the Chairman of the Uttar Pradesh State Council of Higher Education;

(iii) Secretary to the State Government in the Judicial Department;

(iv) Secretary to the State Government in the Finance Department;

(v) Secretary to the Governor;

(vi) Secretary to the State Government in the Higher Education Department who shall be *ex-offico* Secretary of the Co-ordination Council.

(2) Subject to the recommendation of or guidelines issued by the University Grants Commission, the powers and functions of the Co-ordination Council shall be as follows namely –

(a) to recommend common course of study for a Bachellor's Degree;

(b) to recommend in respect of the constitution of a Central Board of Studies for the

54. Chapter IV-A *Ins.* by President's Act 4 of 1996, S.6 (w.e.f. 11-7-1995)

Foundation Course or for each subject or group of subjects;

(c) to recommend ways and means of co-operation in academic programmes amongst the Universities;

(d) to consider and recommend matters of common interest to the Universities.

(3) The Co-ordination Council shall meet at Lucknow or such other place and at such intervals as the Chancellor may determine.

Central Board of Studies

18-B. (1) There shall be Central Board of Studies for Foundation Course or such other subjects or group of subjects as the Chancellor may, on the recommendation of the Co-ordination Council, by order direct.

(2) The Central Board of Studies for Foundation Course shall consist of–

(i) one teacher from each University not below the rank of a Reader or a Principal of an affiliated or associated college, nominated by the Vice-Chancellor; and

(ii) five Educationists who are on the eminent Professor's list of the University Grants Commission nominated by the Chancellor on the recommendation of the Co-ordination Council.

(3) The Central Board of Studies for other subjects or group of subject shall consist of–

(i) Convenor, Board of studies of each University in respect of the subject or group

of subject for which the Central Board of Studies is to be constituted :

Provided that if a University does not have a Board of Studies in the subject or group of subjects, the Vice-Chancellor may nominate any teacher not below the rank of a Reader in the University or a Principal of an affiliated or associated college ;

(ii) One Head of Department in an affiliated or associated College nominated by the Chancellor, teaching the subject upto the Post Graduate level;

(iii) One Head of Department in an affiliated or associated college nominated by the Chancellor teaching the subject upto the Degree level.

(iv) Three experts on the subject who are on the eminent professor's list of the University Grants Commission, nominated by the Chancellor on the recommendation of the Co-ordination Council; and

(v) Two other experts on the subject from outside the State nominated by the Chancellor.

(4) The Chancellor shall nominate the Chairman of the Central Board of Studies–

(i) for foundation course from amongst the members referred to in clause (i) of sub-section (2); and

(ii) for other subject or group of subject, from amongst the members referred to in clauses (i) and (ii) of sub-section (3).

(5) The constitution of the Central Board of studies and the nomination of the members thereon, other than *ex-officio* members, shall be notified by the State Government.

(6) The term of the Central Board of Studies shall be three years from the date of notification referred to in sub-section (5) and the term of the members shall be co-terminus with it :

Provided that the term of office of a member nominated to fill a causual vacancy shall be the remainder of his predecessor's term.

(7) Subject to the recommendations of, or guidelines issued by, the University Grants Commission, the functions of the Central Board of Studies shall be as follows, namely:

(a) Subject to the recommendations of the Co-ordination Council and the approval of the Chancellor, to prescribed the courses of study and examinations, and the academic calender, and to recommend text books and other books for undergraduate level ;

(b) to consider and report on any matter referred to it by the Co-ordination Council, or the Chancellor; and

(c) to perform such other functions consistent with this Act within such time as the Chancellor may, by an order in writing, require it to perform.

(8) In carrying out its functions, the Central Board of Studies may consult such experts also who are not its members.

(9) The recommendations of the Central Board of Studies approved by the Chancellor shall came into force in respect of all Universities in the State with effect from the date as may be notified by the Chancellor.

(10) The Chancellor may at any time suspend, modify or amend any decision of the Central Board of Studies on the ground that it does not fulfil the objectives set out in this section and may direct the Board to consider the matter afresh.

18-C. The Uttar Pradesh State Council of Higher Education constituted under the Uttar Pradesh State Council of Higher Education Ordinance, 1995, shall provide secretarial assistance to the Co-ordination Council and the Central Boards of studies]. **Secretarial assistance**

CHAPTER V
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of the University

19. The following shall be the authorities of the university –

(a) the Executive Council ;

(b) the Court;

(c) the Acedemic Council;

(d) the Finance Committee ;

(e) the Boards of Faculties;

(f) the Selection Committees for appointment of teachers of the University;

(g) the Admission Committee;

(h) the Examination Committee; and

(i) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

Constitution of the Executive Council

20. (1) The Executive Council shall consists of –

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;

(b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

(c) the Deans of two Faculties, by rotation in the manner prescribed;

[55][(d) in the case of Universities of Kumaun and Bundelkhand and the Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra the Chhatrapati

---

55. *Subs.* for claused (d) by U.P. Act. No. 20 of 1999 S.2.

Shahu Ji Maharaj University, Kanpur, the Hamvati Nandan Bahuguna Garhwal University, the Chaudhary Charan Singh University, Meerut, the Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad and the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Barelly, –

(i) one Professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a Dean referred to in clause (c) above, one Reader and one Lecturer of the University to be selected in the manner prescribed;

(ii) three Principals and two other teachers of affiliated colleges, to be selected in the manner prescribed;

and in the case of any other University notified under sub-section (1) of Section 37, four Principals and four other teachers of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed;

(dd) in the case of the Dean Dayal Upadhyaya Gorakhpur University Gorakhpur,–

(i) one Professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a Dean referred to in clause(c) above, one Reader and one Lecturer of the University to be selected in the manner prescribed;

(ii) one representative of Maharana Pratap Shiksha Parishad, Gorakhpur to be elected by the said parishad from amongst its members ;

(iii) three Principals and two other teachers o affiliated colleges, to be selecte in the manner prescribed;]

(e) in the case of University mentioned in or notifie under sub-section (1) of Section 38 –

(i) two professors [other than the Pro-Vice Chancellor or a Dean referred to i clause (c) above], two Readers and tw Lectures of the University, to be selected i the manner prescribed;

(ii) one Principal of an associated college to b selected in the manner prescribed;

(f) four persons to be elected by members of th Court from among such of them as are n enrolled as students of or in the service of th University or an Institute or of a constituen college or an affiliated or associated college c hall or hostel ;

(g) four persons of academic eminence to b nominated by the Chancellor.

[56](h) one person, from amongst the repute industrialists who have made valuab contribution in the field of higher education, be nominated by the State Government :

[57][Provided that one of the persons so nominate shall be a person who is or has been a Judge of the Supren Court or High Court.]

---

56. *Ins.* by U.P. Act 14 of 1955 S.6 (w.e.f. 25-2-1995)

57. *Ins.* by U.P. Act 9 of 1988 S.2 (w.e.f. 15-1-1988)

[58][(2) The term of office of members mentioned in –

(i) clauses (c), (d) and (e) of sub-section (1) shall be one year;

(ii) clause (f) of sub-section (1) shall be three years; and

(iii) [cláuse (g) or (h)][59] of sub-section (1) shall be two years.]

(3) No person shall be a member of the Executive Council under clause (f), clause (g), [or clause (h)][60] of sub-section (1) for more than two consecutive terms.

(4) Notwithstanding anything in sub-section (1), no person shall be elected or nominated as a member of the Executive Council unless he is a graduate.

(5) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Executive Council if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit of any hall or hostel or proctor or tutor for any duties of a similar nature in relation to the University.

Explanation– In this section 'relative' means the relations defined in Section 6 of the Companies Act, 1956 and includes the wife's (or husband's) brother, wife's (or

---

58. *Subs.* by U.P. Act 10 of 1982 (w.e.f. 8-7-1981)

59. *Subs.* by U.P. Act 14 of 1995, S.6 (w.e.f. 25-2-1995)

60. *Subs.* by U.P. Act 4 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995)

husband's) father, wife's (or husband's) sister, brother's son and brother's daughter.

Powers and duties of Executive Council

21. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University and subject to the provisions of this Act, have the following powers, namely —

(i) to hold and control the property and funds of the University ;

(ii) to acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the University;

(iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances;

(iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes ;

(v) to prepare the budget of the University;

(vi) to award scholarshiops, fellowships bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;

(vii) to appoint officers, teachers and othe employees of the University and to defin their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of temporar casual vacancies in their posts;

(viii) [61][* * *] to fix the fees, emoluments an travelling and other allowances of th examiners;

61. *Omitted* by U.P. Act 5 of 1977, S.8.

(ix) [62][Subject to the provisions of Section 37] to admit any college to the privileges of affiliation or recognition or enlarge the privileges of any college already affiliated, recognised or withdraw or curtail any such privilege;

(x) to arrange for and direct the inspection of Institutes, affiliated, associated or constituent colleges, halls, hostels and other places of residence of students;

(xi) to direct the form and use of the common seal of the University;

(xii) to regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and other staff of the University in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(xiii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University, and for that purpose, to appoint such agents as it may think fit;

(xiv) to invest any money belonging to the University (including any income from trust and endowed property) in such stocks, funds, shares or securities as it shall from time to time think fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investment from time to time;

62. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S.8.

(xv) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(xvi) to enter into, vary, carry out, and cancel contracts on behalf of the University;

(xvii) to regulate and determine all other matters concerning the University as well as Institutes, constituent, affiliated and associated colleges in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) No immovable property of the University shall except with the prior sanction of the State Government, be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government, or, with the previous sanction of the State Government, from any other person.

(3) No expenditure in respect of which approval of the State Government is required by this Act or the Statutes or Ordinances shall be incurred except with such approval previously obtained, and no post shall be created either in the University or in any Institute or constituent college maintained by the University except with the prior approval of the State Government [63][or except in accordance with any general or special order of the State Government].

---

63. *Ins.* by U.P. Act 21 of 1975 S.4.

[64][(3-A) The Executive Council may, with the prior approval of the University Grants Commission and the State Government create supernumerary post of a teacher of the University with a view to enabling a teacher who is for the time being holding a responsible position of national importance in India or abroad in education administration or other similar assignments, to retain his lien and seniority as such teacher and also to continue to earn increments in his pay scale during the period of his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits, if any, in accordance with the Statutes :

Provided that no salary shall be payable to such teacher by the University for the period of such assignment.

(4) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University or any Institute or constituent college or affiliated or associated college shall be such as may be approved by the State Government.

(5) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.

(6) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers, and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Boards of Faculties concerned.

(7) The Executive Council shall give the consideration to every resolution of the Court, and take such action thereon as it shall deem fit and report to the Court, the

64. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S.8.

action taken or, as the case may be, the reasons for non-acceptance of the resolution.

(8) The Executive Council may, subject to any conditions laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to officer or any other authority of the University, or to a Committee appointed by it.

The Court

22. (1) The Court shall consist of the following members, namely :

Class I - Ex-officio Members

(i) the Chancellor;

(ii) the members of the Executive Council;

(iii) the Finance Officer;

Class II - Life Members

(iv) in the case of an existing University, every person who was a life member of the Court or Senate immediately before the commencement of this Act;

Class III - Representatives of teachers, etc.

(v) all heads of departments of the University and of constituent colleges maintained by it ;

(vi) the Deans of Faculties of Medicine and Engineering, if they are not members of the Executive Council;

(vii) two representatives of provosts and wardens of hostels and halls of the University and of its constituent colleges and Institutes to be selected by rotation in the manner prescribed;

(viii) all Principals of constituent colleges maintained by the State Government;

(ix) fifteen teachers to be selected in the manner prescribed;

(x) two representatives of the managements of the affiliated or associated colleges to be selected by rotation in the manner prescribed;

Class IV - Registered Graduates

(xi) fifteen representations of registered graduates to be elected, by registered graduates of such standing as may be prescribed from amongst such of them as are not in the service of the University or of an Institute or of a constituent college or in the service or connected with the management of affiliated college, associated college, hall or hostel;

Class V - Representation of Students

(xii) one student from each of the Faculties, who having secured the highest markes in that Faculty at the preceding degree examination of any University is pursuing a course of study for a post-graduate degree or a law or a medical or engineering degree in the University (including an affiliated or associated college);

Cla VI - Nominees of Chancellor

(xiii) [5][* * *]

Omitted by U. P. Act 29 of 1977, S.10.

Class VII – Representatives of the State Legislature

(xiv) two members of the Legislative Council to be elected by it;

(xv) five members of the Legislative Assembly to be elected by it.

(2) The term of office of members of each class, except Classes I, II and V, mentioned in sub-section (1) shall be three years and the term of the members of th said Class V shall be one year.

Powers and duties of the Court

23. The Court shall be an advisory body subject to the provisions of this Act, it shall have the following power and functions, namely –

(a) to review, from time to time, the Broa policies and progammes of the Universit and to suggest measures for the improveme and development of the University;

(b) to consider and pass resolutions on th annual report and the annual accounts of th University and the audit report thereon;

(c) to advice the Chancellor in respect of a matter which may be referred to it for advic and

(d) to perform such other duties and exerci such other functions as may be assigned it by this Act or the Statutes or by t Chancellor.

24. (1) The Court shall meet once a year on a date to be fixed by the Vice-Chancellor and such meeting shall be called the annual meeting of the Court. **Meeting of the Court**

(2) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit, and shall upon a requisition in writing signed by not less than one-forth of the total membership of the Court, convene a special meeting of the Court.

25. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances – **Academic Council**

(a) shall have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standard of instruction, education and research carried on or imparted in the University;

(b) may advice the Executive Council on all academic matters including matters relating to examinations conducted by the University; and

(c) shall have such powers and duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

(2) The Academic Council shall consist of the owing members, namely –

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Deans of all Faculties, if any;

(iii) all Heads of Departments of the University and where there is no department in a

subject in the University, the senior-mo
teacher from affiliated colleges representi
that subject on the Faculty concerned;

(iv) all Professors of the University who are n
Heads of Departments;

(v) the Principals of constituent colleges and t
Directors of Institutes, if any;

(vi) two Professors, from each constitue
college, if any, by rotation in order
seniority to be determined in the mann
prescribed.

(vii) three Principals of affiliated or associat
colleges to be selected by rotation in t
manner prescribed;

(viii) fifteen teacher to be selected in the mann
prescribed;

(ix) the Dean of Students Welfare;

(x) the Librarian of the University ;.and

(xi) five persons of academic eminence to
co-opted in the manner prescribed.

(3) Subject to the provisions of Section [65][66] t
term of office of members other than *ex-officio* memb
shall be such as may be prescribed.

Finance Committe

26. (1) The Finance Committee shall consist of-

(a) the Vice-Chancellor;

66. *Subs.* for '60' by U.P. Act No. 5 of 1977, S.9.

[67][(aa) the Secretary to the State Government in the Higher Education Department;

(aaa) the Secretary to the State Government in the Finance Department;

(b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

(c) the Registrar;

(cc) the Controller of Examinations;][68]

(d) one person, not being a member of the Executive Council or the Academic Council or a person in the service of the University or an Institute or of a constituent college, or a member of the Managing Committee of any affiliated or associated college, or a person in the service of such college, to be elected by the Executive Council; and

(e) the Finance Officer who shall also be the Secretary of the Committee.

[69][(1-A) A member referred to in clause (aa) or use (aaa) of sub-section (1) may, instead of attending meeting of the Finance Committee himself, depute an icer not below the rank of a Joint Secretary to the State vernment and an officer so deputed shall also have the nt to vote;]

(2) The Finance Committee shall advise the cutive Council on matters relating to the administration property and funds of the University. It shall, having

---

Ins. by President's Act 4 of 1996, S.8 (a) (w.e.f. 11-7-1995).
Ins. by U.P. Act 14 of 1995, S.7 (w.e.f. 25-2-1995).
Ins. by President's Act 4 of 1996, S.8 (b) (w.e.f. 11-7-1995).

regard to the income and resources of the University, fi limits for the total recurring and non-recurring expenditur for the ensuing financial year and may for any speci reasons, revise during the financial year the limits c expenditure so fixed and the limits so fixed shall be bindin on the Executive Council.

(3) The Finance Committee shall have such oth powers and duties as may be conferred or imposed on by this Act or the Statutes.

[70][(4) Unless a proposal having financial implicatio has been recommended by the Finance Committee, t Executive Council shall not take a decision thereon, and the Executive Council disagrees with the recommendatio of the Finance Committee, it shall refer the proposal ba to the finance committee with reasons for the disagreemer and if the Executive Council again disagrees with t recommendation of the Finance Committee the matter sh be referred to the Chancellor whose decision thereon sh be final.

The Faculties

27. (1) The University shall have such Faculties may be prescribed.

(2) Each Faculty shall comprise such departme of teaching as may be prescribed and each departme shall have such subjects of study as may be assigned t by the Ordinance.

(3) There shall be a Board of each Faculty, t constitution (including the term of office of its membe and powers and duties of which shall be such as may prescribed.

70. *Ins.* by President's Act 4 of 1996, S.8 (b) (w.e.f. 11-7-1995).

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen from amongst the professors by rotation in order of seniority and shall hold office for three years:

[71][Provided that in the case of a Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Arts College, the Principal of such college shall be the *ex-officio* Dean of Medical, Engineering Ayurvedic or Fine Arts Faculty, as the case may be:]

Provided further that where there is more than one such college, the Deanship of each such Faculty shall rotate amongst the Principals of such colleges:

[72][Provided also that if there is no Professor in the Faculty, the office of Dean shall be held by Readers, and if there are no Readers, then by other teachers in that Faculty, by rotation in order of seniority.]

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of Faculty and be responsible for –

(a) the organization and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the Faculty; and

(b) the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.

[73][(6) In each Department of teaching in the University, there shall be a Head of the Department whose appointment shall be regulated by Statutes:

1. *Subs.* by U.P. Act 29 of 1974, S.11.
2. *Subs.* by U.P. Act of 5 1977, S. 10.
3. *Subs.* by U.P. Act 29 of 1974, S. 11.

Provided that every person holding the office of Head of Department immediately before the date of commencement of this sub-section shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, continue to hold office on the same terms and conditions as he held immediately before the said date.]

(7) The Head of Department shall be responsible to the Dean for the organisation of teaching in the department and have such other powers and duties as may be provided in the Ordinances.

(8) There shall be constituted in accordance with the provisions of the Ordinances, Boards of Studies in respect of different subjects of study and more than one subject may be assigned to one Board of Studies.

Admissions Committee

28. (1) There shall be an Admissions Committee of the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the Ordinances.

(2) The Admissions Committee shall have the power to appoint such number of sub-committees as it thinks fit.

(3) Subject to the superintendence of the Academic Council and to the provisions of sub-section (5), the Admissions Committee shall lay down the principles or norms governing the policy of admission to various courses of studies in the University and may also nominate a person or a sub-committee as the admitting authority in respect of any course of study in an Institute or a constituent college maintained by the University.

(4) Subject to the provisions of sub-section (5) the Committee may issue any direction as respects criteria or

methods of admissions [74][including the number of students to be admitted] to constituent college maintained by the State Government and affiliated or associated colleges, and such directions shall be binding on such colleges.

[75][(5) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act,–

(a) reservation of seats for admission in any course of study in University, Institute, constituent college, affiliated college or associated college for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens may be made and regulated by such orders as the State Government may, by notification make in that behalf:

Provided that reservation under this clause shall not exceed fifty percent of the total number of seats in any course of study :

Provided further that reservation under this clause shall not apply in the case of an institution established and administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution–

(b) admission to medical and engineering colleges and to courses of instruction for degrees in education and Ayurvedic or Unani systems of medicine (including the number of students to be admitted), shall subject to clause (a), be regulated by such orders (which if necessary may be with

74. *Ins.* by U.P. Act 21 of 1975, S.5.

75. *Subs.* by U.P. Act 20 of 1994 S.6 (w.e.f. 15-7-1994).

retrospective effect, but not effective prior to January 1, 1979) as the State Government may by notification, make in that behalf:

Provided that no order regulating admission under this clause shall be inconsistent with the rights of minorities in the matter of establishing and administering educational institutions of their choice–

(c) in making an order under clause (a), the State Government may direct that any person who wilfully acts in a manner intended to contravene, or defeat the purposes of the orders shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding three months or with fine not exceeding one thousand rupees, or with both, as may be specified in the order.

(5-A) Every order made under clause (a) of sub-section (5) shall be laid, as soon as may be, before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

(6) No student admitted to any college in contravention of the provisions of this section shall be permitted to take up any examination conducted by the University, and the Vice-Chancellor shall have the power to cancel any admission made in such contravention.]

Examinations Committee

29. (1) There shall be an Examinations Committee in the University, the constitution of which shall be as may be provided for in the Ordinances.

(2) Except as provided in sub-section (2) of Section 42, the Committee shall supervise generally all examinations of the University, including moderation and tabulation, and perform the following other functions, namely–

(a) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them ;

(b) to review from time to time the results of University examintions and submission of reports, thereon to the Academic Council;

(c) to make recommendation to the Academic Council for the improvement of the examinations system ;

(d) to scrutinise the list of examiner proposed by the Board of Studies, finalise the same and declare the result of the University.

(3) The Examinations Committee may appoint such number of sub-committee as it thinks fit, and in particular may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

[76][(4) Notwithstanding anything contined in this Act, it shall be lawful for an Examinations Committe or, as the case may be, for a sub-committee on any person to whom the Examination Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3), to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination].

30. (1) The constitution, powers and duties of other authorities of the University shall be such as may be prescribed. **Other Authorities**

76. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 11.

CHAPTER VI

APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS AND OFFICERS

Appointment of Teachers

31. (1) Subject to the provisions of this Act, the teachers of the University and the teachers of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government [77][* * *] shall be appointed by the Executive Council or the Management of the affiliated or associated college, as the case may be, on the recommendation of a Selection Committee in the manner hereinafter provided. [78][The Selection Committee shall meet as often as necessary].

(2) The appointment of every such teacher, Director and Principal not being an appointment under sub-section (3), shall in the first instance be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year :

Provided that no order of termination of service during or on the expiry of the period of probation shall be passed –

(a) in the case of a teacher of the University, except by order of the Executive Council made after considering the report of the Vice-Chancellor and (unless the teacher is himself the Head of the Department), the Head of the Department concerned ;

(b) in the case of principal of an affiliated or associated college, except by order of the Management; and

77. Words "or by a local authority" *omitted* by U.P. Act 12 of 1978, S. 10 and wherever occurring in Chapter VI.

78. *Ins.* by U.P. Act 1 of 1992, S.3 (w.e.f. 22-11-1994).

(c) in the case of any other teacher of an affiliated or associated college, except by order of the Management made after considering the report of the Principal and (unless such teacher is the senior-most teacher of the subject), also of the senior-most teacher of the subject :

[79][Provided further that no such order of termination shall be passed except after notice to the teacher concerned giving him an opportunity of explanation in respect of the ground on which his services are proposed to be terminated:

Provided also that if a notice is given before the expiry of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, the period of probation shall stand extended until the final order of the Executive Council under clause (a) of the first proviso or, as the case may be, until the approval of the Vice-Chancellor under Section 35 is communicated to the teacher concerned.

(3) (a) In the case of a teacher of the University other than a Professor, the Vice-Chancellor in consultation with the Dean of the Faculty and the Head of the Department concerned and an expert nominated by the Chancellor in that behalf and in the case of a teacher of an affiliated or associated college, the Management in consultation with an expert nominated by the Vice-Chancellor in that behalf may make officiating appointment in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee, but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference.

79. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 12.

[80](b) Where before or after the commencement of this Act, any teacher is appointed (after reference to a Selection Committee) to a temporary post likely to last for more than six months, and such post in subsequently converted into a permanent post or to a permanent post in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period exceeding ten months and such post subsequently becomes permanently vacant or any post of same cadre and grade is newly created or falls vacant in the same department, then unless the Executive Council or the Management, as the case may be, decide to terminate his services after giving an opportunity to show cause, it may appoint such teacher in a substantive capacity to that post without reference to a Selection Committee :

Provided that this clause shall not apply unless the teacher concerned holds the prescribed qualifications for the post at the time of such substantive appointment, and he has served continuously, for a period of not less than one year after his appointment made after reference to a Selection Committee :

Provided further that appointment in a substantive capacity under this clause of a teacher who had served, before such appointment, continuously for a period of less than two years, shall be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year, and the provisions of sub-section (2) shall apply accordingly.]

[81][(c) Any teacher of the University who was appointed as lecturer on or before June 30, 1991 without reference to the Selection Committee by way of a short

---

80. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 12

81. *Ins.* by U.P. Act 1 of 1992, S. 3 (w.e.f. 22.11.1991)

term arrangement in accordance with the provisions for the time being in force for such appointment, may be given substantive appointment by the Executive Council, if any substantive vacancy of the same cadre and grade in the same department is available on November 22, 1991 if such teacher –

(i) is serving as such on November 22, 1991 continuously since such initial appointment by way of short-term arrangement ;

(ii) possessed on November 22, 1991 the qualifications required for regular appointment to the post under the provisions of the relevant Statute in force on the date of the initial appointment ;

(iii) has been found suitable for regular appointment by the Executive Council.

A teacher appointed by way of short-term arrangement as aforesaid who does not get a substantive appointment under this clause shall cease to hold such post on such date as the Executive Council may specify.]

(4) (a) The Selection Committee for the appointment of a teacher of the University (other than the Director of an Institute and the Principal of a constituent college), shall consist of –

(i) the Vice-Chancellor who shall be the chairman thereof,

(ii) the Head of the Department concerned :

Provided that the Head of the Department shall not sit in the Selection Committee, when he is himself a

candidate for appointment or when the post concerned is of a higher rank than his substantive post and in that even his office shall be filled by the Professor in the Department and if there is no Professor by the Dean of the Faculty :

[82][Provided further that where the Chancellor is satified that in the special circumstances of the case, a Selection Committee cannot be constituted in accordance with the preceding proviso, he may direct the constitution of the Selection Committee in such manner as he thinks fit.]

(iii) in the case of Professor or Reader, three experts, and in any other case, two experts be nominated by the Chancellor;

(iv) in the case of appointment of teachers in a department of a constituent medical college upgraded under any scheme sanctioned by the Central Government, one nominee each of the Central Government and the State Government;

(v) in the case of appointment of teachers of any Institute or constituent college, the Director of the Institute or the Principal of the constituent college, as the case may be.

(b) The Selection Committee for the appointment of the Director of an Institute or the Principal of a constituent college shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;

82. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 12.

(ii) two experts to be nominated by the Chancellor.

(c) The Selection Committee for the appointment of the Principal of an affiliated or an associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government [83][* * *] shall consist of–

(i) the Head of the Management, or a member of the Management nominated by him who shall be the Chairman;

[84][(ii) one of the Deans or Professors of those Faculties which comprise subjects taught in the college, to be nominated by the Vice-Chancellor]

(iii) one member of the Management nominated by the Management; and

(iv) two experts to be nominated by the Vice-Chancellor :

Provided that in the case of appointment of the rincipal of an affiliated college, the Dean of Faculty shall ot sit in the Selection Committee; if he is himself a teacher f that college:

Provided further that in the case of colleges stablished and administered by a minority referred to in ause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the kperts shall be nominated by the Management from out

---

Vords "or l a local authorit" *omitted* by U.P. Act 12 of 1978, S. 10.

Ins. by U.P. Act 12 of 1978.

of a panel of five experts suggested by the Managemen and approved by the Vice-Chancellor:

[85][Provided also that in the case of college referre to in the preceding proviso, the Dean or Professor wh shall be the member of the Selection Committee under sub clause (ii) shall also be nominated by the Management fro out of a panel of five Deans or Professors suggested by th Management and approved by the Vice-Chancellor, and the requisite number of such Deans or Professors is not s available, the panel may include the names of Principals c affiliated or associated colleges.

(d) The Selection Committee for the appointme of other teachers of an affiliated or associated college (oth than a college maintained exclusively by the Sta Government [* * *][86] shall consist of–

(i) the Head of Management or a member the Management nominated by him who sha be the Chairman ;

(ii) the Principal of the college and anoth teacher of the college nominated by t Principal;

(iii) two experts to be nominated by the Vic Chancellor;

[87][Provided that in the case of college where there no Principal or other teacher available for being a memb

---

85. Proviso *inserted* by U.P. Act 5 of 1977, S. 12.
86. Words "or by a local authority" *omitted* by U.P. Act 12 of 1 S. 10.
87. *Ins.* by U.P. Act 29 of 1974, S. 12, and shall be deemed alwa have been inserted.

of the Selection Committee under sub-clause (ii), the remaining members referred to in this clause shall constitute such Selection Committee :]

Provided further that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the experts shall be nominated by the Management from out of a panel of five experts suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor:

(5) (a) A panel of six or more experts in each subject of study shall be drawn up by the Chancellor after consulting the corresponding Faculty in Indian Universities or such academic bodies or research institutions in or outside Uttar Pradesh as the Chancellor may consider necessary. Every expert to be nominated by the Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on such panel.

(b) The Board of each Faculty shall maintain a standing panel of sixteen or more experts in each subject of study, and every expert to be nominated by the Vice-Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on the panel.

(c) A panel referred to in clause (a) or clause (b) shall be revised after every three years.

Explanation 1– For the purposes of this sub-section, a branch of subject in which a separate course of study is prescribed for a post-graduate degree or for Part I or Part II thereof shall be deemed to be a separate subject of study.

Explanation II–Where the post of teacher to b selected is common to more than one subject of study, th expert may belong to either of such subject of study.

[88][(d) The Chancellor or the Vice-Chancellor, as th case may be, may intimate in a specified order, a large number of names of experts than required under sub section (4) for serving as his nominees on the Selectio Committee. In such case, on any person whose nam appears higher in the specified order not being availab for a meeting of the Selection Committee, a person whos name appears nearest lower in the specified order shall b requested to serve on the Committee.]

(6) No recommendation made by a Selectio Committee referred to in sub-section (4) shall be considere to be valid unless one of the experts had agreed to suc selection.

(7) Subject to the provisions of sub-section (6), th majority of the total membership of any Selectio Committee shall form the quorum of such Committee.

[89][Provided that in the case of a professor or Reader, the persons present to form the quorum mu include atleast two experts.]

[90][(7-A). It shall be open to the Selection Committ to recommend one or more but not more than three nam of each post].

(8)(a) In the case of appointment of a teacher of t University, if the Executive Council does not agree with t

---

88. *Ins.* by U.P. Act 29 of 1974, S. 12.
89. *Ins.* by U.P. Act No. 4 of S. 2 (w.e.f. 17-12-1994).
90. *Ins.* by U.P. Act 29 of 1974, S. 12 and shall be deemed alway have been *inserted.*

ecommendation made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor long with the reasons of such disagreement and his decision hall be final :

[91][Provided that if the Executive Council does not ake a decision on the recommendations of the Selection Committee within a period of four months from the date of e meeting of such Committee, then also the matter shall and referred to the Chancellor, and his decision shall be nal.

[92][(aa) Where the failure of the Executive Council to take a decision within the period specified in the proviso to clause (a) is not attribute to any fault of the Executive Council, the Chancellor may require the Executive Council to take a decision within such time as the Chancellor may; from time to time, allow and may direct the Vice-Chancellor to call a meeting of the Executive Council for the purpose :

Provided that –

(i) if the Executive Council does not agree with the recommendations made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement and his decision shall be final;

Ins. by U.P. Act 5 of 1977, S. 12.

Ins. by U.P. Act No. 4 of 1995 S.2 (w.e.f. 17-12-1994).

(ii) if the Executive council does not take decision within the time allowed by t Chancellor, the Chancellor shall decide t matter and his decision shall be final.

(b) In the case of appointment of a teacher of affiliated or associated college, if the Management do not agree with the recommendation made by the Selecti Committee, the Management shall refer the matter to t Vice-Chancellor along with the reasons of su disagreement, and his decision shall be final :

Provided that in the case of appointment of a teac of an affiliated or associated college, established a administered by a minority referred to in clause (1) Article 30 of the Constitution of India. If the Managem does not agree with the recommendation made b Selection Committee, the Management shall have the ri to appoint another Selection Committee and the decis of the Committee shall be final.

(9) The disqualification of members of Select Committee for appointment of teachers of the Univer and the Principals and other teachers of such affiliate associated colleges on the ground of interest for participat in the deliberations of such Committees and other matt relating to appointment of such Principals and teachers s be prescribed by the Statutes.

(10) No selection for any appointment under section shall be made except after advertisement of vacancy in at least three issues of two newspapers hav adequate circulation in Uttar Pradesh.

[93][(11) (a) No teacher recommended by the Selection Committee shall be appointed by the Management of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government) unless prior approval of the Vice-Chancellor has been obtained.

(b) The Management shall, as soon as possible, after the meeting of the Selection Committee, submit the recommendations of the Committee, along with other relevant documents to the Vice-Chancellor for approval.

(c) The Vice-Chancellor, if he is satisfied that the candidate recommended by the Selection Committee does not possess the minimum qualifications or experience prescribed, or that the procedure laid down in the Act for the selection of the teacher has not been followed, shall convey to the management his disapproval :

Provided that if the Vice-Chancellor does not convey his disapproval within a period of one month from the date of receiptof the documents referred to in clause (b), or does not send to the Management any intimation in connection therewith, he shall deemed to have approved of the proposal.

(12) Notwithstanding anything contained in this section, the Executive Council, with the prior approval of the Chancellor, or the Management with the prior approval of the Vice-Chancellor, may appoint on deputation on the post of a teacher any Government servant who possesses the qualifications prescribed for the post.]

(13) The Principal of the King George's Medical College, Lucknow, shall be appointed on the

93. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 12.

recommendation of the Selection Committee constituted under clause (b) of sub-section (4) from amongst the Professors of the said college and the provisions of sub section (10) shall not apply in relation to such selection.

Personal promotion to Teachers of University

[94][**31-A.** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, [95][a Lecturer in the University appointed under Section 31 or a Reader in the Univeristy appointed under Seciton 31 or promoted under this section], who has put in such length of service and possesses such qualifications, as may be prescribed, may be given personal promotion, respectively to the post of Reader or Professor.

(2) Such personal promotion shall be given on the recommendation of the Selection Committee, constitued under clause (a) of sub-section (4) of Section 31, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Nothing contained in this section shall affect the posts of the teachers of the University to be filled by direct appointment in accordance with the provisions of Section 31.]

Promotion to the Post of Associate Professor and Professor

[1][**31-AA.** (1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, an Assistant Professor substantively appointed in the Faculty of Medicine or Dental Sciences of the University of Lucknow or an Associate Professor, substantively appointed, or promoted under this section, in the said Faculties of the said University, who

94. *Ins.* by U.P. Act 9 of 1985 (w.e.f. 10.10.1984).

95. *Subs.* by President's Act 4 of 1996, (w.e.f. 11-7-1995).

1. *Ins.* by U.P. Act 9 of 1998 S.2 (w.e.f. 19-9-1997).

has put in such length of service and possesses such qualifications as may be prescribed, may be given personnel promotion respectively to the post of Associate Professor or Professor

(2) The promotion under sub-section (1) shall be given on the recommendation of the Selection Committee, constituted under clause (a) of sub-section (4) of Section 31 in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Explanation–With regard to the Faculty of Medicine or Dental Sciences of the University of Lucknow, the word "Reader" referred to in clause (a) of sub-section (4) of Section 31 shall be construed as "Associate Professor"]

[2][(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2) or in any other provisions of this Act, every person who was promoted to the post of Associate Professor or Professor in a Faculty referred to in sub-section (1) in accordance with the Order No. 842/15-10-97-11(7)/96, dated April 11, 1997 issued by the State Government and is contiuning in service as such on the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Act 1999 shall be deemed to have been promoted to such post under sub-section (1) from the date of such promotion].

Special provision with regard to appointment

[3][**31-B.** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act or in the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission

2. *Ins.* by U.P. Act 21 of 1999 S.2
3. *Ins.* by U.P. Act 9 of 1998 S.3 (w.e.f. 12-2-1998).

Act, 1980 appointment to the post of principal or teacher at the Motilal Nehru. Regional Engineering College, Allahabad shall be made in accordance with the rules and bye-laws of the Motilal Nehru Regional Engineering College Society Allahabad.

(2) All appointments made before the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1998 in accordnace with the provisions of sub-section (1) shall be deemed to have been made under the said sub-section as if the provisions of the said sub-section were in force at all material times].

Regularisation of certain adhoc appointments

[3a][**31 B-1.** (1) Every teacher, other than a Principal, directly appointed on or before January 3, 1984, on *ad-hoc* basis, against a substantive vacancy in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Removal of Difficulties) Order, 1982 or the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Removal of Difficulties) Order, 1983, who possess the qualification prescribed under, or is exempted for such qualification in accordance with, the provisions of the concerned Statutes, shall with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1985, be deemed to have been appointed in a substantive capacity provided that such teacher has been continuously serving the college from the date of such ad-hoc appointment up to the date of such commencement.

(2) Every teacher deemed to have been associated in a substantive capacity under sub-section (1) shall be deemed to be on probation from the date of such commencement.

3a. *Ins.* by U.P. Act No. 22 of 1985 (w.e.f. 22.6.1985).

(3) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to substantive appointment if –

(a) on the date of such commencement, such post had already been filled, or selection for such post had already been made, in accordance with the provisions of this Act, or

(b) Such teacher was related to any member of the Management, of the Principal, of the college concerned.

Explanation–For the purpose of this sub-section a person shall be deemed to be related to another if they are related in the manner mentioned in the Explanation to Section 20 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

Contract of appointment of teachers of the University

32. (1) Except as otherwise provided by Statutes, no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) The original contract shall be lodged with the Registrar and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(3) In the case of an officer or teacher employed before the commencement of this Act, all contracts in force, immediately before such commencement, shall, to the extent of any inconsistency with the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances be deemed to have been modified by the said provisions.

(4) Notwithstanding anything contained in any contract or other instrument, teachers of any constituent medical college shall not have right of private practice, except to such extent, if any, and subject to such conditions and restrictions as the State Government may, by general or special order specify.

Pensions, Provident Fund, etc.

33. The University and every affiliated or associated college shall constitute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions [4][as may be specified by general or special order by the State Government] such pension, insurance or provident fund, as it may deem fit including a fund from which such teachers or their heirs; as the case may be, shall be paid pension or gratuity in the event of their incurring disability, wound or death in connection with the discharge of their duties as Superintendent of a Centre or invigilator as defined in Uttar Pradesh Universities (Provisions Regarding Conduct of Examinations) Act, 1965.

Limits of additional remunerative work permissible to teachers

34.(1) The conditions regarding payment of remuneration to the teachers of the University or for an affiliated or an associated college for any duties performed in connection with any examination conducted by an Indian University or any body other than Public Service Commission [5][* * *] shall be such as may be prescribed.

(2) No teacher of the University or of an affiliated or associated college shall at any time, hold more than one

4. *Subs.* by U.P. Act No. 21 of 1975, S.2.

5. Words "and the holding of remunerative offices by them" *omitted* by U.P. Act 29 of 1974, S.13.

remunerative office carrying duties other than teaching or duties connected with any examination.

Explanation–The words 'remunerative offices' include the offices of Warden or Superintendent of a Hall or Hostel, Proctor, Games Superintendent, Librarian, and any office in the National Cadet Corps, National Sports Organisation, National Social Service Scheme and University Employment Exchange.

Conditions of service of teachers of affiliated or associated colleges other than those maintained by Government or local authority

35. (1) Every teacher in an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government) [6][* * *] shall be appointed under a written contract which shall contain such terms and conditions as may be prescribed. The contract shall be lodged with the University and a copy thereof shall be given to the teacher concerned, and another copy thereof shall be retained by the college concerned.

(2) Every decision of the Management of such college to dismiss or remove a teacher or to reduce him in rank or to punish him in any other manner shall before it is communicated to him, be reported to the Vice-Chancellor and shall not take effect unless it has been approved by the Vice-Chancellor :

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the decision of the management dismissing removing or reducing in rank or punishing in any other manner any teacher shall not require

6. Words "or by a local authority" *omitted* by U.P. Act 12 of 1978, S. 10.

the approval of the Vice-Chancellor, but shall be reported to him and unless he is satisfied that the procedure prescribed in this behalf has been followed, the decision shall not be given effect to :

(3) The provisions of sub-section (2) shall also apply to any decision to terminate the services of a teacher, whether by way of punishment or otherwise but shall not apply to any termination of service on the expiry of the period for which the teacher was appointed :

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the decision of the Management terminating the service of any teacher shall not require the approval of the Vice-Chancellor, but shall be reported to him and unless he is satisfied that the procedure prescribed in this behalf has been followed, the decision shall not be given effect to.

(4) Nothing in sub-section (2) shall be deemed to apply to an order of suspension pending inquiry, but any such order may be stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor :

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, such order may be stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor only if the conditions prescribed for such suspension are not satisfied.

(5) Other conditions of service of teacher of such colleges shall be such as may be prescribed.

Tribunal of Arbitration

36.(1) Any dispute arising out of a contract of appointment referred to in Section 32 or Section 33 shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of the following members, namely –

(a) in the case of an officer or teacher of the University, one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and one member (who shall act as convener) nominated by the Chancellor ;

(b) in the case of a teacher of an affiliated or associated college, one member nominted by the management of the college, one member nominated by the teacher concerned, and one member (who shall act as convener) nominated by the Vice-Chancellor:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the Convener shall be selected by the nominees of the management and the teacher concerned out of a panel of five persons suggested by the management and approved by the Vice-Chancellor:

Provided further that in the event of their failure to appoint the Convener within the time prescribed, the Vice-Chancellor shall nominate a Convener out of the panel.

(2) If for any reason, a vacancy occurs in the office of a member of the Tribunal, the appropriate person or body concerned shall nominate another person in accordance with the provisions of sub-section (1) to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the

Tribunal from the stage at which the vacancy is filled.

(3) The decision of the Tribunal shall be final and binding on the parties and shall not be questioned in any court.

(4) The Tribunal of Arbitration shall have the power–

(i) to regulate its own procedure;

(ii) to order re-instatement of the officer or teacher concerned; and

(iii) to award salary to the officer or teacher concerned, after deducting therefrom such income which such officer or teacher might have otherwise derived during his suspension, removal, dismissal or termination from service.

(5) Nothing contained in any law for the time being in force relating to arbitration shall apply to an arbitration under this section.

(6) No suit or proceedings shall lie in any court in respect of any matter which is required by sub-section (1) to be referred to the Tribunal of Arbitration :

Provided that every decision of the Tribunal referred to in sub-section (3) shall be executable by the lower court having territorial jurisdiction, as if it were a decree of the court.

CHAPTER VII

AFFILIATION AND RECOGNITION

37. (1) This section shall apply to the Universities of Agra, Gorakhpur, Kanpur and Meerut and such other Universities (not being the Universities of Lucknow and Allahabad) as the State Government may, by notification in the *Gazette*, specify. **Affiliated Colleges**

(2) The Executive Council may, with the previous sanction of the Chancellor, admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject to the provisions of sub-section (8), withdraw or curtail any such privilege.

[7][* * *]

(3) It shall be lawful for an affiliated college to make arrangement with any other affiliated college situated in the same local area, or with the University, for co-operation in the work of teaching or research.

(4) Except as provided by the Act, the management of an affiliated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep, and its Principal shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.

(5) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council or the Vice-Chancellor may call for.

---

7. Proviso *omitted* by U.P. Act 21 of 1975, S. 7.

(6) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more persons authorised by it in that behalf, and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(7) The Executive Council may direct an affiliated college so inspected to take such action as may appear to it to be necessary within such period as may be specified.

(8) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (7) or to fulfil the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college and with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Statutes.

[8][(9) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2) and (8), if the Management of an affiliated college has failed to fulfil the conditions of affiliation, the Chancellor may, after obtaining a report from the Management and the Vice-Chancellor, withdraw or curtail the privileges of affiliation.]

Associated Colleges

38. (1) This section shall apply to the Universities of Lucknow and Allahabad and such other Universities (not being Universities of Agra, Gorakhpur, Kanpur or Meerut or the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalay) as the State Government may, be notification in the *Gazette*, specify.

(2) Associated colleges shall be such as may be named by the Statutes.

---

8. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S.13.

(3) It shall be lawful for an associated college to make arrangements with any other associated college or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(4) The conditions of recognition of an associated college shall be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council, but no associated college shall except with the previous approval of the Chancellor, be authorised to impart instruction for post-graduate degrees:

Provided that if an associated college is refused recognition for imparting instruction for post-graduate degrees, such college may, with the approval of the Chancellor, be granted affiliation by any University referred to in Section 37, anything in Section 5 notwithstanding, and thereupon, such college shall cease to be an associated college.

(5) Except as provided by this Act, the Management of an associated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such college shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.

(6) The Executive council shall cause every associated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding three years by one or more persons authorised by it in this behalf and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(7) The recognition of an associated college may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn by the Executive Council, if it is satisfied after considering

any explanation furnished by the management, that it h ceased to fulfil the conditions of its recognition or that persists in making default in the performance of its duti under this Act or in the removal of any defect in its wo pointed out by the Executive Council.

[9][(8) Notwithstanding anything in this section or Section 5, any associated college situated within the ar of any University to which this section applies, may, subj to such direction, as may be issued by the State Governme in this behalf, be admitted to the privileges of affiliation any University to which Section 37 applies.]

Disqualification for membership of Management

39. A person shall be disqualified for being chos as, and for being, a member of the Management of affiliated or associated college (other than a colle maintained exclusively by the State Government or by lo authority), if he or his relative accepts any remuneration f any work in or for such college or any contract for t supply of goods to or for the execution of any work f such college :

Provided that nothing in this section shall apply the acceptance of any remuneration by a teacher as su or for any duties performed in connection with examination conducted by the college or for any duties Superintendent or Warden of a training unit or of a hall hostel of the college or as a proctor or tutor or for a duties, of a similar nature in relation to the college.

Explanation– The term 'relative' shall have t meaning assigned to it in the Explanation to Section 20.

9. *Subs.* by U.P. Act 19 of 1987

Inspection, etc., of Affiliated and Associated Colleges

40.(1) The State Government shall have the right to use an inspection to be made by such person or persons it may direct, of any affiliated or associated college, luding buildings, laboratories and equipments thereof d also of the examinations, teaching and other work nducted or done by it, or cause an inquiry to be made in spect of any matter connected with the administration d finances of such college.

(2) Where the State Government decides to cause inspection or inquiry to be made under sub-section (1), shall inform the Management of the same and a presentative appointed by the Management and where Management fails to appoint a representative, the ncipal of the college may be present at such inspection inquiry and shall have the right to be heard on behalf of Management but no legal practitioner shall appear, plead act on behalf of the college at such inspection or inquiry.

(3) The person or persons appointed to inspect or uire under sub-section (1) shall have all the powers of a il court while trying a suit under the Code of the Civil ocedure, 1908, for the purpose of taking evidence on h and of enforcing the attendance of witnesses and npelling production of documents and material objects, shall be deemed to be a civil court within the meaning Sections 480 and 482 of the Code of Criminal cedure, 1898[10] and any proceedings before him or them ll be deemed to be judicial proceedings within the ning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government may communicate to the nagement, the result of such inspection or inquiry and

See now Cr. P.C, 1973 (2 of 1974).

may issue direction as to the action to be taken and the Management shall forthwith comply with such directions.

(5) The State Government shall inform the Vice-Chancellor about any communication made by it to the Management under sub-section (4).

(6) The State Government may, at any time, call for any information from the Management or Principal of an affiliated or associated college in connection with such inspection or inquiry.

Constituent Colleges

41. (1) Constituent colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) The Principal of a constituent college shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the college and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the college. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes.

Autonomous College

42. (1) The University may grant in the manner prescribed, to an affiliated or associated college which satisfies the conditions prescribed in that behalf, the privileges of varying, for the students receiving instruction in such college, the courses of study prescribed by the University and holding examination in the courses so varied.

(2) The extent to which the courses may be varied and the manner of holding the examination conducted by such college shall be determined in each case by the University.

(3) Such a college shall be declared in the manner prescribed as an autonomous college.

43. (1) The University may, under such conditions as may be prescribed, recognize, an affiliated or associated college as a 'Working men's College', for the purpose of providing courses, for degrees to persons, otherwise eligible for admission to such courses who may be unable to be enrolled as whole-time students by reasons of being engaged in business, trade, agriculture or industry or employed in any other form of service. **Working Men's Colleges**

(2) The courses for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half time the duration prescribed for such course for other students.

(3) Each such courses shall be organized separately.

44. The University may establish one or more Institutes to organize and conduct teaching and research in any subject. **Institutes**

CHAPTER VIII

ADMISSIONS AND EXAMINATIONS

Admission of Students

45. (1) No students shall be eligible for admission to the course of study for a degree unless –

(a) he has passed –

(i) the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or of any University or Board incorporated by any law for the time being in force; or

(ii) any examination, or any degree conferred by any other University, being an examination or degree recognized by the University as equivalent to the Intermediate Examination or to a degree of the University; and

(b) he possesses such further qualifications, if any, as may be specified in the Ordinances :

Provided that the University may prescribed by Ordinances any lower qualifications for admission to a degree in Fine Arts.

(2) The conditions under which students may be admitted to the diploma courses of the University shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The University shall have the power to recognize (for the purposes of admission to a course of study for a

degree), as equivalent to its own degree, any degree conferred by any other University or, as equivalent to the Intermediate Examination of any Indian University, any examination conducted by any other authority.

(4) Any student whose work or conduct is unsatisfactory may be removed from the University or an institute or a constituent college or an affiliated or associated college in accordance with the provisions of the Ordinances.

Bar of charging any donation, etc. for admission to a college

46. No person connected with the management of an affiliated or associated college and no Principal or other teacher or other employee thereof shall directly or indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates laid down in the Ordinances, from or on behalf of any pupil [as a condition for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such college]

Contribution and donations to colleges

[12][**46-A.** Where a contribution or donation, either in cash or in kind is taken or received by any affiliated or associated college maintained exclusively by the State Government or a local authority, the contribution or donation so received shall be utilised only for the purpose for which it was given to it and in the case of a college maintained exclusively by the State Government any cash contribution or donation shall be credited to the personal ledger account of such institution which shall be operated in accordance with the general or special orders of the State Government.

---

1. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 14.
2. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 15.

Halls hostels and delegacy of the University

47. (1) This section shall apply to the University of Lucknow, Allahabad, Gorakhpur and such other University the State Government may by notification specify.

(2) The halls and hostels of the University shall be–

(a) those maintained by the University and named in the Statutes ;

(b) those recognised by the Executive Council on such general or special conditions as may be provided by the Ordinances.

(3) The warden and other staff of the halls and hostels shall be apointed in the manner provided by the Ordinances.

(4) The Executive Council shall have power to suspend or withdraw the recognition of a hall or hostel which is not maintained in accordance with the conditions referred to in clause (b) of sub-section (2) :

Provied that no such action shall be taken without giving to the management of such hall or hostel an opportunity of making a representative against the proposed action.

(5) There shall be a Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any constituent college or hall. The constitution power and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes.

Examinations

48. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Examinations Committee shall direct the arrangements for the conduct of examinations.

CHAPTER IX

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

49. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular, provide for – **Statutes**

(a) the constitution, power and duties of the authorities of the University;

(b) the election, appointment and term of office of the members of authorities of the University, including the continuance in office of the first members, and the filling in of vacancies in their membership and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary to provide;

(c) the powers and duties of the officers of the University;

[13][(d) the classification and recruitment (including minimum qualifications and experience) of Principals and other teachers of the University and of affiliated and associated colleges, the maintenance by them of their annual academic progress report, the rules of conduct to be observed by them and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement);

13. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 16 and shall be deemed always to have been substituted.

(e) the recruitment (including minimum qualifications and experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement) of persons appointed to other posts under the University;]

(f) the constitution of a pension or provident fund or the establishment of an insurance-scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;

(g) the institution of degrees and diplomas;

(h) the conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees and diplomas, certificates and other academic distinctions;

(j) the establishment, amalgamation, abolition and reorganisation, of Faculties;

(k) the establishment of departments of teaching in the Faculties;

(l) the establishment, abolition and reorganisation of halls and hostels maintained by the University;

(m) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of affiliation or recognition by the University and the conditions under which any such privilege may be withdrawn;

(n) the recognition of the Management of any affiliated or associated college;

[14][(o) the number, minimum qualifications and experience, the emoluments and other conditions of service, including the age of retirement and provisions relating to compulsory retirement of salaried employees (not being teachers) of the University or an affiliated or associated college, and the preparation and maintenance of record of their service;]

(p) the institution of scholarship, fellowships, studentships, medals and prizes;

(q) the qualifications, conditions and manner of registration of graduates and the maintenance of a register of registered graduates;

(r) the holding of convocation, if any; and

(s) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the statutes.

Statutes how made

50. The first Statutes of the University shall be made by the State Government by notification in the *Gazette* and in the case of any existing University, for so long as the First Statutes are not so made, the statutes as in force immediately before the commencement of this Act, insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Act, shall, subject to such adaptations and modifications whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient, as the State Government may, by notification inthe *Gazette* provide, continue in force, and any such adaptation or modification shall not be called in question.

---

14. *Subs.* by U.P. Act of 1977, S. 16

[15][(1-A) The State Government may by notification in the *Gazette* amend whether by way of addition, substitution or omission, the First Statutes at any time [16] [up to December 31, 1990][17] and any such amendment may be retorspective to a date not earlier than the date of such commencement).

[18][(1-B) Until the First Statutes of the Purvanchal University are made under this section, the Statutes of the University of Gorakhpur, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.]

[19][(2) The Executive Council may, at any time [after December 31, 1990][20] make new additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A)].

(3) The Executive Council shall not propose the draft of any Statute affecting the status, power or constitution

---

15. *Ins.* by U.P. Act 29 of 1974, S. 15.
16. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 17 and U.P. Act 12 of 1978, S. 4.
17. '1978' *subs.* by '1981' (w.e.f. 1.1.1979) by U.P. Act 15 of 1980; '1981' *subs.* by '1982' (w.e.f. 29.12.1981) by U.P. Act 25 of 1982; 1982 *subs.* by '1984' (w.e.f. 1.1.1983) by U.P. Act 6 of 1983; '1984' *subs.* by '1985' (w.e.f. 31.12.1984) by U.P. Act 9 of 1985; '1985' *subs.* by '1987' by U.P. Act 15 of 1986, and shall be deemed always to have been *substituted*; '1987', *subs.* by '1990' by U.P. Act 9 of 1988, S. 3 (w.e.f. 1-1-1998)
18. *Ins.* by U.P. Act 19 of 1987.
19. *Subs.* by U.P. Act 29 of 1974, S. 15.
20. '1978' *subs.* by '1981' (w.e.f. 1.1.1979) by U.P. Act No. 15 of 1980, '1981' *subs.* by '1982' (w.e.f. 29.12.1981) by U.P. No. 25 of 1982; '1982' *subs.* by '1984' (w.e.f. 1.1.1983) by U.P. Act 6 of 1983; '1984' *subs.* by '1985' (w.e.f. 31.12.1984) by U.P. Act 9 of 1985; '1985' *subs.* by '1987' by U.P. Act 15 of 1986 '1987' *subs.* by U.P. Act 9 of 1988 S.3 (w.e.f. 1.1.88).

of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be submitted to the Chancellor.

(4) Every new Statute or addition to a Statute or any amendment or repeal of Statute shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent therefrom or remit it to the Executive Council for further consideration.

(5) A Statute passed by the Executive Council shall have effect from the date it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him.

[21][[22](6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Government may in order to implement any decision taken by it the interest of learning, teaching or reseach or for the benefit of teachers, students or other staff or on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commission or the State or national education policy with regard to the qualifications of the teachers, require the Executive Council to make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement the State Government may with the assent of the Chancellor make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A).

(7) The Executive Council shall have no power to amend or repeal the Statutes made by the State Government

---

21. *Ins.* by U.P. Act No. 4 of 1995, S.3 (w.e.f. 17-12-1994).
22. *Subs.* by U.P. Act No. 9 of 1998, S.4 (w.e.f. 19-9-1997).

under sub-section (6) or to make new or additional Statutes inconsistent with such Statutes.

Ordinances

51. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes the ordinances may provide for any matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Ordinance shall provide for the following matters, namely –

(a) the admission or students to the University and their enrolment and continuance as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diploma and other academic distinctions of the University;

(c) the conditions under which students shall be admitted to the examinations, degrees and diplomas of the University and shall be eligible for the award of such degrees and diplomas;

(d) the conditions of the award of scholarships, fellowships, studentships, bursaries, medals and prizes;

(e) the conditions of the residence of students at the University and the management of halls and hostels maintained by the University;

(f) the recognition and management of halls and hostels not maintained by the University;

(g) the maintenance of discipline among the students of the University;

(h) all matters relating to correspondence courses and private candidates;

[23][(i) the formation of parent-teachers association];

(j) the fees which may be charged by the University or by an affiliated or associated college for any purpose;

(k) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instructions in halls and hostels;

(l) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners, moderators, invigilators and tabulators;

(m) the conduct of examinations;

(n) the remuneration and allowances including travelling and daily allowances to be paid to persons employed on the business of the University;

(o) all other matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for by the Ordinances.

Ordinances how made

52. (1) The First Ordinances of each existing University shall be the Ordinances as in force immediately before the commencement of this Act insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Act :

Provided that for the purposes of bringing the provisions of any such Ordinances into accord with the

Subs. by U.P. Act 5 of 1977, S. 18.

provisions of this Act and the Statutes, the Chancellor may by order make such adaptations and modifications of the Ordinances whether by way of repeal, amendment or additions as may be necessary or expedient and, provided that the ordinances shall as from such date as may be specified in the order have effect subject to the adaptations and modifications so made any such adaptations or modification shall not be called in question.

(2) The First Ordinances of the Universities of Kumaun and Garhwal and of any other University to be established after the commencement of this Act shall be made by the Government by notification in the *Gazette*.

[24][2-A) Until the First Ordinances of the Purvancha University are made under sub-section (2), the Ordinance of the University of Gorakhpur, as in force immediatel before the establishment of the said University, shall appl to it subject to such adaptations and modifications as th State Government may, by notification, provide.]

(3) Save as otherwise provided in this section, th Executive Council may, from time to time, make new c additional Ordinances or may amend or repeal th Ordinances referred to in sub-sections (1) and (2):

Provided that no Ordinance shall be made –

(a) affecting the admission of students, c prescribing examinations to be recogniz as equivalent to the University examinatio or the further qualifications mentioned i sub-section (1) of Section 45 for admissi

24. *Ins.* by U.P. Act 19 of 1987.

to the degree courses of the University, unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council; or

(b) effecting the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations or any course of study except in accordance with a proposal of Faculty or Faculties concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council; or

(c) effecting the number, qualifications and emoluments of the teachers of the University or the income or expenditure of the University, unless a draft of the same has been approved by the State Government.

(4) The Executive Council shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (3) but may reject it or return to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendments which the Executive Council may suggest.

(5) All ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct and shall be submitted as soon as may be to the Chancellor.

(6) The Chancellor may, at any time signify to the Executive Council his disallowance of such Ordinances other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (3) and from the date of receipt by Executive Council of intimation of such disallowances, such Ordinances shall become void.

(7) The Chancellor may direct that the operation of any ordinance other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (3) shall be suspended until he has an opportunity of exercising his power of disallowance. An order of suspension under this sub-section shall cease to have affect on the expiration of one month from the date of such order.

Regulations

53. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statute and the Ordinances, and authority or other body of the University may make regulations –

(a) laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to form the quorum;

(b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be provided by Regulations; and

(c) providing for any other matter solely concerning such authority or body and not provided for by this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) The Regulations made by any authority or other body of the University shall provide for the giving of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted thereat and for the keeping of record of the proceedings of such meetings.

(3) The Executive Council may direct any authority or other body of the University other than the Court to cancel or to amend in such form as may be specified in the direction, any Regulation made by such authority or body

and such authority or body shall thereupon cancel or amend the Regulation accordingly:

Provided that any authority or other body of the University, if dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor who may after obtaining the views of the Executive Council pass such orders as he thinks fit.

(4) The Academic Council may subject to the provisions of the ordinances, make Regulations providing for the course of study for any examination, degree or diploma of the University only after the Board of Faculty concerned has proposed a draft of the same.

(5) The Academic Council shall not have power to amend or reject any draft proposed by the Board of Faculty under sub-section (4), but may return it to the Board for further consideration together with its own suggestions.

CHAPTER X

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

Annual Report

54. (1) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court a month before its annual meeting and the court shall consider it in its annual meeting.

(2) The Court may, by resolution make recommendations on such report and communicate the same to the Executive Council which may take such action thereon as it thinks fit.

Accounts and audit

55. (1) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and all money accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

(2) A copy of the annual accounts and the balance sheet shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

(3) The annual accounts and the balance-sheet audited shall be printed and copies thereof shall, together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council, to the Court and the State Government.

(4) The Executive Council shall also prepare, before such date as may be prescribed, the budget for the ensuing year.

(5) Every item of new expenditure above such amount as may be prescribed which it is proposed to

include in the budget shall be referred by the Executive Council to the Finance Committee which may make recommendations thereon.

(6) The Executive Council shall, after considering the recommendations if any, of the Finance Committee approve the budget finally.

(7) The annual accounts, the balance-sheet and the audit report shall be considered by the Court at its annual meeting and the Court may, by resolution, make recommendations with reference thereto and communicate the same to the Executive Council.

(8) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure –

(a) either not sanctioned in the budget, or in the case of funds granted to the University, subsequent to the sanction of the budget, by the State Government or the Government or India or the University Grants Commission or any international organisation or Foundation, save in accordance with the term of such grant:

Provided that notwithstanding anything in sub-section (7) of Section 13, the Vice-Chancellor may, in the case of fire, flood, excessive rainfall or other sudden or, unforeseen circumstances, incur non-recurring expenditure not exceeding rupees five thousand not sanctioned in the budget and he shall immediately inform the State

Government in respect of all such expenditure;

(b) on any litigation in opposition to [25][any order of the Chancellor or of the State Government purporting to be made under this Act.]

Surcharge

[26][**55-A.** (1) An officer specified in any of the clauses (c) to (i) of Section 9 shall be liable to surcharge for the loss, waste or mis-application of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or mis-application shall be such as may be prescribed.]

---

25. *Subs.* by U.P. Act 12 of 1978, S.5.
26. *Ins.* by U.P. Act 12 of 1978, S.6.

CHAPTER XI

REGULATION OF DEGREE COLLEGES

56. In this Chapter, unless the context otherwise requires – **Definitions**

(a) 'Property', in relation to an affiliated or associated college, includes all property, movable and immovable, belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the college, including lands, buildings (including hostels), works, library, laboratory, instruments, equipment, furniture, stationery, stores, automobiles and other vehicles, if any, and other things pertaining to the college, cash on hand, cash at bank, investments, and book debts and all other rights, and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the college and all books of account, registers, and all other documents of whatever nature relating thereto, and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations of whatever kind of the college;

(b) 'Salary' means the aggregate of the emoluments including dearness or any other allowances for the time being payable to a teacher or other employee, after making permissible deductions.

Power of the State Government to issue notice

57. If the State Government receives information in respect of any affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or a local authority)–

(i) that its Management has persistently committed wilful default in paying the salary of the teachers or other employees of the college by the twentieth day of the month next following the month in respect of which or any part of which it is payable; or

(ii) that its Management has failed to appoint teaching staff possessing such qualifications as are necessary for the purpose of ensuring the maintenance of academic standards in relation to the college or has appointed or retained in service any teacher in contravention of the Statute or Ordinances; [26a.][or has failed to comply with the orders of the Director of Education (Higher Education) made on the basis of the recommendation of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission under the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980,];or

(iii) that any dispute with respect to the right claimed by different persons to be lawful office-bearers of its Management has affected the smooth and orderly administration of the college; or

---

26a. *Ins.* by U.P. Act 9 of 1998 S.5 (w.e.f. 19-9-1997).

(iv) that its Management has presistently failed to provide the college with such adequate and proper accommodation, library, furniture, stationery, laboratory, equipment, and other facilities, as are necessary for efficient administration of the college; or

(v) that its Management has substantially, diverted misapplied or mis-appropriated the property of the college to the deteriment of the college;

it may call upon the Management to show cause why an order under Section 58 should not be made :

Provided that where it is in dispute as to who are the fice-bearers of the Management, such notice shall be issued to all persons claiming to be so.

Authorised Controller

58. (1) If the State Government after considering the explanation, if any, submitted by the Management, under Section 57 is satisfied that any ground mentioned in that section exists, it may, by order, authorise any person (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over, for such period not exceeding two years as may be specified, the Management of the college and its property to the exclusion of the Management and whenever the Authorised Controller so takes over the Management, he shall, subject only to such restrictions as the State Government may impose, have in relation to the Management of the college and its property all such powers and authority as the Management would have if the college and its property were not taken over under this sub-section:

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper Management of the college and its property, it may, from time to time, extend the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of operation of the order including the period specified in the initial order under this sub-section does not exceed [27][five years]:

[28][Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawful constituted Mangement or the college the Authorised Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that the Management has been lawfully constituted:

Provided also that the State Government may, at any time revoke an order made under this sub-section.]

(2) Where the State Government while issuing a notice under Section 57 is of opinion, for reasons to be recorded, that immediate action is necessary in the interest of the college, it may suspend the Management, which shall thereupon cease to function, and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the college and its property till further proceedings are completed :

Provided that no such order shall remain in force for more than six months from the date of actual taking over the Management in pursuance of such order :

Provided further that incomputation of the said period of six months, the time during which the operation of the

---

27. 'Four years' *substituted* by 'five years' (w.e.f. 25.6.1982) by U.P. Act 4 of 1983.
28. *Subs.* by U.P. Act 4 of 1983 (w.e.f. 25.6.1982).

order was suspended by any order of the High Court passed in exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution or any period during which management failed to show cause in pursuance of the notice under Section 57, shall be excluded.

(3) Nothing in sub-section (1), shall be construed to confer on the Authorised Controller the power of transfer any immovable property belonging to college (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management or to create any charge thereon) except as condition of receipt of any grant -in-aid of the college from the State Government or the Government of India.

(4) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or in any instrument relating to the management and control of the college or its property :

Provided that the property of the college and any income therefrom shall continue to be applied for the purposes of the college as provided in any such instrument.

(5) The Director of Education (Higher Education) may give to the Authorised Controller such directions as may deem necessary for the proper management of the college or its property, and the Authorised Controller shall carry out those directions.

Clause 58 not applied to minority colleges

59. Nothing contained in Section 58, shall apply to a college established and administered by a minority referred in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

Duty to deliver possession to the Authorised Controller.

60. (1) Where an order has been passed under Section 58 in respect of a college, every person in whose possession or custody or under whose control any property of the college may be, shall deliver the property to the Authorised Controller forthwith.

(2) Any person who on the date of such order has in his possession or under his control any books or other documents relating to the college or to its property shall be liable to account for the said books and other documents to the authorised controller and shall deliver them up to him or to such person as the Authorised Controller may specify in this behalf.

(3) The Authorised Controller may apply to Collector for delivery of possession and control over the college or its property or any part thereof, and the Collector may take all necessary steps for securing possession to the Authorised Controller of such college or property, and in particular, may use or cause to be used such force as may be necessary.

[29][Chapter XI-A

PAYMENT OF SALARY TO TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF DEGREE COLLEGES

60-A. In this Chapter, unless the context otherwise requires – **Definitions**

(i) 'College' means any college affiliated to or recognised by any University in accordance with the provision of this Act or the Statutes made thereunder and for the time being receiving maintenance grant from the State Government (but does not include a college maintained exclusively by the State Government or a [30][Nagar Mahapalika];

(ii) 'Deputy Director' means the Regional Deputy Director of Education and includes and other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Deputy Director under this Chapter;

(iii) 'Employee', in relation to a college, means a non-teaching employee of such college–

(a) in respect of whose employment maintenance grant was being paid by the State Government during the financial year 1974-75; or

---

29. Chapter XI-A *ins.* by U.P. Act 21 of 1975, S.9.

30. Words "local authority" *subs.* by "Nagar Mahapalika" by U.P. Act 15 of 1980, (w.e.f. 26.9.1979).

(b) who was appointed to a post with the permission of the Director of Education (Higher Education);

(iv) 'maintenance grant' means such grant-in-aid of a college as the State Government by general or special order in that behalf directs to be treated as maintenance grant appropriate to the level of that college;

(v) 'salary' shall have the meaning assigned to it, in clause (b) of Section 56;

(vi) 'teacher' in relation to a college, means a teacher in respect of whose employment maintenance, grant was being paid by the State Government during the financial year 1974-75, or who is employed with the approval of the Vice-Chancellor of the University concerned –

(a) to a post created, before April 1, 1975, with the permission of the Vice-Chancellor concerned; or

(b) to a post created, after Marth 31, 1975, with the permission of the Director of Education (Higher Education).

Payment of salary within time and without unauthorised deductions

60-B. (1) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a teacher or other employee of any college in respect of any period after the 31st day of March 1975, shall be paid to him before the expiry of the 20th day or such earlier day as the State Government may, by

general or the month in behalf, appoint, of the month next following special order in that respect of which or any part of which it is payable.

(2) The salary shall be paid without deductions of any kind except those authorised by this Act, the Statutes or the Ordinances, or by any other law for the time being in force.

60-C. (1) The Deputy Director may at any time, for the purposes of this Chapter, inspect or cause to be inspected any college or call for such information and records (including registers, books of account and vouchers) from its management with regard to the payment of salaries to its teachers or emloyees or give to its management any direction for the observance of such canons of financial propriety (including any direction for retrenchment of any teacher or employee or for prohibition of any wasteful expenditure) as he thinks fit. **Power to inspect**

(2) Every direction for retrenetment under sub-section (1) shall be issued after obtaining the prior approval of the Director of Education (Higher Education) and shall specify a future date on which such retrenchment shall become operative.

(3) Where any direction for retrenchment is issued in accordance with sub-sections (1) and (2), the teacher or the employee concerned shall, with effect from the date specified in such direction, cease to be a teacher or employee of the college for the purposes of the maintenance grant payable under this Chapter.

[31][**60-CC.** The Vice Chancellor may with the prior approval of the State Government create any **Super-numerary post of teachers**

1. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 19.

supernumerary post with a view to enabling a teacher who is for the time being holding responsible position of a national importance in India or abroad in education administration, or other similar assignment to retain his lien and seniority as such teacher and also to continue to earn increments in his pay scale during the period of his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits, if, any, in accordance with the Statutes :

Provided that no salary shall be payable to such teacher by the college for the period of such assignment.]

Procedure for payment of salary in case of certain colleges

60-D. (1) The management of every college shall for the purposes of disbursement of salaries to its teachers and employees open in a scheduled bank or a co-operative bank or post office, a separate account (thereinafter in this Chapter called 'Salary Payment Account') to be operated jointly by a representative of the management and by the Deputy Director or such other officer as may be authorised by the Deputy Director in that behalf :

Provided that after the Salary Payment Account is opened, the Deputy Director may, if he is, subject to any rules made under Section 60-H satisfied that it is expedient in the public interest so to do, instruct the bank that the account shall be operated by the representative of the management alone, and may at any time revoke, such instructions :

Provided further that in the case referred to in sub-section (3), or where in any other case after giving to the Management an opportunity of showing cause, the Deputy Director is of opinion that it is necessary or expedient so to do, the Deputy Director may instruct the bank that the

Salary Payment Account shall be operated only by himself, or by such other officer as may be authorised by him in that behalf and may at any time revoke such instruction.

(2) The State Government may, from time to time, equire by general or special order that the Management of a college shall deposit in the Salary Payment Account, uch portion of the amount received from students as fees nd also such portion, if any, of the income received from ny property, movable or immovable belonging to or ndowed wholly or partly for the benefit of the college, nd by such date, as may be specified in that order, and hereupon, the Management shall be bound to comply with uch direction.

(3) Where the Deputy Director is of opinion that the Management has failed to deposit the fees in accordance ith the provisions of sub-section (2) or the orders issued ereunder, the Deputy Director may, by order, prohibit e Management from realising any fees from the students d thereupon, the Deputy Directory may realise the fees ither through the teachers of the college or in such other anner as he thinks fit) directly from the students and shall posit the fees so recovered in the Salary Payment count.

(4) The State Government shall also pay into the lary Payment, Account such amount as maintenance nt, which after taking into consideration the amounts posited under sub-sections (2) and (3) is necessary for king payment in accordance with sub-section (5).

(5) No money credited to the salary Payment count shall be applied for any purpose except the

following, namely –

(a) for payment of salary to the teachers an other employees of the college falling du for any period after March, 31, 1975;

(b) for crediting the Management's contributio if any to the provident fund accounts teachers and employees of the colleg concerned.

(6) The salary of a teacher or employees shall paid by transfer of the amount from the Salary Payme Account to his account, if any, in the same bank, or if has no account in that bank, then by cheque.

Liability in respect of salary

60-E. (1) The State Government shall be liable f payment of salaries of teachers and employees of eve college due in respect of any period after March 31, 197

(2) The State Government may recover any amou in respect of which any liability is incurred by it under su section (1) by attachment of the income from the prope belonging to or vested in the college as if that amount w an arrear of land revenue due from such college.

(3) Nothing in this section shall be deemed derogate from the liability of the college for any such du to the teacher or employee.

Punishment penalties and procedure

60-F. (1) If any default is committed in complyi with any direction under Section 60-C, or with provisions of Section 60-B or Section 60-D, every pers who at the time the default was committed was manage any other person vested with the authority to manage a conduct the affairs of the college shall, unless he pro

that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be punishable, in the case of a default in complying with the provisions of Section 60-B with fine which may extend to one thousand rupees, and in the case of any other default with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this section except with the previous sanction of the Deputy Director.

(3) Every offence under this section shall be cognizable, but no police officer below the rank of a Deputy Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefore without a warrant.

(4) No court below the rank of a Magistrate of the first class shall take cognizance of an offence under this section.

Finality of orders

60-G. No order made or direction given by the State Government, the Director of Education (Higher Education), the Deputy Director of other officer in exercise of any power conferred by or under this Chapter shall be called in question in any court.

Rule making power

60-H. (1) The State Government may by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Chapter.

(2) All rules made under this Chapter shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House

of the State Legislature while it is in session for a total perio
of thirty days comprised in its one session or more tha
one successive sessions and shall, unless some later date i
appointed, take effect from the date of their publication i
the official *Gazette*, subject to such modifications c
annulments as the two Houses of Legislature may durin
the said period agree to make, so however, that any suc
modification or annulment shall be without prejudice to th
validity of anything previously done thereunder.]

CHAPTER XII

PENALTIES AND PROCEDURE

61. (1) Whoever contravenes the provisions of Section 46 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or both. **Penalties**

(2) Any person who –

(a) having in his possession, custody or control any property of college in respect of which an order has been made under Section 58 wrongfully withholds such property from the Authorised Controller appointed under that section or from any person authorised by him in that behalf; or

(b) wrongfully obtains possession of any property of such college ; or

(c) wilfully withholds or fails to furnish the Authorised Controller or any person specified by him as required by sub-section (2) of Section 60 any books or other documents which may be in his possession, custody or control; or

(d) wilfully obstructs any person from duly carrying out all or any of the provisions of this Act;

shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine or with both :

Provided that the Court trying any offence under clause (a) or clause (b) of this sub-section may at the time of convicting the accused person, order him to deliver up or refund within a time to be fixed by the Court any property wrongfully withhleld or wrongfully obtained or any books or other documents wilfully withheld.

Cognizance by Courts

62. No court shall take cognizance of an offence punishable under Section 61 except with the previous sanction of the Director of Education (Higher Education).

Offences by registered societies

63. (1) If the person committing the offence under Section 61 is a society registered under the Societies Registration Act, 1860, the society as well as every person incharge of and responsible to the society for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a registered society and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of offence is attributable to any neglect on the part of any member of the society, such member shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

Manner of appointment of officers and members of authorities

64. (1) Except as expressiy provided by this Act or the Statutes, officers of the University and members of authorities of the University shall so far as may be, be chosen by methods other than election.

(2) Where a provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualifications the manner of rotation and determination of seniority and other qualifications shall be such as may be prescribed.

(3) Where a provision for an election is made in this Act, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where provision for an election is made in the Statutes it shall be held in such manner as the Statutes may provide.

(4) Except as expressly provided by this Act, no officer or employee of the University shall be eligible to seek election to any authority or other body of the University.

Filling of casual vacancies

65. (1) Any casual vacancy among the members, other than *ex-officio* members, of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the members whose vacancy is to be filled up was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member

(2) A person, who is a member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the Universtiy or outside, shall retain his seat on such

authority for so long as he continues to be the representative of such body [* * *][32]

Proceeding not to be invalidated by vacancies, etc.

66. No act or proceeding, of any authority or body or committee of the University shall be invalid merely by reason of –

(a) any vacancy or defect in the constitution thereof, or

(b) some person having taken part in the proceedings who was not entitled to do so; or

(c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof, or

(d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

Removal from membership of the University

67. The Court may by a two-third majority of the members present and voting remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Court, is an offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or has behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same grounds withdraw from any person any degree, diploma, or certificate conferred or granted by the University.

Reference to the Chancellor

68. If any question arises whether any person has been duly elected or appointd as, or is entitled to be, member of any authority or other body of the University, or whether any decision of any authority or officer of the

32. Words "and thereafter till his successor is duly appointed" *omitted* by U.P. Act 9 of 1998, S.6 (w.e.f. 19-9-1997).

University [33][(including any question as to the validity of a Statute, Ordinance or Regulation, not being a Statute or Ordinance made or approved by the State Government or by the Chancellor)] is in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinance made thereunder the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final :

Provided that no reference under this section shall be made –

(a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;

(b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved :

Provided further that the Chancellor may in exceptional circumstances –

(a) act *suo motu* or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso;

(b) where the matter referred relates to a dispute about the election and the eligibility of the person so elected is in doubt, pass such orders of stay as he thinks just and expedient;

(c) [34][* * *]

---

33. *Ins.* by U.P. Act 21 of 1975, S. 10.

34. *Omitted* by U.P. Act 5 of 1977, S. 21.

Power of Vice-Chancellor to enforce his order against Management.

[35][**68-A.** (1) Where a decision of the Management of an affiliated or associated college to dismiss, remove or to reduce a teacher in rank or to punish him in any other manner or to terminate his services, has not been approved by the Vice-Chancellor or where an order of suspension of such teacher has been stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of this Act or of an Act repealed by Section 74, and the management has committed default in paying the salary of such teacher which became due to him in consequence of the Vice-Chancellor's order, the Vice-Chancellor may pass an order, requiring the management to pay the amount of salary as may be specified in the order during the period of suspension, may also require the management to pay the suspension allowance at the rate of one-half of the salary payable, if the said amount has not been paid.

(2) In any such case as is referred to in sub-section (1), the Vice-Chancellor may also order reinstatement of the teacher concerned subject to such terms and the conditions as he thinks fit.

(3) The amount of salary or suspension allowance required to be paid under an order of the Vice-Chancellor under sub-section (1) shall on a certificate issued by him to the effect, be recoverable by the Collector as arrears of land revenue.

(4) Every order of the Vice-Chancellor under sub-section (2) shall be executable by the lowest civil court having territorial jurisdiction, as if it were a decree of that court.

35. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 21.

(5) No suit shall lie against any management or teacher in respect of any matter for which a relief can be granted by the Vice-Chancellor under this Section.]

[36][**69.** No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or the Director of Education (Higher Education) or the Deputy Director (as defined in Section 60-A) or the Authorised Controller or the University or any officer, authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the Act of the rules or the Statutes or the Ordinances made thereunder.] **Bar of suit**

70. (1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would if produced have been admissible in evidence. **Mode of proof of University record**

(2) No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party, be required to produce any document, register or other record of the University the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.

36. *Subs.* by U.P. Act 21 of 1975, S. 11.

CHAPTER XIV

TRANSITORY PROVISION

Continuation of existing Officers of the University

71. Subject to the provisions of this Act, every person holding office as an officer of an existing University on the date immediately before the commencement of this Act shall continue to hold office on the same terms and conditions until the expiration of his term of office.

Constitution of authorities

72. [37][(1) Every authority of an existing University shall, as soon as may be after the commencement of this Act be constituted in accordance with the provisions of this Act, and every person holding office as member of such authority immediately before the commencement of this Act shall, on the date of such commencement, cease to be such member.]

(2) Until any authority of the University is constituted under sub-section (1), the State Government may, by order direct from time to time by whom and in what manner the powers, duties and functions exercisable or dischargeable under this Act, by any authority of University shall be exercised or discharged :

Provided that no such direction shall be issued after December 31, [38][[(1981)]][39].

(3) The Administrative Committees and the Academic Committees constituted, in pursuance of sub-section (2) of Section 67 of the Uttar Pradesh State Universities Ordinance, 1973, shall, on the 15th September,

---

37. *Subs.* by U.P. Act 21 of 1975, S. 12..
38. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 22 and U.P. Act 12 of 1978, S. 7.
39. '1978' *substituted* by '1981' w.e.f. January 1, 1979 by U.P. Act 15 of 1980.

1973, stand dissolved except as respect things done or omitted to be done by such Committees before that date, but nothing in this sub-section shall be deemed to preclude the State Government from taking, as from that date, such action under sub-section (2) as it thinks fit.

Transitory provisions regarding Kashi Vidyapith

[40][**72-A.** Notwithstanding anything contained in this Act –

(a) every person holding office as an officer (other than the Chancellor) of the Kashi Vidyapith on the date immediately before its establishment as a University shall continue to hold office as such on the same terms and conditions except as respect tenure as he held on the said date until fresh appointments are made under clause (b);

(b) as soon as may be after the commencement of this section, the State Government may appoint interim officers of the said University (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of the said University in such manner as it thinks fit, upon which the corresponding officers referred to in clause (a) shall cease to hold office and the corresponding authorities, shall stand dissolved forthwith;

[41][(c) the officers appointed and the members of the authorities constituted under clause (b) shall hold office up to [December 31,

---

40. *Ins.* by U.P. Act 29 of 1974, S. 16.
41. *Subs.* by U.P. Act 12 of 1978, S. 8.

1981][42], or until the appointment of the officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (d) whichever be earlier;

(d) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of the said University in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under clause (c).]

Transistory provision on change of name of Garhwal University

[43][**72-B.** With effect from April 25,1989 any reference to the University of Garhwal in this Act or any rules, statutes,ordinances, statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any documents or proceedings shall be construed as a reference to the Hemveti Nandan Bahuguna Garhwal University.]

Transitory provisions on change of name of University of Meerut

[44][**72-C.** With effect from January 17, 1994 any reference to the University of Meerut in this Act, or any rules, statutes, Ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Chaudhary Charan Singh University, Meerut.]

Transitory provisions on the change of name of the University of Avadh

[45][**72-D.** [(1)][46] With effect from June 18, 1994 any reference to the University of Avadh in this Act or any

42. '1978' *subs.* by '1981' (w.e.f. 1.1.1979) by U.P. Act 15 of 1980;
43. *Ins.* by U.P. Act 26 of 1989, S.3. (w.e.f. 24-4-1989).
44. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1994, S.3. (w.e.f. 17-1-1994).
45. *Ins.* by U.P. Act 20 of 1994, S.7. (w.e.f. 18-6-1994).
46. *Renumbered* by President's Act 4 of 1996, S.10 (w.e.f. 11-7-1995

rules, Ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Dr. Ram Manohar Lohia University, Faizabad.]

[47][(2) With effect from July 11, 1995 any reference to the University of Avadh, or to the Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad, in this Act or any rules, statutes, Ordinance, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad.]

Transitory provision on the name of the Kashi Vidyapith

[48][**72-E.** With effect from July 11,1995 any reference to the Kashi Vidyapith in this Act or any rules, statutes, Ordinance, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Mahatama Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.]

Transitory provision on the name of the University of Agra and Kanpur

[49][**72-F.** [1][50] With effect From September 24,1995 any reference to the University of Agra and Kanpur University in this Act or any rules, statutes, Ordinance, statutory instruments or any other law for the time being in force in any document or proceedings shall be construed as reference to Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra and Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur respectively.

[51][(2). With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment)

47. *Ins.* by President's Act 4 of 1996, S.10 (w.e.f. 11-7-1995).
48. *Ins.* by President's Act 4 of 1996, S.11 (a) (w.e.f. 11-7-1995).
49. *Ins.* by President's Act 4 of 1996, S.11 (b) (w.e.f. 11-7-1995).
50. *Ins.* by U.P. Act 12 of 1997, S.4.
51.. *Ins.* by U.P. Act 12 of 1997, S.4..

Act,1997, any reference to the Kanpur University, or to Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur in this Act or any rules, Statutes, Ordinance, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur.]

Transitory provisions on the change of names of University of Gorakhpur and University of Rohilkhand

[52][72-G. With effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 any reference to the University of Gorakhpur and the University of Rohilkhand in this Act, or any rules , Statutes , Ordinances, statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any document or procedings shall be construed as a reference to Deen Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur and Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly respectively.]

Transitory provision of change of name of the Purvanchal University

[53][72-H. With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State University (Amendment) Act, 1999 any reference to the Purvanchal University in this Act or any rules, Statutes, Ordinances, statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any document or proceeding shall be construed as a reference to Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur.]

Power to remove difficulties

73. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the enactment repealed by Section 74 to the provisions of this Act, by order published in the official *Gazette* direct that the provisions of this Act

52. *Ins.* by U.P. Act 18 of 1997, S.4.

53. *Ins.* by U.P. Act 11 of 1999, S.3. (w.e.f. 8-1-1999).

shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made [54][after December 31, [1982][55]

(2) Every order made under sub section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred in sub-section (1) existed or required to be removed.

Repeal of certain enactments

74. (1) The following enactments are hereby repealed, with effect from the respective dates on which this Act is brought into force in relation to the existing University concerned, namely –

(a) the Lucknow University Act, 1920;

(b) the Allahabad University Act, 1921;

(c) the Agra University Act, 1926;

(d) the Gorakhpur University Act, 1956;

(e) the Varanaseya Sanskrit (Vishwavidyalaya Act, 1956; and

(f) the Kanpur and Meerut University Act, 1965.

---

54. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1977, S. 24 and U.P. Act 12 of 1978, S.9.

55. '1978' *subs.* by '1981' (w.e.f. 1.1.1979) by U.P. Act 15 of 1980; '1981' *subs.* by '1982' (w.e.f. 29.12.1981) by U.P. Act 25 of 1982.

[56][(2) Notwithstanding such repeal –

(a) all appointments made, order issued, degrees or diplomas conferred or certificates issued, privileges granted or other things done (including registration of graduates) under any such enactment, shall be deemed to have been respectively made, issued, conferred, granted or done under the corresponding provisions of this Act, and except as otherwise provided by or under this Act continue in force unless and until they are superseded by any order made under this Act;

(b) all proceedings of Selection Committee which took place before the commencement of this Act and all actions by the Management or by the Executive Council, as the case may be, in respect of the recommendation of such selection Committees, where no orders or appointment on the basis thereof were passed before the commencement of this Act, shall, notwithstanding that the procedure for selection has been modified by this Act, be deemed to have been valid but further proceeding in connection with such pending selections shall be taken in accordance with the provisions of this Act and be continued from the stage where they stood immediately before such commencement.]

56. *Subs.* by U.P. Act 21 of 1975, S. 13 and be deemed always to have been *substituted.*

(3) Notwithstanding anything in sub-sections (1) and (2), or in any other provisions of this Act –

(a) [57][* * *];

(b) [58][* * *];

(c) where any institution has applied for affiliation to the University of Agra in accordance with the provisions of the Agra University Act, 1926, before June 18, 1973 and such application was pending on the said date, and the place where the institution is situated lies under this Act outside area of the University of Agra, such application may be disposed of by the competent authorities of the University of Agra as if the institution would be affiliated to that University, and upon the grant of such application by the Chancellor, the institution would stand affiliated to the University within whose territorial jurisdiction as specified in Section 5, the institution would lie;

(d) until fresh panels of experts are drawn up under sub-section (5) of Section 31, the Chancellor or the Vice-Chancellor, as the case may be, may nominate experts to a Selection Committee under that section from out of the panels in existence immediately before the commencement of this Act :

[59][Provided that the provisions of Explanation I d II the said sub-section (5) shall apply also to the panels

---

Omitted by U.P. Act 5 of 1974, S. 17.

Omitted by U.P. Act 5 of 1974, S. 25.

Ins. by U.P. Act 21 of 1975, S. 13 and shall be deemed always to have been *inserted*.

of experts referred to in this clause and the nominations made from such panels under this clause;]

(e) until a Finance Officer is appointment in a University, the functions of the Finance Officer under this Act shall be performed by a Dean of Faculty nominated by the Chancellor in that behalf;

(f) until rules are made under Section 17, any vacancy in a post of Registrar, Deputy Registrar or Assistant Registrar may be filled on a provisional basis by the Chancellor, in the case of the post of Registrar and by the Vice-Chancellor in the case of the post of Deputy Registrar or Assistant Registrar;

[60][(g) every student of the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, or the Government Degree College, Jakhni situate in district Varanasi or the Government Degree College, Rishikesh, situate in district Dehra Dun, who–

(1) immediately before the commencement of Uttar Pradesh State Universities Ordinance, 1973, was studying for a degree of the University of Agra; or

(2) was admitted as a student of any of the said colleges during the academic year 1973-74 for a degree of the said University; or

60. *Ins.* by U.P. Act 29 of 1974, S. 17.

(3) is eligible to appear at any degree examination of the said University in the year 1974 or in the year 1975 [61][or in the year 1976] as an ex-student;

shall be permitted to complete his course in accordance with the syllabus of the University of Agra, and necessary arrangements for the instruction and examination of such students shall be made by the University of Agra and on the results of such examination, the degree may be conferred by that very University;

(h) until the Faculties are constituted in the Universities referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A) of Section 4, the Selection Committee referred to in clause (c) of sub-section (4) of Section 31 shall consist of the following members, namely–

(1) the Head of the Management or a member of the Management nominated by him, who shall be the Chairman;

(2) one member of the Management nominated by the Management; and

(3) three experts to be nominated by the Vice-Chancellor;

[62][(i) every person residing within the area of the University of Gorakhpur who was permitted

---

61. *Ins.* by U.P. Act 21 of 1975, S. 13.

62. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1977. S. 25 and shall be deemed always to have been *substituted.*

by the Agra University to appear in B.A. Part I or M.A. Part I Examination of 1974 from the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, Varanasi Centre and who, on the result of the examination, has been declared successful, shall be permitted by the University of Agra to appear in the B.A. Part II or M.A. Part II Examination, as the case may be, of the said University from the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, Varanasi Centre, during the academic years 1974-75 and 1975-76 and on that results of such examination the degree may be conferred by that very University and such examination shall be deemed to be valid;

(j) any person residing within the area of the University of Allahabad or the University of Lucknow may be permitted by the University of Kanpur (hereinafter in this clause referred to as the said University) to appear in an examination referred to in clause (5) of Section 7, and on the result of such examination a degree may be conferred by the said University notwithstanding that such person was not residing within the area of the said University].

Amendment of U.P. Act XXIV of 1965

75. In Section 3 of the Uttar Pradesh Universities (Provision regarding Conduct of Examinations) Act, 1965, for the words 'two months' the words 'six months' shall be *substituted.*

76. (1) The Uttar Pradesh State Universities Ordinance, 1973 (U.P. Ordinance I of 1973), is hereby *repealed*.

Repeal and savings

(2) Notwithstanding any such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall, subject to the provisions of sub-section (3) of Section 72, be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had commenced on the 18th day of June, 1973.

THE SCHEDULE

(See Section 5)

Serial No.	Name of the University	Areas within which the University shall exercise jurisdiction
1	2	3
1.	The University of Lucknow	Area within a radius of sixteen kilometers from the Convocation Hall of the University.
2.	The University of Allahabad	Area within a radius of sixteen kilometers from the Convocation Hall of the University.
[63][3.	[64][Doctor Bhimrao Ambedker University Agra]– (i) until the establishment of the University of Rohilkhand,	Districts of Agra, Aligarh, Bareily, Bijnore, Badaun, Etah, Mainpuri, Mathura, Moradabad, Pilibhit, Rampur and Shahjahanpur.
	(ii) upon the establishment of the University of Rohilkhand.	District of Agra, Aligarh, Etah, Mainpur and Mathura
[65][4.	[66][Dean Dayal Upadhyaya University of Gorakhpur– (i) until the establishment of the Purvanchal University,	Districts of Azamgarh, Ballia, Basti, Deoria, Ghazipur, Gorakhpur, Jaunpur, Mirzapur and Varanasi.
	(ii) upon the establishment of the Purvanchal University.	District of Basti, Deoria and Gorakhpur]

63. Entries 3 to 11 *subs.* by Act 29 of 1974, S. 18.
64. *Subs.* by President's Act 4 of 1996, S.12 (a) (w.e.f. 23-9-1995).
65. *Subs.* by U.P. Act 19 of 1987.
66. *Subs.* by U.P. Act 18 of 1997, S.5..

1	2	3
[67][5.	[68][[69][Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur]– (i) until the establishment of the Universities of Bundelkhand and Avadh	Districts of Allahabad, Banda, Barabanki, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jhansi, Kanpur, Lakhimpur-Kheri, Lalitpur, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur and Unnao, excepting the area which lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow.
	(ii) upon the establishment of the University of Avadh, but until the establishment of the University of Bundelkhand.	Districts of Allahabad, Banda, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jhansi, Kanpur, Lakhimpur-Kheri, Lalitpur, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur and Unnao, excepting the area which lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow.
	(iii) upon the establishment of the University of Avadh and also the University of Bundelkhand	Districts of Allahabad, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hardoi, Kanpur, Lakhimpur-Kheri, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur and Unnao, excepting the area which lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow]

67. *Subs.* by U.P. Act 21 of 1997, S.14.
68. *Subs.* by President's Act 4 of 1996, S.12 (a) (w.e.f. 23-9-1995).
69. *Subs.* by "Shri" by U.P. Act 12 of 1997, S.5.

1	2	3
6.	[Chaudhary Charan Singh University, Meerut][70]	Districts of Bulandshahr, Meerut, Muzaffarnagar and Saharanpur
7.	The University of Kumaun	Districts of Almora, Naini Tal and Pithoragarh
8.	[Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal, University][71]	Districts of Chamoli, Dehra Dun, Garhwal, Tehri-Garhwal and Uttar Kashi
9.	The University of Bundelkhand	Districts of Banda, Hamirpur, Jalaun, Jhansi and Lalitpur
10.	[Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad][72]	Districts of Buhraich, Bara Banki, Faizabad, Gonda, Pratapgarh and Sultanpur].
11.	[73][Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University Bareilly,	Districts of Badaun, Bareilly, Bijnor, Moradabad, Pilibhit, Rampur and Shahjahanpur
[74][12.	[75][Vir Bahadur Singh Purvanchal University Jaunpur]	Districts of Azamgarh, Ballia, Ghazipur, Jaunpur, Mirzapur and Varanasi].

70. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1994, S.4 (w.e.f. 17-1-1994).
71. *Subs.* by U.P. Act 26 of 1989, S.4 (w.e.f. 24-4-1989).
72. *Subs.* by President's Act 4 of 1996, S.12 (b) (w.e.f. 11-7-1995).
73. *Subs.* by U.P. Act 18 of 1997, S.5.
74. *Ins.* by U.P. Act 19 of 1987.
75. *Subs.* by U.P. Act 11 of 1999, S.4 (w.e.f. 8-1-1999).

APPENDIX A

UTTAR PRADESH SHASAN

SHIKSHA ANUBHAG - 10

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 3452/XV-X-94-6-(6)-94, dated November 14, 1994.

NOTIFICATION

No. 3452/XV-X-94-6(6)- 94

Dated : Lucknow, November 14, 1994

In exercise of the powers under sub-section (14) of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act No. 10 of 1973) as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment Act, 1974), U.P. Act No. 29 of 1974, the Governer is pleased to specify with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following other Universities to which Section 14 of the said Act shall apply :

(1) The University of Agra.

(2) The University of Kanpur.

(3) Chaudhary Charan Singh University, Meerut.

(4) Sampuranand Sanskrit Vishvavidhalaya, Varanasi.

(5) Kashi Vidhyapith, Varanasi.

(6) The University of Kumaun.

(7) Hemavati Nandan Bahuguna Garhwal University.

(8) Doctor Ram Manohar Lohia Azad University, Faizabad.

(9) The University of Bundelkhand.

(10) The University of Rohilkhand.

By order,

M. Ram Chandran,

SECRETARY

APPENDIX 'B'

The Uttar Pradesh Universities (Provisions Regarding Conduct of Examinations) Act, 1965 (U.P. Act XXIV of 1965 as amended by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973).

An Act to make provision for certain matters in connection with the conduct of examination by certain Universities in Uttar Pradesh.

It s hereby enacted in the Sixteenth year of the Republic of India as follows :

1. Short title and extent.- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Universities (Provisions Regarding Conduct of Examinations) Act, 1965.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2. Definitions– In this Act, unless the context otherwise requires –

(a) 'Centre' means any institution, or part thereof, or any other place, fixed by the University for the purposes of holding its examinations and includes the entire premises attached thereto,

(b) "Invigilaton" means a person who assist the Superintendent of a centre in conducting and supervising an examination at a centre,

(c) "Superintendent of a Centre" means a person appointed by the University to conduct and supervise its examination held or to be held at a centre, and includes an Additional Superintendent or Associate Superintendent of such centre;

(d) "Universty" means any University established by or under an Uttar Pradesh Act and declared by the State Government by Notification in the *Gazette* to be a University to which this Act applies.

3. Superintendent and invigilators to be public servant– Every Superintendent of a centre and every invigilator shall be deemed to be public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code during the course of an examination or examination conducted by the Unversity for a period of one month prior to the commencement of and of six months immediately following examination or examinations.

4. Assault, etc. on Superintendent or Invigilator– An assault or use of criminal force to a Superintendent or invigilator during the period mentioned in Section 3 shall be seemed to be an obstruction voluntarily caused to public servant in the discharge of his public function punishable under Section 186 of the Indian Penal Code (Act No. XIV of 1860), and shall notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898), be congnizable offence.

APPENDICES

(I)

The Uttar Pradesh State Universities (Centralised) Service Rules, 1975[1]

No. 6884/XV-10-75-60(24)-74, dated October 31, 1975

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, as re-enacted and amended by Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, the Governor is pleased to make the following rules for the creation of a separate service of the Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars common to all the universities to which the aforesaid Act applies and for regulating the recruitment to and conditions of service of persons appointed to any such service.

PART I

Preliminary

1. Short title, application and commencement-

(1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Universites (Centralised) Service Rules, 1975.

(2) They shall apply to all the Universities to which the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as

1. Published in *U.P. Gazette Extraordinary*, dated 31-10-1975

re-enacted and amended by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, is apphcable.

(3) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official *Gazette*.

2. Definitions.– In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) "Act" means the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended from time to time;

(b) 'Centralised Service' or 'Service' means the Centralised Service created under Rule 3 of these rules;

(c) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(e) 'Education Department' means Education Department of the Government;

(f) 'Governmen' or 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh;

(g) 'Secretary' means Secretary to Government in the Education Department;

(h) 'University' means a University to which the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 is applicable;

(i) Words and expression not defined in these rules, but used in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act.

PART II

CADRE AND STRENGTH

3. Creation of Centralised Service.– With effe from the commencement of these rules, there shall b Centralised Service common to all the Universities, whic shall consist of the following administrative posts, namely

(1) Registrars.

(2) Deputy Registrars.

(3) Assistant Registrars.

4. Scale of pay. – The scales of pay for the variou categories of posts mentioned in Rule 3 shall be such as th Government may from time to time fix.

5. Strength. – (1) The strength of each category posts mentioned in Rule 3 shall be such as the Governme may from time to time fix.

(2) All the posts mentioned in Rule 3 existing in th Universities immediately before the commencement of the rules shall from the present permanent strength of th centralised service.

(3) Any of the existng posts under the Centralise Service or any such post which the State Government ma create in future, shall not be abolished by any Universi without the prior approval of the State Government.

PART III

Recruitment

[1][6. **Source of recruitment absorption and termnation of service of existing officers.**– Subject to the provisions of Rule 7–

(a) thirty-three per cent of the posts of Registrar, all posts of Deputy Registrar and thirty-three per cent of the posts Assistant Registrar shall be filled in by promotion in the manner laid down in Rule 20; and

(b) the remaining posts of Registrar and Assistant Registrar shall be filled in by direct recruitment in the manner laid down in Part V :

Provided that any fractions, obtained up to calculation of percentage in accordance with clause (a) shall be ignored:

Provided further that notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may appoint any Government servant on deputation to any of the posts of the Centralised Service, for a period not exceeding three years.]

7. **Absorption of the existing officers.**– [(1)][2] The absorption or termination of services of the persons, serving on any of the posts mentioned in Rule 3, immediately before

1. *Subs.* by Noti No. 1506/XV-10-77, dt. 24.3.1977.
2. *Subs.* by Noti. No. 1793/XV - 10.83.35(41)-1981-UPA - 10-1973-Rule/1975-AM(4) -1982, dated 31.12.1983.

the commencement of the rules, shall be governed by the following provisions :

(a) Persons serving on the administrative post of Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar and confirmed in any one of the said posts before May 14, 1973 shall unless they opt otherwise, be absorbed in the Centralised Service finally.

(b) Other persons holding temporary or officiating appointments referred to in clause (a) above shall unless they opt otherwise, be absorbed provisionally, subject to such orders as the State Government may in each case pass under clause (c) below.

(c) The services of persons who are provisionally absorbed under clause (b) but who are not found suitable for absorption finally may, by orders of the State Government (made on or before December 31,1977) be terminated on payment of one month's salary as compensation as provided in sub-section (2) of Section 17 of the Act.

(d) If in any case, orders of the State Government are not made to the contrary under clause (c), the persons concerned shall be deemed to have been finally absorbed in the Centralised Service.

(e) Persons serving on any of the said posts immediately prior to the commencement of these rules shall be required to exercise their

option for absorption in the Centralised Service. A person who fails to communicate to the Government in the Education Department his option within a period of three months from the date of commencement of these rules shall be deemed to have opted for such absorption.

(f) The services of persons referred in clause (a) who opt against absorption, shall stand determined, with effect from the date of exercise of such option, and they shall, without prejudice to their claim to any provident fund admissible to them, be paid as compensation, the pay for the remaining period of their service in the University, or six months' pay in the case of persons whose total continuous service immediately before the commencement of these rules exceeded ten years, or three months' pay in the case of persons whose total continuous service as aforesaid did not exceed ten years, whichever is less.

(g) The amount of compensation payable under clause (c) or clause (f) shall be paid by the Universty in which the person concerned was employed immediately before the commencement of these rules.

(2) Where in the case of a person referred to in sub-section (2) of Section 17 of the Act and absorbed in the service, any particular condition of service prescribed

by these rules works out, to be less advantageous to him that that applicable to him before such absorption, then, notwithstanding anything contained in these rules, the condition applicable to him before his absorption shall apply to such person.

Explanation.– Every person to whom these rules apply, shall be liable to transfer from one University to another.

8. Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes etc. - Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Disabled Military personnel and dependents of freedom-fighters shall be in accordance with the orders of the State Government as in force at the time of recruitment.

Note.–Copies of the orders of the State Government as in force at the time of commencement of these rules will be found in Schedules 1, 2 and 3 annexed hereto.

PART IV

QUALIFICATIONS

9. Nationality.– A candidate for recruitment to any post in the Centralised Service must be–

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda any of the United Republic of Tanzania (formerly Tanzanayika and Zanzibar) with the intention of permanently settling down in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) (c) above must be a person in whose favour a certificate eligibihty has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to ategory (b) will also be required to obtain a certificate of ligibility granted by the Deputy Inspector General of olice, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category c) above, no certificate of eligibility will be issued for a eriod of more than one year, and such candidate may be etained in service after a period of one year, only if he has cquired Indian Citizenship.

Note.– A candidate in whose case a certificate of ligibility is necessary, but the same has neither been issued or refused may be admitted to an examination or interview nd he may also be provisionally appointed subject to the ecessary certificate being obtained by him or issued in his avour.

[3][**10. Age** – (i) A candidate for direct recruitment the post of Registrar and Assistant Registrar must have ttained the minimum age and must not have attained the aximum age, mentioned below, on the first day of January ext following the year in which the recruitment is made.

			Minimum	Maximum
egistrar	...	...	35	45
ssistant Registrar	...	...	30	45

Provided that the maximum age-limit shall, in the case f candidates belonging to the Scheduled Castes,

Subs. by Noti. Pub. in 1987 LLT-V-127.

Scheduled Tribes and dependants of freedom-fighters, be greater by five years :

Provded further that in respect of the posts already advertised by the commission, the age-limit shall be as provided in Rule 10 before the enforcement of the Uttar Pradesh State Universities (Centralised) Service (Fifth Amendment) Rules, 1986.

(2) In the case of a person who has already rendered at least one year's service in any of the posts in the Centralised Service or in the University, the maximum age-limit shall be greater to the extent he has rendered continuous service over the age-limits mentioned in sub-rule (i)".]

11. Character – (1) The appointing authority shall satisfy itself that the character of a candidate for appointment to any post in the service is such as may render him suitable in all respects, for employment in the Centralised Service.

(2) Every candidate for recruitment shall be required to submit certificate of character from the principal/head of the institution last attended and from two *Gazetted* Officers (not related to the candidate) in active service of the State or Union Government who are well acquainted with his private life but unconnected with his school, college or University.

(3) Persons dismissed by the Union Government or any State Government or by a Local Authority or any Government body or Corporation or Public Sector undertaking or a University shall be ineligible for appointment to the service. Any person who has been

convicted by a court of law for offences involving moral turpitude shall also be deemed ineligible.

12. Physical fitness–No person shall be appoionted to a post in the Centralised Service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his official duties. Before a candidate is finally approved for appointment to a post in the Centralised Service he shall be required to appear before the State Medical Board for medical examination and be declared fit by it.

13. Qualifications.–A candidate to any post under the Centralised Services must possess the requisite qualifications as the Commission may prescribe with the approval of the State Government.

14. Marital Status.–A male candidate who has more than one wife living and a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for recruitment to the Centralised Service :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

PART V

PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

15. Communication of the number of vacancies.–Whenever a vacancy/vacancies to a post in the service requires/require to be filled by direct recruitment, the Secretary shall send intimation about it to the Commission intimating also the number of vacancy/

vacancies. If any, reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 8.

16. Applications.–(1) Applications for recruitment to the Centralised Service shall be invited by the Commission and shall be made on the prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission and shall be submitted within such time as may be specified.

(2) Candidates already employed in the Centralised Service shall submit their applications through proper channel to the Government who shall forward them to the commision along with their periodical reports. Candidates employed elsewhere should submit their applications to the commission through their employer.

17. Scrutiny of applications, interview, etc.– Recruitment to the posts of Assistant Registrar shall be made on the basis of a competitive examination. The Commission shall scrutinize the applications received and shall admit the eligible candidates to appear at the competitive examination. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission granted by the Commission.

(2) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission, having regard to the necessity of securing due representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc. shall summon for interview such number of candidates as, on the results of the written examination, have shown their suitability for being called for such interview. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates arranged in order of merit and forward the same to the Secretary.

(4) The syllabus and the rules relating to the competitive examination will be prescribed from time to time by the Commission with the prior approval of the State Government.

(5) Recruitment to the posts of Registrar shall be made on the basis of interview alone. The Commission shall scrutinize the applications received by them and summon for interview such candidates as seem best qualified for appointment to the Service. Thereafter the Commission shall prepare a list of candidates arranged in order of merit and forward the same to the Secretary.

18. Fees.–Candidates shall pay to the Commission and to the Medical Board such fees as may, from time to time, be prescribed by the State Government. No claim for the refund of fees shall be entertained.

19. Approved list.–On receipt of the list prepared by the Commission under Rule 17, the Secretary shall, subject to the provisions of Rule 8, have the names of the candidates entered in a list in the same order in which they have been recommended by the Commission for appointment.

PART VI
PROCEDURE FOR PROMOTION

[4][**20. Vacancies to be filled by promotion–**
(1) Selection shall be made for recruitment by promotion :

(a) To the post of Registrar, strictly on merit from amongst the permanent Deputy Registrars;

(b) To the post of Deputy Registrar on the basis of seniority, subject to rejection of the unfit, from amongst the permanent Assistant Registrars; and

(c) To the post of Assistant Registrar, on merit from amongst the permanent Superintendents including permanent Superintendents (Accounts) in offices of the Universities.

(2) The selection shall be made in consultation with the Commission according to the Uttar Pradesh Selection by Promotion in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.

(3) The Selection Committee for the purposes of such selection, shall consists of–

(i) The Chairman or a member of the Commission representing the Commission who will be the Chairman of the Committee;

(ii) The Director of Education (Higher Education), Uttar Pradesh; and

(iii) One of the Vice-Chancellors of the Universities to be nominated by the State Government].

---

4. *Subs.* by Noti No. 1793/XV–10-83-35(41)–1981–UPA–10-1973–Rule/1975–AM(4)–1982, dt. 31-12-1983.

PART VII

APPOINTMENT, PROBATION AND CONFIRMATION

21. Appointment.–(1) On the occurrence of substantive vacancies, the Government shall make appointment to the various posts in the Centralised Service from the list prepared under Rule 19 or Rule 20, as the case may be.

(2) The Government may also make appointment in temporary vacancies for a period exceeding six weeks from among the persons from the list prepared under Rules 19 and 20.

(3) If no approved candidate is available for appointment the Government may either make a temporary appointment by deputation of an officer serving under the State Government or may appoint a candidate who is eligible under the rules for permanent recruitment to the Centralised Service. No such appointment shall extend beyond the period of one year without consultation with the Commission.

(4) If a vacancy arises in any post for a period not exceeding six weeks, temporary arrangements may be made by the Vice-Chancellor concerned by appointment of a person eligible under the rules.

22. Probation.–A person on appointment to the Centralised Service in or against substantive vacancy, shall be placed on probation for a period of two years:

Provided that continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre of the Centralised Service may be allowed, in whole

or in part, to be counted by the State Government towards the period of probation :

Provided further that the Government may, for sufficient reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in individual cases for a further period not exceeding two years. Any such order of extension shall specify the exact period for which the probationary period is extended.

(2) If during or at the end of the period of probation or extended period of probation, it is found that the person concerned has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to come up to the standard expected of him, he may be reverted to his substantive post, if any or if he does not hold a lien on any post his service may be dispensed with without entitling him to any compensation.

23. Confirmation.–A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct are satisfactory and his integrity is certified by the Vice-Chancellor of the University in which he has, during the period of probation, worked.

24. Seniority.–(1) Seniority in any category of posts in the Centralised Service shall be determined by the date of the order of appointment in substantive capacity to that category provided that if two or more candidates are appointed on the same date, their seniority *inter-se* shall be determined according to the order in which their names appear in the list prepared under Rule 19 or 20.

(2) Seniority of the officers in Service at the commencement of these rules may be determined in any

category of posts on the basis of total length of continuous service followed by confirmation in that category.

(3) If a dispute arises in regard to the seniority of an Officer, the matter shall be decided by orders of the Government which shall be final.

Note.–A candidate appointed directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when a vacancy is offered to him. Whether the reasons in a particular case are valid or not shall be subject to the decision of the State Government.

25. Transfer.–The State Government may transfer any member of the Centralised Service from one University to another.

PART VIII

OTHER PROVISIONS

26. Paying Authority.–Subject to the provisions of these rules, the pay and allowances of persons appointed to Centralised Service shall be paid by the University in which such person is for the time being posted.

27. Pay during probation.–(1) A person on probation, if he is not already in the permanent service of a University shall draw during the period of probation, the minimum pay of the post for the first year and increments as they accrue, provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, the extended period shall not count for increment unless the Government so directs.

(2) The pay during the period of probation of a person who is already holding a substantive post in the

service of a University before recruitment to the Centralised Service, shall be regulated in accordance with the relevant rules relating to the pay of the employees of the University.

28. Criteria for crossing efficiency bars.–(1) No member of the Centralised Service shall be allowed to cross the first efficiency bar unless he is found to have worked satisfactorily and to the best of his ability and his integrity is certified by the Vice-Chancellor of the University in which he has worked.

(2) No member of the Centralised Service shall be allowed to cross the second and subsequent efficiency bars, if any, unless he has given full satisfaction by his work, conduct, integrity and ability.

(3) Orders allowing a member of the Centralised Service to cross the efficiency bar and allowing the increment next above the bar shall be issued by University in which he is for the time being posted.

(4) On each occasion on which a member of the Centralised Service is allowed to cross an efficiency bar which had previously been withheld, his pay, with effect from the date of crossing the bar shall be fixed in the time scale at such stage as the University may decide.

29. Canvassing.–No recommendation for recruitment, either written or oral, other than those required under these rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of the candidate to enlist support either directly or indirectly for his candidature by other means shall disqualify him for appointment.

30. Leave, Leave allowances, officiating pay, fees and honoraria.–(1) Except as otherwise provided in these rules, all matters relating to leave and leave-salary shall be regulated in the manner laid down in the leave rules applicable to the Government servants of like status and all amendments thereto together with all explanation and clarification issued from time to time shall, *mutatis mutands*, apply.

(2) Grant of pay, including officiating and additional pay, special pay, honorarium, compensatory allowance subsistence allowance. to a member of the Centralised Service and the acceptance of fees, if any, shall be regulated on the same terms and conditions as are applicable to the Government Servants of the same status under the U.P. Fundamental and Subsidiary Rules contained in the U.P. Financial Handbook, Volume II, Parts II-IV.

(3) Except as expressly provided in these rules, the provisions of the U.P. Fundamental and Subsidiary Rules contained in the Financial Handbook, Volume II, Parts II-IV and travelling allowance rules contained in Financial Handbook, Volume III, shall *mutatis mutandis*, apply.

Notes.–(i) The corresponding authorities competent to exercise various powers under the said Handbook for purposes of these rules shall be such as Government may, by order, determine from time to time.

(ii) In the event of doubt the applicability of the rules etc., the decision of the Government shall be final.

31. Incidence of leave charges, ete.–The incidence of leave charges, transit, pay and allowances including

travelling allowance of a member of the Centralised Servi transferred from one University to another, shall be regulat in accordance with the following principles :

(a) When a member of the service is transferr from one University to another, his tran pay and allowances shall be borne by t University to which he is transferred.

(b) Before the member of the service is allow to draw his pay and allowances in t University to which he has been transferr the member shall produce a certificate fro the Finance Officer of the University in whi he has been serving before such transfer, the effect that such member has not draw any such pay or allowances.

(c) Leave salary shall be borne by the Univers from where such member proceeds leave.

32. Existing Provident Fund Rules to continu Till such time as a common Provident Fund for t Centralised Service is established, the member of t Service shall, unless otherwise provided in these rul continue to be governed by the Provident Fund Regulatio or Rules of the University in which they are posted for t time being :

Provided that notwithstanding anything contained the regulations or the rules of such University, the minimu amount of subscription to be made by a member of su service to the Fund shall be an amount calculated at t

rate of ten per cent of his salary (which term shall mean pay, leave salary or subsistence grant as defined in Financial Handbook, Volume II) and the contribution thereto be made by the University shall be at the rate twelve per cent of his salary in the case of a subscriber drawing a salary of more than Rs. 500 and ten per cent in the case of subscriber drawing a salary of more than Rs. 500 but not exceeding Rs. 1,000 and eight per cent in each case of a subscriber drawing a salary of Rs. 1,000 or above, both amounts being separately rounded to the nearest whole rupee (50 paise or more counting as the next higher rupee) :

Provided further that a member of the Centralised Service, who was governed by any General Provident Fund Regulations or Rules of a University immediately before his absorption in or appointment to such service shall, notwithstanding anything contained in these Rules, continue to be governed by such General Provident Fund Regulation or Rules, as the case may be, in the following manner :

(i) The subscription on account of General Provident Fund of such a member shall be deducted every month from his pay by the University in which he is posted for the time being;

(ii) The said University shall pay every month to the University in which such an officer was employed immediately before his absorption in or appointment to the Centralised Service his subscription to the General Provident Fund; and

(iii) The University where such an officer was employed immediately before his absorption

or appointment shall be liable to pay General Provident Fund to him after his retirement and to the members of his family in accordance with the said General Provident Fund Regulations or Rules, as the case may be.

33. Provident Fund in the case of transfer.–Immediately upon transfer of a member of the Centralised Service from one University to another, otherwise than in a leave arrangement not exceeding 120 days, a new Provident Fund Account shall be opened in the name of such member under the University to which he has been transferred and the Vice-Chancellor of the University from where he has been transferred shall, within thirty days from the date of such transfer, forward to the University to which he has been transferred, a full and complete account of the member's Provident Fund and cause to be transferred to his new account the amount standing to his credit in the old account alongwith interest calculated up to the month in which the account is so transferred. All further interest on such amount as from the next succeeding month, shall be payable by the University where the new account has been opened.

34. Intimation to be sent promptly.–In the circumstances other than those mentioned in Rule 33 the member of the Centralised Service shall continue to subscribe to his existing Provident Fund and tender such further amounts as may be required to him in connection therewith and the University administering the Fund shall continue to credit its own contribution thereto, and it shall be incumbent on the University to which the officer has

been transferred to inform with all reasonable despatch the University from where such member has been transferred, the exact amount of his emoluments. Intimation about every change therein shall similarly be sent promptly.

35. Responsibility of the University.–The responsibility for payment upon an amount becoming due shall devolve on the University which is responsible for maintaining the Provident Fund for the time being.

[5][**36. Disciplinary proceedings.**–(1) Subject to such modifications as the State Government may make from time to time, and subject to the provisions of sub-rules (2) to (9), the rules relating to disciplinary proceedings, appeals and representations against punishment, applicable to the employees of the State Government shall, *mutatis mutandis* apply to the members of the Centralised Service.

(2) The power to start disciplinary proceedings and to impose –

(a) the punishment of dismissal or removal from service or reduction in rank on the members of the Centralised Service shall vest in the State Government; and

(b) other punishments shall vest in the Vice-Chancellor of the University in which the member of such service is for the time being posted :

Provided that it shall be necessary to consult the Commission before passing an order imposing any of the punishments referred to in clause (a).

5. *Subs.* by Noti. dated 14.12.1979.

(3) Where disciplinary proceedings against a member of the Centralised Service have been started in accordance with the provisions of sub-rule (2)–

(a) by the Vice-Chancellor and after the completion of inquiry, he comes to a provisional conclusion that a punishment referred to in clause (a) of sub-rule (2) is called for, he shall refer the case along with his findings and recommendations to the State Government for orders ;

(b) by the State Government and, during or after the completion of inquiry, it comes to a provisional conclusion that a punishment to which clause (b) of sub-rule (2) applies is called for, it shall refer the case to the Vice-Chancellor who shall pass such orders as he deems fit, and shall send a report of the action taken to the State Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (3), the State Government may direct the Vice-Chancellor of a University in which any member of the Centralised Service is for the time being posted to start disciplinary proceedings against him and to inform it of the result thereof or, as the case may be, refer the case to the State Government for its final orders under clause (a) of sub-rule (3).

(5) Where the Vice-Chancellor of any University wants to start disciplinary proceeding against a member of the Centralised Service. who has been transferred to some other University, he shall submit a report to the State

overnment to that effect, and thereupon, the State overnment may –

(i) itself proceed in accordance with clause (a) of sub-rule (2); or

(ii) direct the Vice-Chancellor of the first mentioned University to start and conclude the inquiry in accordance with clause (b) of the said sub-rule or, as the case may be, refer the case to the State Government for its final order under clause (a) of sub-rule (3) ; or

(iii) direct the Vice-Chancellor of the University in which such member is for the time being posted to start and conclude the inquiry against such member and inform the State Government of the result thereof or, as the case may be refer the case to the State Government for its final order under clause (a) of sub-rule (3).

(6) Where the Vice-Chancellor of a University is mpetent to start disciplinary proceedings under this Rule, may hold the inquiry himself or may appoint any other ficer of the University for the purpose.

(7) The State Government may, at any stage, transfer y proceedings under this rule from one officer to another ficer in the same University, or from the Vice-Chancellor one University to the Vice-Chancellor of any other niversity, and, unless any direction is issued to the ntrary, the officer or the Vice-Chancellor to whom such

proceedings are transferred shall continue the proceedings from the stage at which it was so transferred.

(8) During the course of inquiry under this rule, the Vice-Chancellor or the officer appointed by him as inquiry officer under sub-rule (6) may exercise all the powers of the inquiring authority under the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1976.

(9) Notwithstanding anything contained in these rules, it shall be lawfull for the State Government to direct that the disciplinary proceedings against any member of the Centralised Service may be started in respect of any act or omission relating to the period before the date of his absorpiton in such service under Rule 7 and thereupon the provisions of sub-rules (1) to (8) shall *mutatis mutandis* apply.

37. Age of retirement.–(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the age of retirement from service of the member of the Centralised Service shall be 60 years beyond which no one shall be retained in the Service.

(2) The State Government may require a member of the Centralised Service to retire on his attaining the age of 57* years on three months notice or pay in lieu of the whole or part thereof if the State Government considers it necessary to do so in public interest.

(3) A member of the Centralised Service may, on attaining the age of 57* years, voluntarily retire after giving

---

* 57 years *subs.* by 52 years vide Govt. Order No. 5051/XV-10-92-35(5) 88, dated Feb. 18. 1993.

three months notice to the State Government. In case of the member against whom disciplinary proceedings are pending or contemplated, this notice shall be effective only when it is accepted by the State Government. A notice once given under this sub-rule shall not be withdrawn without the permission of the State Government.

38. Reference to the State Government.–(1) If any dispute arises as to liability of a University for payment of salary, travelling allowance, Provident Fund or any other dues to a member of the Centralised Service, or if any dispute or difficulty arises regarding interpretation of any of the provisions of these rules, the same shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final and conclusive.

(2) Matters not covered by these rules shall be governed by such rules or orders as the State Government may from time to time make.

39. Power to grant exemption. – Notwithstanding anything contained in these rules, where the State Government is satisfied that the operation of any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may in consultation with the Commission by order dispense with or relax the requirements of that provision to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with case in a just and equitable manner.

40. Power to delegate.–The State Government may, by notification published in the official *Gazette*, delegate any of its powers under these rules, to any person or authority on such conditions as it thinks fit.

(II)

The Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970[1]

No. 42/4/66 - Apptt. (B) dated Lucknow, October 6, 1970.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

PART I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement— (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.

(2) They shall come into force at once.

2. Extent of application— These rules shall apply to all services and posts in connection with the affairs of Uttar Pradesh to which recruitment by promotion is required to be made by selection in consultation with the Uttar Pradesh Public Service Commission otherwise than on the results of a competitive examination.

3. Overriding effect of these Rules.—The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith in any service rules in force immediately before the commencement of these rules.

1. Published in *U.P. Gazette Extraordinary*, dated 6-7-1970 and *amended* by *U.P. Gazette Extraordinary*,. dated 4-7-1972.

4. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) 'Appointing authority' in relation to any service or post means the authority empowered to make appointments to that service or post, and in the case of the Governor being the appointing authority includes the Chief Secretary to Government or the Secretary or Special Secretary to Government in the Department concerned.

(b) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(c) 'Governor' means the Government of Uttar Pradesh;

(d) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(dd) Select List means the list of candidates selected for temporary or officiating appointment in accordance with the rules or orders in force prior to the commencement of these rules.

(e) 'service rules' means rules, regulations or government orders regulating recruitment to, or the conditions of service of persons appointed to any service or post in connection with the affairs of Uttar Pradesh;

(f) 'year of recruitment' means the period of twelve months beginning from the first day of July of a calendar year.

PART II

CRITERIA FOR PROMOTION

5. Criteria for promotion.—(1) Where any service rules provide either 'strict merit' or 'primarily on merit' or 'rigorous selection on merit from the whole field of eligibility' or 'strictly on merit' or 'seniority counting where merits are equal' or any such other criterion howsoever expressed, as lays primary stress on merit as the basis of selection for promotion, the criterion to be followed on and after the commencement of these rules shall be 'merit'.

(2) Where any service rules provide either 'seniority' or 'seniority-cum-fitness' or 'seniority subject to the rejection of the unfit' or any such other criterion, howsoever expressed, as lays primary stress on seniority as the basis of selection for promotion, the criterion to be followed on and after the commencement of these rules shall be 'seniority subject to the rejection of the unfit'.

(3) In all cases in which no service rules exist or in which the service rules do not lay down clearly which of two criteria for promotion mentioned in sub-rules (1) and (2) is to be followed, such criterion of the two shall be followed as may be decided upon by the Governor in consultation with the Commission.

6. Other conditions of eligibility.— (1) Nothing in these rules shall affect any provision in any service rule in respect of the conditions of eligibility for promotion relating to age, educational or technical qualification, nature of experience or length of service except to the extent that the relevant date with reference to which a candidate shall be deemed to have fulfilled such conditions shall be the date of commencement of the year of recruitment.

(2) In the absence of any provision in the service rules in respect of the conditions of eligibility as aforesaid, the said conditions shall be such as may be determined by the Governor in consultation with the Commission.

PART III

PROCEDURE OF PROMOTION WHERE THE CRITERION IS MERIT

7. Application of this Part.—Where by virtue of the provisions of Rule 5 promotion is to be made on the criterion of merit the procedure laid down in this Part shall be followed.

7-A. Notwithstanding anything contained in these rules, but subject to the proviso to Rule 18, the names of candidates on the select list appointed in temporary or officiating vacancies prior to the date of issue of this notification shall be re-arranged in order of seniority.

7-B. The candidates of the Select List as re-arranged in accordance with Rule 7-A, shall be appointed against substantive vacancies in preference to any candidate selected in accordance with the provisions of these rules.

8. Preparation of eligibility list.— The appointing authority shall prepare a list (hereinafter in this Part referred to as the eligibility list) of the seniormost eligible candidates containing names so far as may be in the following proportion:

For 1 to 5 vacancies	Five times the number of vacancies subject to a minimum of 15.

For 6 to 12 vacancies	Four times the number of vacancies subject to a minimum of 25.
For over 12 vacancies	Three times the number of vacancies subject to a minimum of 50 :

Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year. In such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be–

(a) for the second year	the number according to said proportion plus the number of vacancies in the first year;
(b) for the third year	the number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second years

and so on :

Provided further that candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names :

Provided also that in the case of higher research posts in departments in which research work is done, the names

of all eligible candidates shall be included in the list irrespective of the number of vacancies.

Explanation 1.—

In this rule—

(a) 'the number of vacancies' means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies occurring during the year of recruitment after taking into account the probable absorption of candidates of the Select List (as re-arranged in accordance with Rule 7-A) or of List 'B' against substantive vacancies.

(b) 'higher research posts' means posts requiring technical knowledge and ability of a high order undertaking and guiding research work.

Explanation II.—A single eligibility list shall be prepared to cover all types of vacancies.

9. Sending of list Commission.—The appointing authority shall forward to the Commission the eligibility list or lists together with the gradation list of all persons within the field of eligibility and the character rolls of the candidates included in the eligibility list or lists and also intimate to it the numbers of different types of vacancies takekn into account for the purpose of preparing the list or lists.

10. Revision of eligibility list.—If in any case the Commission feels that the requisite number of suitable candidates may not be available from amongst those whose names are included in the list or lists received by it under

Rule 9, it may ask the appointing authority to include therein the names and character roll of such larger number of the seniormost or of all eligible candidates, as it thinks fit and the appointing authority shall notwithstanding anything contained in Rule 8, revise the list or lists accordingly.

11. Selection Committee.—A Selection Committee consisting of the following shall be constituted by the appointing authority—

(i) the Chairman or Member representing the Commission who will be the Chairman of the Committee;

(ii) the appointing authority; and

(iii) a senior officer of that or any other department nominated by the Government, provided that where the appointing authority is the Governor, the head of that department shall ordinarily be nominated under this clause.

12. Fixing of date for selection.—(1) The appointing authority shall in consultation with the Commission fix a date for selection :

Provided that the process of selection may spread over the dates more than one.

(2) In case the Commission or the appointing authority considers it necessary that all or any of the candidates included in the eligibility list or lists should be interviewed by the Selection Committee, the appointing authority shall call such candidates or candidate, as the case may be, for the purpose on the aforesaid date or dates.

(3) The Selection Committee shall in each case consider the character rolls of the candidates and may consider any other factor relevant in its opinion.

13. Lists A and B.—(1) The Selection Committee shall prepare two lists in order of merit as follows namely:

(i) *List A*—Containing names of candidates recommended for substantive appointment against the permanent vacancies intimated to the Commission under Rule 9;

(ii) *List B*—Containing names of candidates recommended for temporary or officiating appointments intimated to the Commission under Rule 9 as well as the names of candidates, if any, carried over on review from pending List B in accordance with sub-rule (2) of Rule 16 :

Provided that if recruitment is made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year. In such a case the names of candidate selected against vacancies of one year will be excluded from the eligibility list or lists of subsequent year or years, as the case may be, before making the selection from the eligibility list of the second and subsequent years.

(2) Notwithstanding anything in sub-rule (1) List A need not be prepared in case the number of permanent vacancies does not exceed the number of candidates of the Select List (as re-arranged in accordance with

Rule 7-A) or of List 'B' remaining to be absorbed in permanent vacancies.

14. Commission's approval.—The Commission shall consider the recommendations of the Selection Committee and thereafter send the Lists A and B as approved to the appointing authority.

15. Re-arrangement of each list in order of seniority.—Subject to the provisions of sub-rule (1) and the proviso to sub-rule (2) of Rule 16, the appointing authority shall rearrange each of the Lists A and B in order of seniority.

16. Duration of Lists.—(1) The names of candi- dates, included in List A, for whom permanent vacancies cannot be found during the year of recruitment shall, at the end of the year, be transferred to the top of List B in the order in which their names appear in List A as re-arrnaged under Rule 15.

(2) The names of candidates included in List B fo whom vacancies cannot be found during the year shall be reviewed at the time of every succeeding selection and in case the Selection Committee constituted for the succeed ing year of recruitment considers that the work or condu of any candidate since preceding selection justifies it ma remove his name from that list. Provided that candidat who are selected for List B for the first time shall be plac below those already on the List.

17. Appointment from List A.—(1) Candidat included in List A, shall be appointed against perman vacancies in the order in which their names appear in t List as rearranged under Rule 15.

(2) Candidates included in List A, for whom permanent vacancies are not immediately available, shall be appointed, in the said order, against temporary or officiating vacancies in preference to those included in List B.

18. Appointment from List B.—Subject to the provisions of sub-rule (2) of Rule 17 candidates included in List B shall be appointed in the order in which their names appear in the List as re-arranged under Rule 15 against temporary or officiating vacancies and after List A is exhausted also against permanent vacancies :

Provided that if it appears to the appointing authority at any time that a government servant appointed against a temporary or officiating vacancy has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, it may revert him to the post from which he was promoted without assigning any reason.

19. Absorption of List B candidates in substantive vacancies.—Subject to the provisions of Rule 18, candidates remaining in List B shall be appointed against fresh substantive vacancies in preference to any candidate selected for List A at the succeeding year of recruitment for the first time.

PART IV
PROCEDURE OF PROMOTION

When the Criterion is Seniority subject to the rejection of the Unfit

20. Application of this Part.—Where by virtue of the provisions of Rule 5, promotion is to be made on the criterion of seniority subject to the rejection of the unfit, the procedure laid down in this Part shall be followed.

21. Preparation of Eligibility List.—(1) Except as otherwise provided in Rule 22 the appointing authority shall prepare a list to be called the eligibility list of the seniormost, eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion :

For 1 to 5 vacancies	2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5
For over 5 vacancies	1 ½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10.

The provisions and explanations of Rule 8 shall mutatis mutandis apply to this rule.

(2) The rest of the procedure prescribed in Part III shall *mutatis mutandis* apply to promotion made under this Part except that each of the two Lists A and B referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit and that from among those considered fit the seniormost candidates shall be placed in List A.

22. Power to dispense with Selection Committee in certain cases.—Notwithstanding anything in Rule 21 if in any case the number of vacancies to be filled is small, and the appointing authority considers the seniormost candidate or candidates clearly fit for promotion and accordingly no supersession is involved, the commission may, if it agrees with the view of the appointing authority, approve the proposal straightaway. In that case no Selection Committee need be constituted and the candidate

or candidates so approved shall be deemed to have been duly selected for promotion.

(III)

Rules for admissions to courses of instruction for degrees in Education in Affiliated or Associated Colleges of State Universities, 1983

English translation of Shiksha Anubhag-II, Noti. No. Shiksha (II) – 2929/ XV-83(11)-3(58)-79 dated May 17, 1983, published in U.P. Gazette, Extra., dated 17th May, 1983, pp. 6-10

In exercise of the powers under sub-section (5) of Section 28 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974), the Governor is pleased to supersede all previous Rules and Orders relating to admission to courses of instruction for degrees in Education in Colleges affiliated to or associated with Universities established under the aforesaid Act and to direct that such admission shall be regulated hereafter by the Rules appended hereto.

CHAPTER I

GENERAL

1. Short title.—These rules may be called the rules for admission to courses of instruction for Degrees in Education in Affiliated/Associated Colleges of State Universities. These Rules shall come into force with effect from the academic session 1983-84.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise required—

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974.

(b) 'College' means such college as is duly affiliated to or associated with a University established under the Act;

(c) 'Course of Instruction' means such course of instruction as is imparted in a college for preparing students for admission to examination for B.Ed. or as the case may be M.Ed. degree conducted by the University to which such college is affiliated or associated.

(d) 'University' means the University to or with which the college where admissions to a course of instruction is sought or made is affiliated or associated.

CHAPTER II

ADMISSION TO B.Ed. CLASSES

3. Qualifications for admission.—The minimum educational qualification requisite for the admission of a candidate to B.Ed. Classes shall be the graduate degree with at least two school-teaching subjects, of a University established by law.

Explanation.—A candidate who has passed an examination for the degree of B.A. with Education or Psychology or Philosophy as one of the subjects and any one of the school-teaching subjects as another subject or

B.Com. or B.Sc. (Ag.) or B.Sc. (Home Science) as the case may be shall be deemed to possess the minimum qualification within the meaning of this Rule.

But if a candidate has offered one school-teaching subject or Education or Psychology or Philosophy at the graduation level and has thereafter passed an examination at the graduation/postgraduation level with another school-teaching subject shall also be deemed to possess the minimum qualification within the meaning of this Rule.

4. Maximum number approved for admissions to B.Ed. Classes.—[1][(1) The maximum number of students to be admitted in every college shall be such as may be prescribed by the Vice-Chancellor of the University and no person shall be admitted in excess of such number in any case. In prescribing the maximum number of students to be admitted the Vice-Chancellor shall take into account the teachers available in the college concerned for B.Ed. instructions, so as to maintain the teacher-pupil ratio at 1:15.

(2) In a college having Science classes also the number of seats for candidates holding a B.Sc. Degree shall be prescribed by the Vice-Chancellor. In prescribing such number of seats, the Vice-Chancellor shall take into account the number of Science teachers available in the B.Ed. Department of the College so as to maintain in respect of such candidates the teacher-pupil ratio at 1:15.]

5. Reservation of seats.—In every college, reservation of seats for admission to B.Ed. Classes shall in relation to the total number of seats in such college be made in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes,

---

1. *Subs.* by Noti. Pub. in 1984 LLT-V-141.

Backward Castes and Handicapped candidates to the extent of 18 per cent, 2 per cent, 10 per cent and 2 per-cent respectively :

Provided that where sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Castes and handicapped candidates is not available for admission such seats as are reserved for them and remain unfilled shall be filled by the general candidates.

Note.—A handicapped candidate shall have to submit along with his application a certificate from the Chief Medical Officer of the district to the effect that though he is handicapped he is not dumb, deaf, does not stammer, or does not suffer from skin disease or any other disease which is likely to spread among children or cause hindrance in class teaching.

6. Application for admission.—(1) Every candidate for admission to B.Ed. classes shall apply in the manner hereinafter provided in the prescribed form to be obtained from the office of the Registrar of the University concerned on payment of Rs. 3 for each form. The last date for applying for admission shall ordinarily be the 31st day of May or such date in the month of June as the University may prescribe.

(2) The candidate shall send by registered post one copy of the application to the Registrar of the University.

(3) Another copy of such application containing the number and date of the postal registration receipt shall be sent to the college by registered post.

(4) No such application received in the office of Registrar or the college after such date as may be prescribed by the University in this behalf shall be entertained.

7. Basis of selection.—In respect of every candidate for admission to a course of instructions in B.Ed. classes; a statement of marks allotted to him shall be prepared in the manner hereinafter provided and the candidates shall subject to the other provisions of these rules be admitted to such course of instruction strictly on the basis of such marks in order of merit.

8. Allotment of marks.—(1) Every candidate shall be allotted marks equal to a total of percentage of total marks obtained by him in each of the High School, Intermediate and graduate examinations and one-fourth of the percentage of marks obtained by him in the postgraduate examination and such additional marks, if any as he may be entitled to under these Rules.

Explanations.—(a) Where a candidate has passed the Higher Secondary Examination and thereafter graduated after passing a three-year degree course, marks shall be allotted to him equal to a total of twice the percentage of marks obtained by him in the Higher Secondary Examination and marks obtained in the graduation examination.

(b) Where a candidate has passed more than one postgraduate examination, he shall be allotted one-fourth of the marks which the candidate has indicated in his application under Rule 6.

(2) A candidate falling under any of the categories specified below shall on furnishing such certificates as may be specified by the University in that behalf be allotted extra marks indicated against each but the total of extra marks thus obtained shall not exceed twenty-five.

(1) Candidates taking part in National or State or Inter-University games and sports competition. 15 Marks

(Certificates of participating in the National or State level games or sports competitions issued by the Government Sports Department only shall be accepted).

(2) Candidates taking part in Inter-College Sports competition conducted by any University 10 Marks

(3) Male candidates obtaining 'C' certificates and female candidates obtaining 'G-2' certificates in the National Cadets Corps 15 Marks

Or

Male candidates obtaining 'B' certificates and female candidates obtaining 'G-1' certificates. 10 Marks

Or

Candidates serving for 240 hours and participating in two or more special camps in National Service Scheme. 15 Marks

Candidates serving for 240 hours and participating in one special camp in National Service Scheme. 10 Marks

Or

Candidates serving for 240 hours in National Service Scheme 5 Marks

(4) Candidates related to a freedom-fighter as his son or daughter or his son's son or his son's unmarried daughter (this concession shall cease after the year 1985) 15 Marks

(5) Candidates being defence employee in active service or demobilised or honourably retired or related to such

an employee or a disabled, diseased or traceless defence employee as his son, daughter or wife. 15 Marks

(6) Candidates employed in Police or PAC or Homeguard or B.S.F. for S.S.B. or ITB or CRP or Civil Defence Organisation or related to such an employee whether in active service or retired, disabled or diseased as his son or daughter 15 Marks

(7) Candidates being widows or divorced or abandoned women (such candidates shall furnish legal certificates to this effect) 15 Marks

(8) Son/Daughter/Wife of Teacher or non-teaching employee of any recognised educational institution.

15 Marks

Illustrations.—A candidate, who has secured 55 per cent marks in the High School Examination, 50 per cent marks in Intermediate Examination, 52.2 per cent marks in graduation examination and 60 per cent marks in the postgraduation examination shall be allotted 172.2 Marks [55 + 50 + 52.2 + 15 (One-fourth of 60 per-cent) = 172.2].

If this candidate obtains extra 30 marks on furnishing prescribed certificates under Rule 8(2) then out of these extra marks 25 extra marks only, shall be added to the marks allotted above. Thus the total of all marks allotted to this candidate will be 197.2.

(3) If marks obtained on the basis of the above Rules 8 (1) and 8(2) are of equal preference shall be given to that candidate who has graduated from the same University to which the college in which he is seeking admission, is

2. *Added* by Noti. Pub. in 1985 LLT-V-93.

affiliated or associated, but no extra marks shall be allotted on this account to that candidate.

9. Preparation of list of candidates in order of merit.—(1) On receiving the applications under Rule 6 there shall be prepared in quadruplicate in every college in respect of such applications, two lists namely list 'A' for the reserved seats and the list 'B' for unreserved seats, containing the names in order of merit of qualified candidates together with the particulars mentioned in Rule 8.

(2) The list prepared under this Rule duly signed by the Principal of the college shall be sent to the University within one week from the last date fixed for submission of applications under Rule 6.

10. Selection Committee.—(1) For selection of candidate for admission to the B.Ed. Classes there shall be a selection committee consisting of the following three members for every college, namely :

(i) A nominee of the Vice-Chancellor of the University (who shall also be convener of the Committee).

(ii) A nominee of the Director of Education (Higher Education).

(iii) Principal of the college or in his absence the seniormost teacher of the B.Ed. Department of the college.

(2) The selection committee shall hold its sittings at the headquarters of the University or with prior approval of the Vice-Chancellor, in the College.

(3) All the applications for admission received in the college as well as the lists of candidates forwarded to the University under Rule 9 shall after comparison with the application received in such University and due verification be placed before the selection committee.

(4) The selection committee shall on a consideration of the applications and lists referred to in sub-rule (3) prepare in order of merit list of candidates fit for admission.

(5) The list prepared under sub-rule (4) shall contain the names of candidates selected for admission to the reserved and the unreserved seats available in the college as well as the marks allotted to each such candidate under these Rules.

(6) The selection committee shall also prepare a waiting list of such candidates as may be admitted in a college in accordance with these Rules in the event of the failure of a candidate included in the list under sub-rule (5) to join the college.

(7) The selection committee shall prepare the lists under sub-rule (5) or sub-rule (6) ordinarily by the end of June and shall forthwith furnish one copy thereof to the University and another copy thereof to the college.

(8) In the event of any one member of selection committee being absent, the proceedings of selection shall not be rendered illegal.

11. Admission of selected candidates.—(1) The Principal of the college shall send intimation by registered post at the earliest to every candidate whose name is included in the list prepared under sub-rule (5) of Rule 10

and that candidate shall within fifteen days of the date of registration of intimation in the post office, take admission in that college and on his failure to do so he shall forfeit his claim to admission.

(2) Where any seat falls vacant under sub-rule (1) it may be filled by the admission of a candidate out of the candidates in serial order included in the list prepared under sub-rule (6) of Rule 10.

12. Medical Certificate.—Every candidate selected under Rule 10 shall have to furnish, before admission, a certificate given or countersigned by the Chief Medical Officer in which it should be clearly mentioned that the candidate does not stammer and on account of any disease of the ear, the eye or any other limb, is not unfit to be a teacher.

13. Disqualification for admission in certain cases.—Notwithstanding anything in these Rules where it is discovered that a candidate has been punished on account of using unfair means in any examination or has been expelled from any educational institution the Principal of the college may, subject to the approval of the Vice-Chancellor of the University, refuse to admit such candidate.

CHAPTER III
ADMISSION TO M.Ed. CLASSES

14. Introductory.—The provisions of this Chapter shall apply for admission to a course of instruction in M.Ed. classes only in any college.

15. Academic qualifications for admission.—(1) No person shall be admitted in any college unless he has

passed an examination for the degree of B.Ed. conducted by a University established by law or an examination for the diploma of recognised B.T. or L.T.

(2) Only those applications for admission to M.Ed. will be considered where the candidates, according to the statutes of the concerned University, fulfil all other qualifications except M.Ed., for appointment as a lecturer in B.A. (Education) or in the B.Ed. department in the degree colleges of the State.

16. Admission according to merit.—Candidates shall be admitted strictly in order of merit on the basis of percentage of marks obtained in the B.Ed. or its equivalent other recognised examinations, full marks obtained in the theory and fifty per cent marks obtained in the practical examination shall be considered in calculating the percentage.

Illustration.—If a candidate has secured 240 marks out of 500 in the Theory and 140 marks out of 200 in the Practical Examination, there for the sake of calculation, the full marks obtained by him will be 240 + (140/2 or 70) = 310 and his percentage will be 44.28 (310+100)/700.

17. Application of Rules of Chapter II.—The provisions of Rules 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 shall *mutatis mutandis* apply to admission under this Chapter also.

(IV)
The Uttar Pradesh State Universities (Va. tion of Appointments) Act, 1984[1]
[U.P. ACT No. 18 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to validate certain appointments, made in the State Universities.

It is hereby enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :

1. Short title and commencement.—This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Validation of Appointments) Act, 1984.

(2) It shall be deemed to have come into force on August, 16, 1984.

2. Validation of appointments.—Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court or order of any officer or authority or anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or Statutes framed thereunder, the appointment of every teacher made in any University governed by the said Act or in any affiliated or associated college thereof during the period July 1, 1978 and the date of commencement of this act, in excess of the number of posts advertised, shall be and be deemed always to have been valid and validity of such appointments shall not be called in question before any court, tribunal, officer or authority merely on the ground that the post was not separately advertised or that the prescribed procedure was not followed.

1. Received the assent of the Governor on September 29, 1984 and published in *U.P. Gazette, Extra.*, dated 1st October, 1984. p. 2.

3. Repeal and savings.—(1) The Uttar Pradesh State Universities (Validation of Appointments) Ordinance, 1984 (U.P. Ordinance No. 16 of 1984) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

(V)

The Uttar Pradesh State Universities (Reservation in Admission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Order, 1984[2]

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (5) of Section 28 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President Act No. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act No. 29 of 1974), the Governor is pleased to make the following order :

1. (1) This order may be called the Uttar Pradesh State Universities (Reservation in Admission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Order, 1994.

(2) It shall come into force at once.

2. [(1)][3] Subject to the provisions of sub-section (5) of Section 28 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, with effe ct from the academic session of 1994-95,

2. Vide. Noti. No. 2638/XV-X-94-15(66)-89, dated July 20, 1994, published in the *U.P. Gazette, Extra.*, Part 4, Section (Kha), dated 20th July 1994, pp. 2-3.
3. *Renumbered* by Noti. No. 3509/XV-10-94-15(66)-89, dated 30-8-1994 (w.e.f. 30-8-1994).

following percentages of seats in any course of study in a University, Institute. Constitutent, College, Affiliated college or Associated college shall be reserved for admission for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens, namely :

Scheduled Castes	Twenty-one per cent
Scheduled Tribes	Two per cent
Other Backward Classes of Citizens	Twenty-seven per cent :

Provided that where any University has provided for Reservation in admissions in favour of any other category of candidates than those referred to above, the candidate selected for admission on the basis of such reservation shall be placed in the appropriate category to which he belongs. For example, if a candidate, selected for admission in any course of study on the basis of reservation in favour of sports person, belongs to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other Backward classes, he will be placed in the respective category to which he belongs by making necessary adjustments and similarly, if he belongs to general category, he will be placed in that category after making necessary adjustment :

Provided further that the seats, if any, reserved under any other law for the time being in force, or under any order of the Government of India, for the students belonging to any other State, shall not be included in the total number of seats for the purpose of computing the percentages under this paragraph.

Explanation.—For the purposes of this Order the erm general category, means the category other than those eferred to in paragraph 2.

[4][(2) The reservation in admission as provided in sub-aragraph (1) shall also apply in any course of study in an Jniversity, Institute or such College in respect of any cademic session, prior to academic session 1994-95, for vhich admissions are to be made].

3. If eligible candidates belonging to the Scheduled ribes are not available to fill the seat reserved for them nder paragraph 2, such seat shall be filled by candidates elonging to the Scheduled Castes.

4. Subject to paragraph 3, where due to non-vailability of eligible candidates any of the seats reserved nder paragraph 2 remains unfilled, it shall be filled by a andidate of general category.

Explanation.—For the purposes of paragraphs 3 nd 4 is clarified that a candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes of itizens shall not be ineligible if he fails to secure the minimum ualifying marks, if any, in any admsision test or under any orm relating to admissions.

5. If a candidate belonging to any of the categories nentioned in paragraph 2 gets selected for admission on ne basis of merit with general category candidates, he shall ot be adjusted against the seats reserved for such category nder paragraph 2.

Ins. by Noti. No. 3509/XV-10-94-15(66)-89, dated 30-8-1994 (w.e.f. 30-8-1994).

6. The teachers, belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes or Other Backward Classes of Citizens shall, so far as possible, be given representation in the admission committees to ensure fair admissions.

7. The Chairperson of the admission committee and the Vice-Chancellor in the case of a University and such chairperson and the Head of Institution in any other case shall be responsible for due observance of this order.

8. Whoever wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this order shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(VI)

Notification

English translation of Shiksha Anubhag-10, Noti No. 3452/XV-X-94-6(6)-94, dated November 14, 1994, published in the U.P. Gazette, Extra., Part 4

Section (Kha), dated 14th November, 1994, p. 2.

In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 14 of the Uttar Pradesh State Universities Act 1973 (President's Act No. 10 of 1973) as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974 the Governor is pleased to specify with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following

other Universities to which Section 14 of the said Act shall apply :

1) The University of Agra
2) The University of Kanpur
3) Chaudhary Charan Singh University, Meerut
4) Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi
5) Kashi Vidyapith, Varanasi
6) The University of Kumaun
7) Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
8) Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad
9) The University of Bundelkhand
10) The University of Rohilkhand

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 488/सत्रह–वि–1–1 (क) 5–1994

लखनऊ, 23 मार्च, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 मार्च 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित **अधिनियम** बनाया जाता है –

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2 – इस अधिनियम में – परिभाषाएं

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है ;

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से हैं ;

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं :–

(एक) स्थानीय प्राधिकारी;

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो ;

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूंजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो ;

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश

अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है ;

(पांच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन आच्छादित नहीं है ;

(घ) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के, प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, से है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण

3 – (1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोजगार रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में : इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जन–जातियों के मामले में : दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में : सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाय।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी भर्ती में अनुसूचित जन–जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक वह समाप्त न हो जाय।

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति

4–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2) राज्य सरका, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उस सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

शास्ति

5– (1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है,

इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

अभिलेख मांगने की शक्ति

6— यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

चयन समिति में प्रतिनिधित्व

7— राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी आवश्यक समझी जाय और जहां ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन—जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम—निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

छूट और शिथिलीकरण

8—(1) राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में आदेश द्वारा, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और

उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।

जाति प्रमाण–पत्र

9 – इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण–पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करना

10 – यदि इस अधिनियम के उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

11 – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

12 – राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

13 – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तद्नुसार संशोधित समझा जायगा।

आदेशों इत्यादि का रखा जाना

14 – धारा 3 की उपाधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

15 – (1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण – जहां सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार –

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहां यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर ; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहां लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

निरसन और अपवाद

16 – (1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों

और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यावाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या ल्कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारत्वान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची – एक

(देखिए धारा 2 (ख))

1. अहीर
2. अरख
3. काछी
4. कहार
5. केवट या मल्लाह
6. किसान
7. कोइरी
8. कुम्हार
9. कुर्मी
10. कम्बोज
11. कसगर
12. कुंजड़ा या राईन
13. गोसाई
14. गूजर
15. गड़ेरिया
16. गद्दी
17. गिरि
18. चिकवा (कस्साब)
19. छीपी
20. जोगी
21. झोजा
22. रूफाली
23. तमोली
24. तेली
25. दर्जी
26. धीवर
27. नक्काल
28. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
29. नायक
30. फकीर
31. बंजारा
32. बढ़ई
33. बारी
34. बैरागी
35. बिन्द
36. बियार
37. भर
38. भुर्जी या भड़भूजा
39. भठियारा
40. माली, सैनी
41. मनिहार
42. मुराव या मुराई
43. मोमिन (अंसार)
44. मिरासी
45. मुस्लिम कायस्थ
46. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी
47. मारछा
48. रंगरेज
49. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
50. लोहार
51. लोनिया
52. सोनार
53. स्वीपर (जे अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
54. हलवाई
55. हज्जाम (नाई)

अनुसूची – दो

[देखिये धारा 3 (1)]

1 – निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री :–

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा से पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य ; या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसा सेवा में सीधी भर्ती से आया हो ; या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक शोध या किसी अन्य संस्था के समूह "क"/श्रेणी–एक का ऐसा अधिकारी जो उप–श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है ; या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह "क"/ श्रेणी–एक का ऐसा अधिकारी जो उप–श्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है ; या

(ङ) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो :

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमाह दस हजार रूपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

2 – चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टाक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री :

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

4 – किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाइयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रूपये से अधिक हों और ऐसी इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

5 – किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियत सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रूपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।

6 – किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रूपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रूपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

No. 488(2)/XVII-V-1-1(KA)6-1994

Dated Lucknow, March 23, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatyon, Anusuchit Jan-Jatiyon Aur Anya Pichhre Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 22, 1994.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT, 1994

(U.P. Act No. 4 of 1994)

(As passed by the U.P. Legislative Assembly)

An

ACT

to provide for the reservation in public services and posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classe of citizens and for matters connected therewith or incidenta thereto.

It is hereby enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Prades Public Services (Reservation for Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993.

2. In this Act,— **Definitions**

(a) appointing authority in relation to public services and posts means the authority empowerd to make appointment to such services or posts ;

(b) other backward classes of citizens means the backward classes of citizens specified in Schedule I;

(c) Public Services and posts means the services and posts in connection with the affairs of the State and includes services and posts in —

(i) a local authority ;

(ii) a co-operative society as defined in clause (f) of Section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 in which not less than fifty-one per cent of the share capital of the society is held by the State Government ;

(iii) a Board or a Corporation or a statutory body established by or under a central or a Uttar Pradesh Act which is owned and controlled by the State Government, or a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty-one per cent of the paid up share capital is held by the State Government;

(iv) an educational institution owned and controlled by the State Government or which receives grants -in- aid from the State Government, including a university established by or under a Uttar Pradesh Act, except an institution established and administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution;

(v) respect of which reservation was applicable by Government orders on the date of the commencement of this Act and which are not covered under sub-clauses (i) to (iv) ;

(d) year of recruitment in relation to a vacancy means a priod of twelve months commencing on the first of July of a year within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated.

Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.

3. (1) In public services and posts, there shall be reserved at the stage of direct recruitment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made in accordance with the roster referred to in sub-section (5) in favour of the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes of citizens,—

(a) in the case of Scheduled Castes : twenty one per-cent

(b) in the case of Scheduled Tribes : two per cent :

(c) in the case of other Backward classes of citizens : twenty-seven per -cent

Provided that the reservation under clause (c) shall not apply to the category of other Backward classes of citizens specified in Schedule II.

(2) If, even in respect of any year of recruitment, any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, special recruitment shall be made for such number of times, not exceeding three, as may be considered necessary to fill such vacancy from amongst the persons belonging to that category.

(3) If, in the third such recruitment referred to in sub-section (2), suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.

(4) Where, due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special recruitment referred to in sub-section (2), it may be carried over to the next year commencing from first of July, in which recruitment is to be made, subject to the condition that in that year total reservation of vacancies for all categories of persons mentioned in sub-section (1) shall not exceed fifty per cent of the total vacancies.

(5) The State Government shall, for applying the reservation under sub-section (1), by a notified order, issue a roster which shall be continuously applied till it is exhausted.

(6) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

(7) If, on the date of commencement of this Act, reservation was in force under Government Orders for appointment to posts to be filled by promotion, such Government Orders shall continue to be applicable till they are modified or revoked.

Responsibility and powers for compliance of the Act

4. (1) The State Government may, by notified order, entrust the appointing authority or any officer or employee with the responsibility of ensuring the compliance of the provisions of this Act.

(2) The State Government may, in the like manner, invest the appointing authority or officer or employee referred to in sub-section (1) with such powers or authority as may be necessary for effectively discharging the responsibility entrusted to him under sub-section (1).

Penalty

5. (1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of Section 4 who wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of Section 262, Section 263, Section 264 and Section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

6. If it comes to the notice of the State Government, that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) of Section 3 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders in this behalf by appointing authority, it may call for such records and take such action as it may consider necessary.

Power to call for record

7. The State Government may, by order, provide for nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other Backward classes of citizens in the Selection Committee to such extent and in such manner as it may consider necessary where such Committee is constituted either under the service rules or otherwise.

Representation in Selection Committee

8. (1) The State Government may, in favour of the categories of persons mentioned in sub-section (1) of Section 3, by order, grant such concessions in respect of fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age-limit, as it may consider necessary.

Concession and relaxation

(2) The Government orders in force on the date of the commencement of this Act, in respect of concessions and relaxations, including concession in fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age-limit and those relating to reservation in direct recruitment and promotion, in favour of categories of persons referred to in sub-section (1), which are not inconsistent with the provisions of this Act, shall continue to be applicable till they are modified or revoked, as the case may be.

9. For the purposes of reservation provided under this Act, caste certificate shall be issued by such authority

Caste certificate

or officer and in such manner and form as the State Government may, by order provide.

Removal of difficulties

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Protection of section taken in good faith

11. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Power to make rules

12. The State Government may, by notification, makes rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to amend the Schedules

13. The State Government may, by notification, amend the Schedules and upon the publication of such notification in the *Gazette*, the Schedules shall be deemed to be amended accordingly.

Laying of Order etc.

14. Every order made under sub-section (5) of section 3, sub-sections (1) and (2) of Section 4 and Section 10 and every notification issued under Section 13 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Savings

15. (1) The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of this Act and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of law and Government Orders as they stood before such commencement.

Explanation : For the purposes of this sub-section the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of—

(i) written test or interview only, the written test or the interview, as the case may be, has started, or

(ii) both written test and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not apply to the appoimtment, to be made under the Uttar Pradesh Recruiitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974.

16. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989, (U.P. Act No. 21 of 1989) the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act, 1993 (U.P. Act No. 3 of 1993) and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes) Ordinance, 1994 (U.P. Ordinance No. 5 of 1994) are hereby repealed. **Repeal savings**

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Acts and the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Schedule - I

[See Section 2(6)]

1. Ahir
2. Arakh
3. Kachchi
4. Kahar
5. Kewat or Mallah
6. Kisan
7. Koeri
8. Kumhar
9. Kurmi
10. Kamboj
11. Kasgar
12. Kunjra or Raeen
13. Gosain
14. Gujar
15. Gadariya
16. Gaddi
17. Giri
18. Chilwa (Qassab)
19. Chhippi
20. Jogi
21. Dhafali
22. Jhoja
23. Tamoli
24. Teli
25. Darzi
26. Dhiver
27. Naqqal
28. Nat (Those not included in Scheduled Castes category)
29. Naik
30. Faqir
31. Banjara
32. Barhai
33. Bari
34. Beragi
35. Bind
36. Biyar
37. Bhar
38. Bhurji or Bharbhunja
39. Bhathiara
40. Mali, Saini
41. Manihar
42. Murao or Murai
43. Momin (Ansar)
44. Mirasi
45. Muslim Kayastha
46. Naddaf (Dhuniya), Mansoori
47. Marchcha
48. Rangrez
49. Lodh, Lodha, Lodhi, Lot, Lodhi-Rajput
50. Lohar
51. Lonia
52. Sonar
53. Sweeper (Those not included in Scheduled (Castes category).
54. Halwai.
55. Hajjam (Nai

Schedule - II

[*See* Section 3 (b)]

1. Son or daughter of—

(a) a member of Indian Administrative Services Indian Foreign Service, Indian Police Service, Indian Forest Service or other Central Service whether directly recruited or promoted from any State Service; or

(b) a member of Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch), Uttar Pradesh Police Service or other State Service, who has been directly recruited to such Service; or

(c) such Group A/Class I officer of any Department or Ministry of Government of India or educational, research or other institutions under such Department or Ministry, who is not included in sub-category (a) ; or

(d) such Group A/Class I officer of any Department or institution of the State Government, who is not included in sub-category (b) ; or

(e) an officer of the defence forces or para-military forces who is not below the rank of a Colonel or equivalent rank :

Provided that the income from salary of such member or service or officer is Rupees ten thousand or morre per mensum, his spouse is at least a graduate and he or hiis spouse owns a hosue in an urban area.

2. Son or daughter of a person engaged in profession as a doctor, surgeon, engineer, lawyer, architect, Chartered Accountant, media and information professional, management and other consultant, film artist and other film professional, running educational institution or coaching institute or engaged in the business as share or stock-broker or in entertainment business :

Provided that his average income from all sources for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth atleast rupees twenty lakh.

3. Son or daughter of a business man whose average income for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth atleast rupees twenty lakh.

4. Son or daughter of industrialist whose level of investment in running units is over rupees ten crore and such units are engaged in commercial productlon for atleast five years and his spouse is atleast a graduate.

5. Son or daughter of a person who has holding within the limit fixed under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, has an income of rupees ten lakh in a financial year from sources other than agriculture such as salary, business or industry and the like and his spouse is atleast a graduate.

6. Son or daughter of a person, not included in any of the aforementioned categories, whose average income from all sources for three consecutive financial years is not less than rupees ten lakh per annum, his spouse is atleast a graduate and his family owns immovable property worth at least rupees twenty lakh.

अर्धशासकीय पत्र संख्या–1335 / चालीस 1–94–13 (46)–94

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–1

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ, दिनांक 17 मई, 1994

प्रिय म्महोदय,

लोक सेवाओं में आरक्षण सुनिश्चित किये जाने विषयक शासना के अर्ध शा0 प0 सं0–1167 / चालीस–1–94–13(46) / 94, दिनांक्र 22 अप्रैल, 1994 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आरक्षण्ण की व्यवस्था के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा अलग से शासनाादेश संख्या 1 / 1 / 94–कार्मिक–1–94, दिनांक 29 मार्च, 1994 जारी किया गया है। जिसके साथ आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिये रोस्टर विषयक अधिसूचना संख्या 481 / का0 1–94-–1 / 1 / 94, दिनांक 29 मार्च, 1994 संलग्न की गयी है।

2. शासन स्तर पर इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि 5 या उससे कम रिक्तियों पर रोस्टर प्रणाली के स्पष्ट प्राविधानों के बाव्जूद आरक्षण की व्यवस्थाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 100 बिन्दु वाले रोस्टर (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसाार पहली रिक्ति अनुसूचित जाति, दूसरी अनारक्षित, तीसरी अन्य पिछड़े वर्ग, चतुर्थ अनारक्षित तथा पांचवीं अनुसूचित जाति के लिये चिन्हित्त की गयी है। इसी प्रकार प्रत्येक रिक्ति को रोस्टर के मुताबिक भरा ज्जाता है। अनुसूचित जन जाति के लिये 47वीं एवं 97वीं रिक्ति आरक्षित होगी। यदि रोस्टर प्रणाली पर आधारित किसी रिक्ति विशेष के लिये चयनित अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाता है या योगदान नहीं दे पात्ता है तो अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विशेष चयन कर उस रिक्ति को अनिवार्यता उसी श्रेणी के अभ्यर्थी से भरना सुनिश्चित किया जाय। रोस्टर प्रणाली एक अनवरत चयन प्रक्रिया है, जिसकी शून्य तिथि 11 दिसम्बर, 1993 है। अतएव 5 से कम रिक्तियों पर आरक्षण्ण लागू न होने का प्रश्न अब महत्वहीन हो गया है।

3. शासन के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि कतिपय विभागों में अस्थायी, सीजनल, सामाजिक या कार्य विशेष के लिये

जहां पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अभ्यर्थियों की सेवा का अवसर दिया जाता है ऐसे अवसरों पर प्रायः आरक्षित वर्ग को अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। राजस्व एवं सहकारिता में सीजनल अमीनों की तैनाती में, निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन कार्य हेतु, गन्ना विभाग एवं चीनी मिलों में गन्ने की पिराई के दौरान, खाद्य तथा रसद तथा क्रय एजेन्सियों में गेहूं एवं धान की खरीद के समय रखे जाने वाले स्टाक में, गर्मियों के दिनों में विभिन्न विभागों में "वाटर मैन" के अस्थायी पदों आदि पर सीजनल तैनातियां प्रायः की जाती हैं। शासन की यह अपेक्षा है कि ऐसे अस्थायी व सामयिक आदि पदों पर भी रोस्टर प्रणाली पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्यता लागू की जाय।

4. शासन ने आरक्षण के अनुपालन की स्थिति पर गम्भीर रूख अपनाया है। सभी नियुक्ति प्राधिकारीगण का ध्यान आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 4 व 5 तथा उक्त धारा–4 के तहत जारी अधिसूचना संख्या–482/का–1/94–1–1–1994, दिनांक 29 मार्च, 1994 जिसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को आरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, की ओर भी आकर्षित किये जाने की आवश्यकता है। जिसमें दण्ड का प्राविधान है। लागू कार्मिक नीति के अनुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्रदान करते समय कमजोर वर्गो के प्रति सामान्य दृष्टिकोण तथा आरक्षण की व्यवस्था आदि के संबंध में संबंधित अधिकारी/कार्मिक द्वारा इन वर्गो को न्याय दिलाने हेतु उनके द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख किये जाने की व्यवस्था भी है।

5. अतएव मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि दिनांक 11 दिसम्बर, 1993 की तिथि जबसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण की व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया गया है। उक्त संदर्भ तिथि से प्रत्येक कार्यालय में एक चयन/नियुक्ति रजिस्टर अलग से बना लिया जाय जिसमें समय–समय पर होने वाले चयन/तैनातियों के संबंध में स्पष्ट विवरण रखे जायें। ऐसे रजिस्टर में रोस्टर प्रणाली के 100 बिन्दुओं का शासनादेश भी चस्पा कर लिया जाय। तद्नुसार 11 दिसम्बर, 1993 के बाद जो भी

चयन/तैनातियां हुई हैं उन सभी अभ्यर्थियों के क्रमवार नामों का उल्लेख किया जाय। सामयिक आदि रिक्तियों के लिये भी अलग से इसी प्रकार रजिस्टर बना लिया जाय। प्रत्येक माह पर्याप्त समय देकर मासिक बैठकों में आरक्षण अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाय एवं शासन को नियमित रूप से कृत कार्यवाही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।

अनुरोध है कृपया तद्नुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग – 1

संख्या 481/का–1–94–1–1–1994

लखनऊ, दिनांक 29 मार्च, 1994

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके। राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिये निम्नलिखित रोस्टर जारी करते हैं :–

1. अनुसूचित जाति
2. अनारक्षित
3. अन्य पिछड़ा वर्ग
4. अनारक्षित
5. अनुसूचित जाति
6. अनारक्षित
7. अन्य पिछड़ा वर्ग
8. अनारक्षित
9. अन्य पिछड़ा वर्ग
10. अनारक्षित
11. अनुसूचित जाति
12. अनारक्षित
13. अन्य पिछड़ा वर्ग
14. अनारक्षित
15. अनुसूचित जाति
16. अनारक्षित
17. अन्य पिछड़ा वर्ग
18. अनारक्षित
19. अन्य पिछड़ा वर्ग
20. अनारक्षित
21. अनुसूचित जाति
22. अनारक्षित
23. अन्य पिछड़ा वर्ग
24. अनारक्षित
25. अनुसूचित जाति
26. अनारक्षित
27. अन्य पिछड़ा वर्ग
28. अनारक्षित

29.. अन्य पिछड़ा वर्ग

30.. अनारक्षित

31.. अनुसूचित जाति

32.. अनारक्षित

33.. अन्य पिछड़ा वर्ग

34.. अनारक्षित

35.. अनुसूचित जाति

36.. अनारक्षित

37. अन्य पिछड़ा वर्ग

38. अनारक्षित

39. अन्य पिछड़ा वर्ग

40. अनारक्षित

41. अनुसूचित जाति

42. अनारक्षित

43. अन्य पिछड़ा वर्ग

44. अनारक्षित

4. अनुसूचित जाति

46. अनारक्षित

47. अनुसूचित जन जाति

48. अनारक्षित

49. अनुसूचित जाति

50. अनारक्षित

51. अन्य पिछड़ा वर्ग

52. अनारक्षित

53. अनुसूचित जाति

54. अनारक्षित

55. अन्य पिछड़ा वर्ग

56. अनारक्षित

57. अन्य पिछड़ा वर्ग

58. अनारक्षित

59. अनुसूचित जाति

60. अनारक्षित

61. अन्य पिछड़ा वर्ग

62. अनारक्षित

63. अनुसूचित जाति

64. अनारक्षित

65. अन्य पिछड़ा वर्ग

66. अनारक्षित

67. अन्य पिछड़ा वर्ग

68. अनारक्षित

69. अनुसूचित जाति

70. अनारक्षित

71. अन्य पिछड़ा वर्ग

72. अनारक्षित

73. अनुसूचित जाति

74. अनारक्षित

75. अन्य पिछड़ा वर्ग

76. अनारक्षित

77. अन्य पिछड़ा वर्ग

78. अनारक्षित

79. अनुसूचित जाति

80. अनारक्षित

81. अन्य पिछड़ा वर्ग
82. अनारक्षित
83. अनुसूचित जाति
84. अनारक्षित
85. अन्य पिछड़ा वर्ग
86. अनारक्षित
87. अन्य पिछड़ा वर्ग
88. अनारक्षित
89. अनुसूचित जाति
90. अनारक्षित
91. अन्य पिछड़ा वर्ग
92. अनारक्षित
93. अनुसूचित जाति
94. अनारक्षित
95. अन्य पिछड़ा वर्ग
96. अनारक्षित
97. अनुसूचित जनजाति
98. अनारक्षित
99. अनुसूचित जाति
100. अनारक्षित